



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2013/भाद्र 11, 1935

No. 229]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2013/BHADRA 11, 1935

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 27 अगस्त, 2013

सं.टीएएमपी/41/2012-केपीटी.—महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, केपीटी के कागों प्रहस्तन प्रभाग की लेवी और अन्य प्रभारों के स्थान पर ऑन-बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर के संशोधन के लिए कांडला पत्रन न्यास (केपीटी) से प्राप्त हुए प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी

कांडला पत्रन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी.एस.बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अगस्त, 2013 के 13वें दिन पारित)

यह मामला केपीटी के कागों प्रहस्तन प्रभाग की लेवी और अन्य प्रभारों के स्थान पर ऑन-बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर के संशोधन के लिए कांडला पत्रन न्यास (केपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव से संबंधित है।

21. इस प्राधिकरण ने एक वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च 2012 तक के लिए अपने कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के अन्य प्रभारों की वसूली के स्थान पर ऑन-बोर्ड लेबर के लिए घटकलार प्रति टन समेकित दर निर्धारित करने के लिए काडला पत्तन न्यास के प्रस्ताव को अनुमतिदित करते हुए एक आदेश सं. टीएमपी/37/2007-केपीटी दिनांक 25 मार्च 2011 पारित किया था। ये प्रभार केपीटी के दसमान के अध्याय III में खंड 3 के रूप में शामिल किए गए थे; उक्त आदेश में, केपीटी को 1 अप्रैल 2012 से लागू की जाने वाली दरों के लिए 31 दिसम्बर 2011 तक सुविश्लेषित प्रस्ताव जमा करने की सलाह दी गई थी।

22. इस संबंध में, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 मार्च 2012 द्वारा निवेदन किया था कि ऑन-बोर्ड लेबर के लिए प्रति टन दर के संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले सर्वसम्मति बनाने के लिए ट्रेड के साथ केपीटी के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के ऑन-बोर्ड लेबर के लिए संशोधित प्रति टन दर के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। इसलिए, केपीटी ने अगले तीन महीनों की अवधि अर्थात् 30 जून 2012 तक के लिए अस्थाई तौर पर मौजूदा दर वसूल करना जारी रखने के लिए पत्तन को अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध था और निवेदन किया था कि 1 अप्रैल 2012 से पूर्वव्यापी प्रभाव से दर के संशोधन हेतु प्रस्ताव यूनिटों/ट्रेड एवं बोर्ड के साथ चर्चा के बाद जमा किया जाएगा।

23. केपीटी के अनुरोध पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/37/2007-केपीटी दिनांक 9 अप्रैल 2012 द्वारा इस शर्त के अधीन 31 मार्च 2012 से 30 जून 2012 तक ऑन-बोर्ड लेबर के लिए दरों की वैधता को विस्तारित किया था कि कैमता की विस्तारित अवधि के दौरान केपीटी को यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उपार्जित होता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क से पूर्णतः समाप्तोजित किया जाएगा, और केपीटी को ऑन-बोर्ड लेबर के निर्धारण हेतु प्रस्ताव 30 अप्रैल 2012 तक दाखिल करने की सलाह दी गई थी। 1 अप्रैल 2012 से प्रशुल्क के पूर्वव्यापी संशोधन के संबंध में, जैसाकि केपीटी द्वारा सुझाव दिया गया है, इस प्राधिकरण ने निर्णय दिया था कि पत्तन द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर शुरू की जाने वाली कार्यताहियों में, केपीटी द्वारा प्रेषित किए जाने वाले औचित्यों के आधार पर, इस पर विचार किया जा सकता है।

24. तत्पश्चात्, केपीटी के अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने मौजूदा दरों की वैधता आदेश दिनांक 8 अगस्त 2012 द्वारा 31 अक्टूबर 2012 तक आगे विस्तारित की थी और बाद से आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2012 द्वारा 28 फरवरी 2013 तक विस्तारित की गई थी। प्रदत्त विस्तार इस शर्त के अधीन थे कि 31 मार्च 2012 के बाद केपीटी को उपार्जित होने वाले अतिरिक्त अधिशेष र्थादि कोई हो, के समायोजन के अधीन होंगे।

31. इस परिप्रेक्ष्य में, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 6 जून 2012 और 29 जून 2012 के कवर के अधीन पत्तन के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के लेवी तथा अन्य प्रभारों के स्थान पर ऑन-बोर्ड लेबर के लिए प्रति टन दर के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव जमा किया है। केपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है—

- (i). यारतविक आध, लागत, प्रहस्तित यातायात और 1 अप्रैल 2012 से 30 जून 2012 तक की अवधि के लिए अपूर्ति किए गए कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के ऑन-बोर्ड लेबर के गैंग पर विचार करते हुए दरों का प्रस्ताव किया गया है।
- (ii). आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 में, इस प्राधिकरण ने केपीटी को मैनिंग मान लागू करने का निदेश दिया था। इस संबंध में, यह सूचित किया गया है कि मैनिंग मान का प्रथम चरण 22 अप्रैल 2012 से लागू किया गया है। मैनिंग मान के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, गैंग संख्या में कटौती की गई है और एक वर्ष में 17 बन्द अवकाश दिवसों के मामले में ओवरटाइम के सिवाय ओवरटाइम व्यय शून्य माना गया है।
- (iii). बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत, 01-06-2011 से 30-11-2011 तक छह महीने की अवधि के दौरान राशि ₹0.125 करोड़ + 0.78 करोड़ (ओवर टाइम राशि का 50 प्रतिशत 5 वर्षों में बाटा जाएगा) को ओवर टाइम लागत के अलावा आय से अधिक व्यय मौजूदा संशोधन प्रस्ताव में विचार किया जाया है और अवर टाइम राशि का शेष 50 प्रतिशत दरमान के सामान्य संशोधन में सुविचारित किया जाएगा।
- (iv). प्रस्ताव में, 01-01-2012 से देव आगामी मजदूरी संशोधन के कारण देवन नश्वर मजदूरी लागत में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
- (v). 2.5 प्रतिशत की औसत तिमाही वृद्धि पर विचार करते हुए परिवर्तीय डीए (टीडीए) में 10 प्रतिशत की अनुमतित वृद्धि पर भी विचार किया गया है। टीडीए कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के प्रथमान्तर व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए, दरों को तिमाही आधार पर संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है अन्यथा पत्तन की तरह तक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जब तक टीडीए वृद्धि को दरों में नहीं दर्शाया जाता है।
- (vi). उत्पादकता को स्थीकार करने के लिए, केपीटी ने प्रति गैंग लागत पर पहुंचने के लिए आपूर्ति किए गए गैंगों की वारतविक संख्या से विभाजित किए जाने वाले स्टीवडोर द्वारा प्रहस्तित बास्टिल मात्रा के लिए राजस्व का प्रस्ताव किया गया है और इसकी राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग से तुलना की है। यद्यपि राजस्व प्रति गैंग अधिकतम

राजस्व अपेक्षा प्रति गंग से अधिक रहता है तो अधिसेप स्टीवंडोर को वापिस किया जाएगा और यदि कमी रहती है तो स्टीवंडोर से उत्तरी खस्ती भी पाएगी। यह कार्यपद्धति न केवल उत्पादकता को मान्यता देगी अपितु स्टीवंडोरों तथा प्रयालन स्टाफ द्वारा समझना और कार्यान्वयित करना बहुत आसान हो जाएगा।

(vii). टीएमपी को प्रस्ताव भेजने से पहले 9 मई 2012 को संबद्ध उपयोक्ता संगठनों के साथ उनकी सहमति/टिप्पणियाँ/सुझावों के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के कार्यवृत्तों की प्रति से, यह देखा गया है कि स्टीवंडोरिंग असोसिएशनों के सभी सदस्यों ने प्रस्ताव मुख्यतः इसके समय और प्रस्तावित दरों पर ओवरटाइम के भुगतान की वजह से राजस्व में कमी के बोझ का विरोध किया था। तथापि, यह भी निर्णय लिया गया है कि केपीटी अपना प्रस्ताव टीएमपी को जमा करेगा और तब उपयोक्ता असोसिएशन अपने विचार टीएमपी को सीधे भेजेंगे, जब टीएमपी केपीटी के प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणियाँ मांगेगा।

इसके प्रस्ताव दिनांक 6 जून 2012 में मौजूदा प्रति टन दर और केपीटी द्वारा प्रस्तावित दर को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

क्र. सं.	कार्गो नंदे	मौजूदा दरें (प्रति टन)				प्रस्तावित दरें (प्रति टन)			
		बल्क	ब्रेक बल्क	बल्क	ब्रेक बल्क	विदेशी रु	तटीय रु	विदेशी रु	तटीय रु
1	उर्वरक / उर्वरक कच्चा माल	13.96	8.37	42.92	25.75	20.80	12.48	111.03	66.62
2	चावल और अन्य खाद्याल	21.62	12.97	27.23	16.34	29.71	17.83	49.44	29.66
3	सीमेट	-	-	21.05	12.63	-	-	-	-
4	स्टील कोइल और स्टील पाइप	-	-	17.55	10.53	-	-	28.34	17
5	टिक्कर तथा अन्य लट्ठे	-	-	38.64	23.18	-	-	48.22	28.93
6	सोडा एश	-	-	60.89	36.54	-	-	-	-
7	मशीनरी पैकेज और अन्य पैकेज	-	-	72.84	43.71	-	-	117.78	70.67
8	लौह अयस्क	11.14	11.14	-	-	22.59	22.59	-	-
9	लौह अयस्क से इतर अयस्क	12.20	7.32	-	-	17.57	10.54	-	-
10	कबाड	20.45	12.27	-	-	31.99	19.19	-	-
11	तेल एक्स्ट्रेक्शन्स	18.95	11.37	-	-	24.47	14.88	-	-
12	ताप कोयला	10.39	10.39	-	-	27.33	27.33	-	-
13	अन्य कोयला	9.11	5.46	-	-	12.97	7.78	-	-
14	ननक	11.12	6.67	32.59	19.55	12.12	7.27	23.43	14.09
15	चीनी	17.42	10.45	25.80	15.48	38.08	21.65	44.34	26.60
16	सभी अन्य अविनियित सामान	10.85	6.51	36.26	21.75	19.41	11.65	50.76	30.47

3.3 तत्पश्यत, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई 2012 द्वारा निवेदन किया है कि 30 जून 2012 को हुई बोर्ड की बैठक में कार्यवृत्तों की पुष्टि किए जाने के समय, न्यासियों ने पाया था कि संशोधन के लिए सुविधारित रु 3.91 लरेड के ओवरटाइम तत्पर के समय में विपर्यन था। पतन ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड ने रु 3.00 करोड़ का ओवरटाइम पांच बर्षों की अवधि में खस्ती किए जाने और शेषराशि अपने दरमान के सामान्य संशोधन में समायोजित किए जाने को निर्णय लिया था। इस टिप्पणी के बद्दलेनजर, केपीटी ने रु 3.00 करोड़ की सीमा तक ओवर टाइम राशि (5 वर्षों में विभाजित) पर विचार करते हुए संशोधन प्रस्ताव दाखिल किया था। केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई 2012 के कवर के अधीन संशोधित गणना भेजी थी। केपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई 2012 में प्रस्तावित संशोधित प्रति टन दरों के सापेक्ष सीएचडी से ऑन-बोर्ड लेबर की तैनाती के लिए मौजूदा दरें नीचे तालिकाबद्द की गई हैं:-

क्र. सं.	कार्गो नंदे	प्रस्तावित दरें (प्रस्ताव दिनांक 6 जून 2012 के अनुसार)				प्रस्तावित दरें (प्रस्ताव दिनांक 2 जुलाई 2012 के अनुसार)			
		बल्क	ब्रेक बल्क	बल्क	ब्रेक बल्क	विदेशी रु	तटीय रु	विदेशी रु	तटीय रु
1	उर्वरक / उर्वरक कच्चा माल	20.80	12.48	111.03	66.62	20.68	12.41	110.37	66.22
2	लग्न और अन्य खाद्याल	29.71	17.83	49.44	29.66	29.53	17.72	49.14	29.48
3	सीमेट	-	-	-	-	-	-	-	-
4	स्टील कोइल और स्टील पाइप	-	-	28.34	17.00	-	-	28.17	18.90
5	टिक्कर तथा अन्य लट्ठे	-	-	48.22	28.93	-	-	47.93	28.76
6	सोडा एश	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मशीनरी पैकेज और अन्य पैकेज	-	-	117.78	70.67	-	-	117.08	70.25
8	लौह अयस्क	22.59	22.59	-	-	22.59	22.59	-	-
9	लौह अयस्क से इतर अयस्क	17.57	10.54	-	-	17.46	10.48	-	-
10	कबाड	31.99	19.19	-	-	31.80	19.08	-	-
11	तेल एक्स्ट्रेक्शन्स	24.47	14.68	-	-	24.32	14.59	-	-
12	ताप कोयला	27.33	27.33	-	-	27.33	27.33	-	-
13	अन्य कोयला	12.97	7.78	-	-	12.89	7.73	-	-

14	नमक	12.12	7.27	23.48	14.09	12.05	7.23	23.34	14.00
15	चीज़ी	36.08	21.85	44.34	26.60	35.87	21.52	44.08	26.45
16	सभी अन्य अविनिर्दिष्ट सामग्री	19.41	11.65	50.78	30.47	19.30	11.58	50.48	30.29

4. निर्धारित प्रसारण प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्ताव दिनांक 6 जून 2012 और संशोधित प्रस्ताव दिनांक 2 जुलाई 2012 उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त हुई टिप्पणियां केपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 7 नवम्बर 2012 द्वारा प्रत्युत्तर दिया था।

5. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, केपीटी से हमारे पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2012 द्वारा रिभिन्न बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2012 द्वारा हमारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया था। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों और केपीटी के प्रत्युत्तर नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:-

क्र. सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	केपीटी से प्राप्त प्रत्युत्तर
(i).	इस आधार पर कि परिवर्तनीय डीए (वीडीए) कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के प्रवालन व्यय से 10 प्रतिशत अधिक है और दरों में वीडीए वृद्धि दर्शाने के लिए, केपीटी ने अपने प्रस्ताव में प्रस्तावित किया है कि दरे तिमाही आधार पर संशोधित की जाएंगी। इस संबंध में, यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 3.18 3 वर्षों की प्रशुल्क वैधता अवधि निर्धारित करता है। इसके अलावा, यह याद करना होगा कि मार्च 2011 के प्रशुल्क आदेश में, यह दर्शाया गया है कि दरे सामान्यतः तीन वर्षों के लिए अनुमोदित किए जाते हैं और आदेश में उल्लिखित कारणों से ही, इसे केपीटी के मामले में 31 मार्च 2012 तक की वैधता के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। उपर्युक्त स्थिति के मददेनजर, केपीटी से अनुरोध है कि प्रति टन ऑन-बोर्ड लेबर लेवी निर्धारित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में अप्रैल 2012 से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभाग से संबंधित लागत विवरण भेजे। 3 वर्षों की अवधि के लिए अपने लागत विवरण तैयार करने के लिए केपीटी द्वारा विश्वास किए गए संशोधित अनुमान/बजट अनुमान भी भेजें।	(क). दशकों से, दंश में डॉक लेबर बोर्ड वीडीए दरों में वृद्धि/कटौती करने के लिए लेवी में संशोधन प्रत्येक तिमाही में करते रहे थे और स्टीवडोर उसका भुगतान करते रहे थे। ऐसा करते हुए लेबर की आर्हति के लिए प्रभार संदेव वास्तविक लागतों के करीब थे। वास्तव में, वीडीए दरों में ट्रैमासिक वृद्धि/कटौती जब कार्यान्वयित की गई थी तो इससे भुगतान से महीने से पहले के तीन महीनों के दौरान प्रचलित औसत महंगाई पर पहले से आधारित है। उदाहरणार्थ, अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 तिमाही के लिए वीडीए दरों में प्रतिशत वृद्धि या कटौती जून 2012-अगस्त 2012 के महीनों के लिए ऐतिहासिक डाटा पर आधारित है। वीडीए की वजह से लागत वृद्धि जो सीधे तौर पर उपयोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक डीए प्लाइट्स) पर आधारित है जो सही अनुमानन के लिए उपयुक्त नहीं है। वीडीए दर में बदलाव लगभग हमेशा अधिक रहा है।

		<p>इसलिए, यह महसूस किया गया है कि कार्यों प्रहस्तन लेबर की आपूर्ति के लिए दरे प्रत्येक तीन महीने अथवा प्रत्येक छह महीने आधार पर संशोधित की जाएं।</p> <p>वर्ष 2011-12 के लिए सीएचडी से संबंधित वास्तविक आय तथा लागत दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है। विवरण में लिए गए आंकड़े वार्षिक लेखों के अनुसार हैं; इसलिए मिलान विवरण अपेक्षित नहीं है।</p> <p><u>वर्ष 2011-12 के लिए सीएचडी से संबंधित वास्तविक आय तथा लागत:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th><th>रु0 लाखों में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आय</td><td>4023.77</td></tr> <tr> <td>व्यय</td><td></td></tr> <tr> <td>वेतन तथा मजदूरियाँ</td><td>5491.66</td></tr> <tr> <td>भंडार</td><td>6.98</td></tr> <tr> <td>कायालय तथा प्रशासन व्यय</td><td>2.82</td></tr> <tr> <td>प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय</td><td>0.86</td></tr> <tr> <td>चिकित्सा व्यय</td><td>49.10</td></tr> <tr> <td>मूल्यांकन</td><td>9.05</td></tr> <tr> <td>पैशान उपदान तथा कम्प्यूटरशनर</td><td>1012.00</td></tr> <tr> <td>नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ @ 16%</td><td>44.07</td></tr> <tr> <td>घाटा</td><td>-2592.78</td></tr> </tbody> </table>	विवरण	रु0 लाखों में	आय	4023.77	व्यय		वेतन तथा मजदूरियाँ	5491.66	भंडार	6.98	कायालय तथा प्रशासन व्यय	2.82	प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय	0.86	चिकित्सा व्यय	49.10	मूल्यांकन	9.05	पैशान उपदान तथा कम्प्यूटरशनर	1012.00	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ @ 16%	44.07	घाटा	-2592.78
विवरण	रु0 लाखों में																									
आय	4023.77																									
व्यय																										
वेतन तथा मजदूरियाँ	5491.66																									
भंडार	6.98																									
कायालय तथा प्रशासन व्यय	2.82																									
प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय	0.86																									
चिकित्सा व्यय	49.10																									
मूल्यांकन	9.05																									
पैशान उपदान तथा कम्प्यूटरशनर	1012.00																									
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ @ 16%	44.07																									
घाटा	-2592.78																									
(ii).	<p>केपीटी से यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2011-12 के लिए कार्यों प्रहस्तन प्रभाग से संबंधित वास्तविक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में भेजे। वास्तविक आंकड़े दर्शाने के लिए केपीटी द्वारा विश्वास किए गए वार्षिक लेखें भी वार्षिक लेखों तथा लागत विवरणों में आंकड़ों के बीच भिन्नताओं, यदि कोई हो, के मिलान के लिए मिलान विवरण के साथ भेजे।</p>																									
(iii).	<p>मार्च 2011 के आदेश के पैरा 13(vii)(ख) में यथा उल्लिखित, केपीटी को मैनिंग मानों तथा डेटम के संबंधित के लिए अधिकरण निर्णय कार्यान्वयित करने से संबंधित कदम उठाने की सलाह दी गई है। केपीटी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि मैनिंग मान का घरण 1 22 अप्रैल 2012 से कार्यान्वयित किया गया गई है, जिसके परिणामस्वरूप गैंग संख्या कम हुई है। इस संबंध में, केपीटी से निम्नलिखित स्पष्ट करने/प्रेषित करने का अनुरोध है—</p> <p>(क). मैनिंग मानों के कार्यान्वयन के कारण गैंग संख्या में कटौती की सीमा भेजी गई है जिसे अर्जित मैनपावर में कटौती सहित मैनिंग मानों के घरण 1 के कार्यान्वयन के प्रभाव के साथ भेजें। अधिकरण के निर्णय को कार्यान्वयित किए जाने से पहले और कार्यान्वयित किए जाने के बाद प्राप्त करने के लिए बल्कि में नमक के लिए मैनिंग मान और कई प्रकार के कार्यों (सिवाय बल्कि में नमक) पर ध्यान दिए बिना प्रति हुक ऑन-बोर्ड कामगारों के संदर्भ में मैनिंग मान की तुलनात्मक स्थिति भी भेजी जाए।</p>	<p>(क). यह महसूस किया गया है कि मैनिंग मान का कार्यान्वयन एक नीति निर्णय है और पत्तन के कार्य पर इसका प्रभाव पहुँच रहा है तथा ट्रेड यूनियनों के साथ बास-बार बातचीत किए जाने की आवश्यकता है तथा इस दिशा में लिया गया कोई भी गलत निर्णय पत्तन की सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है।</p> <p>(ख). पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पत्तन क्षेत्र हेतु कार्य समूह की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 11.6.2.1 में स्वीकार करता है कि निर्णय अभी कुछ पत्तनों द्वारा कार्यान्वयित किया जाना है। (केपीटी ने पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पत्तन क्षेत्र हेतु कार्य समूह की रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से की प्रति भेजी है।) इस प्रकार, पोत परिवहन मंत्रालय इस मामले को पहले ही निपटा चुका है। मैनिंग मानों को कार्यान्वयित किए जाने की सीमा संबंधी निर्णय, कार्यान्वयन के घरण पत्तन प्रबंधन पर छोड़ देने चाहिए और इसे प्रशुल्क निर्धारण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।</p> <p>(ग). वास्तव में, मैनिंग मान के पूर्ण कार्यान्वयन से अधिकांश कामगार अधिशेष हो जाएंगे। उनके पुनर्रोजगार या विशेष स्वैच्छिक सेवानिकृति योजनाओं अथवा उनके पुनर्प्रशिक्षण की सही योजना तैयार किए बिना, मैनिंग मानों के 100 प्रतिशत कार्यान्वयन से पत्तन में विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और पत्तन क्षेत्र में भारी औद्योगिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी।</p> <p>उनकी प्रतिबद्ध वेतनों तथा मजदूरियों की लागत को कौन वहन करेगा यह प्रश्न भी संबोधित किया जाना है। पत्तन उपयोक्ताओं से उसकी वसूली किए बिना मजदूरी बोर्ड निपटान के अनुसार वेतनों</p>																								

मजदूरियों, भत्ता तथा सेवानिवृत्ति लाभों की अदायगी करने की उम्मीद नहीं कर सकता।

(घ). केपीटी ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए वास्तविक डाटा के आधार पर मैनिंग मान के कार्यान्वयन का प्रभाव दर्शाने वाला विवरण भेजा है। विवरण से यह देखा गया है कि आरपी कामगार की 82358 आदमी पालियां और टिप्पडल की 1830 आदमी-पालियां अधिशेष रही हैं। आरपी कामगार की उपलब्ध आदमी-पालियों में 85 प्रतिशत और टिप्पडल की उपलब्ध आदमी पालियों का 21 प्रतिशत की राशियां हैं।

(ङ). इसलिए, इस भारी अधिशेष मैनपावर की रिट्रैचमेंट अधिक पुर्णतानाती में से किसी किसी एक के बारे में निर्णय लिए जाने तक केपीटी को उनके बेतनों तथा मजदूरियों की वसूली स्टीदडारों से करनी होगी और यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उनके बेतनों तथा मजदूरियों को उसकी आरक्षित निधियों से पूँजी किया जाए।

(च). इसके अलावा, ये कामगार अधानक नहीं हटाए जा सकते क्योंकि ट्रेड यूनियनें ऐसे कदम का भारी विरोध करेगी। इसलिए यह महसूस किया गया है कि टीएमपी अपने को इस नीति कार्यान्वयन से नहीं जोड़ना चाहिए और इस स्थानीय पत्तन प्रबंधन पर छोड़ देना चाहिए।

(छ). अधिकरण के निर्णय को कार्यान्वयित किए जाने से पहले आरपी कार्यान्वयित किए जाने के बाद प्राप्त करने के लिए दल्क वे नमक के लिए मैनिंग मान और कई प्रकार के कार्गो (सेवायां बल्कि में नमक) पर ध्यान दिए विना प्रति हुक ऑन-बोर्ड कामगारों के संदर्भ में मैनिंग मान की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है-

कार्गो के प्रकार	मैनिंग मानों पर अधिकरण निर्णय का कार्यान्वयित किए जाने से पहले गए स्थिति			मैनिंग मानों पर अधिकरण निर्णय का कार्यान्वयन के बाद गए स्थिति		
	आरपीडब्ल्यू (प्रति हुक)	टिप्पडल (प्रति हुक)	सिनल्मेन (प्रति हुक)	आरपीडब्ल्यू (प्रति हुक)	टिप्पडल (प्रति हुक)	सिनल्मेन (प्रति हुक)
सभी कार्गो (बल्कि में नमक से इतर)	10	1	1	5	1	1
नमक बल्कि में उत्तरी कार्गो	2	1	1	2	1	1

*आरपीडब्ल्यू - पर्जीकृत पूल कामगार

(क) यह दिखाई देता है कि केपीटी न मैनिंग मानों का चरण-वार-कार्यान्वयन परिकल्पित किया है। कृपया मैनिंग मानों के चरण-वार-कार्यान्वयन पर विस्तृत नोट भेजें।

मैनिंग मानों के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में पर्जीकृत पूल कामगारों (आरपीडब्ल्यू) हालत किए गए हैं और सूक्ष्म बल्कि कार्गों पर उनकी तैनाती जारी रखी गई है। दूसरे चरण में आरपीडब्ल्यू की तैनाती यह सुनिश्चित किए जाने के मददेनजर माग/आपूर्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी कि काइ अधिशेष रैम नहीं हैं। पत्तन की रणनीति कामगारों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर विचार करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए मैनिंग मान व अनुसार धीरे-धीरे तैनाती स्तर अर्जित करना है कि मैनिंग का अधिशेष में नहीं रखा गया है जिससे औद्योगिक झड़ाति घैटा न हो जाए।

(ग) केपीटी अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन की वजह से डेटम के सशोधन के सबध में खामोश है। केपीटी से अनुरोध है कि इस सबध में भौजूदा स्थिति स्पष्ट करे।

डेटमों में अभी सशोधन नहीं किया गया है क्योंकि पत्तन में प्रदालून कर रही प्रमुख ट्रेड यूनियनों के साथ सहमति नहीं बन पाई है। इस सबध में, धैठकों की एक श्रृंखला ट्रेड यूनियनों के साथ हुई है। तथापि, ट्रेड यूनियनें इस निर्णय पर अडे हैं कि पीस दस को २५ वर्षों पहले अंतिम रूप दिया गया था और इस अवधि के दौरान मजदूरी संशोधन किए जाने के बावजूद विना किसी संशोधन के आज तक वहीं दरे चल रही है। यूनियनें इस बात पर भी ज़रूरी कि सशोधन से कामगारों को लाभ पहुँचेगा जिसके बिना काइ समाधान नहीं हो सकता है। यूकि यह बहुत ही संवेदनशील लेवर मामला है और इसे परामर्श और वातचीत के ज़रिये ही सुलझाना

		होगा ताकि पत्तन प्रचालकों को परेशानी न हो। वास्तव में, यूनियन मैनिंग मान को यह सुनिश्चित किए जाने के बाद ही आशिक रूप से कार्यान्वयन किए जाने के लिए सहमत हैं कि वर्तमान में भूगतान किए जा रहे पीस दर प्रोत्साहन सुरक्षित रखे जाएंगे। वैसे नीति निर्णय होने के नाते, यह महसूस किया गया है कि टीएमसी को अपने को इस मामले से नहीं जोड़ना चाहिए और कार्यान्वयन का मुददा स्थानीय पत्तन प्रबंधन पर छोड़ देना चाहिए। इससे कोई निवल वित्तीय विवेका भी नहीं होगी क्योंकि ट्रेड यूनियनें मौजूदा लाभों को कम किए जाने पर बिल्कुल सहमत नहीं होंगी। इस प्रकार, जहां एक ओर डैटम संशोधित किए जाएंगे, वहां दूसरी तरफ पीस दर से तटस्थ प्रभाव बढ़ेगा। यूनियनों के साथ हस्ताक्षरित मजदूरी करारों में इस बारे में एक ऐसा खंड दिया गया है कि कामगारों द्वारा मौजूदा स्तर पर उठाए जा रहे लाभों को सुरक्षित रखा जाएगा।
(iv).	मार्च 2011 के आदेश के पैरा 13(xviii) में यथा उल्लिखित, केपीटी को उक्त अनुच्छेद में यथा सूचीबद्ध विभिन्न कारकों पर विचार करने और उत्पादकता स्तरों से संबंधित अपना प्रस्ताव जमा करने की सलाह दी गई थी। इस संदर्भ में, केपीटी से अनुरोध है कि निम्नलिखित स्पष्ट/प्रेषित करें—	
	(क) हालांकि केपीटी ने पत्तन द्वारा आपूर्ति किए गए गैंग की उत्पादकता के आधार पर स्टीवडोर से/को वसूली/वापसी किए जाने का प्रस्ताव किया है, परन्तु यह इससे यह दिखाई नहीं देता है कि केपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह के अनुसार उत्पादकता से सबंधित प्रस्ताव के आधार के लिए उपर्युक्त अनुच्छेद में मार्च 2011 के आदेश में सूचीबद्ध विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा है। केपीटी से अनुरोध है कि इस संबंध में रिथ्ति स्पष्ट और समीक्षा करें।	मैनिंग मान पर राष्ट्रीय अधिकरण निर्णय के कार्यान्वयन से ओवरटाइम पर व्यय में कटौती किए जाने से लागत में भारी कटौती हुई है। विभिन्न कारों के लिए निर्धारित प्रति टन दरें मई 2011 से नवम्बर 2011 तक अवधि के दौरान तैनात किए गए वास्तविक गैंगों पर आधारित हैं और अर्जित उत्पादकता में पहले से दी गई हैं। इसके अलावा, केपीटी ने कार्गो-वार उत्पादकता संबंधित दरों का प्रस्ताव करने में मुश्किलों को अभिय्यक्त करते हुए उपर्युक्त (iv) पर हमारे प्रश्न के जवाब में अपने किए गए निवेदनों को दोहराया है।
	(ख) दरमान में शामिल किए जाने के लिए बेहतर निष्पादन हेतु प्रोत्साहन और कम निष्पादन के लिए हतोत्साहन हेतु एक मसौदा शर्त का प्रस्ताव किया है।	उपर्युक्त के मद्देनजर, कोई टिप्पणी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।
(v)	मार्च 2011 के आदेश के पैरा 13(xv) में यथा उल्लिखित, केपीटी को कुशलता में सुधार करने तथा लागतों में कमी करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई थी। इस संबंध में पत्तन द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करें और ऐसे कदमों को उठाए जाने की वजह से दिल्लीय विवेका को परिमाणित और प्रेषित करें।	मैनिंग मान पर राष्ट्रीय अधिकरण निर्णय के कार्यान्वयन से ओवरटाइम पर व्यय में कटौती किए जाने से लागत में भारी कटौती हुई है। विभिन्न कारों के लिए निर्धारित प्रति टन दरें मई 2011 से नवम्बर 2011 तक अवधि के दौरान तैनात किए गए वास्तविक गैंगों पर आधारित हैं और अर्जित उत्पादकता में पहले से दी गई हैं। कांडला में कई कार्गो बहुत मौसमी प्रवृत्ति के हैं। उदाहरणार्थ, उर्वरक आयात मई से अक्टूबर तक की अवधि के दौरान बढ़ जाता है जिसके बाद आयातों में उल्लेखनीय कटौती होती है। खाद्यान्नों तथा सोया एक्सट्रेक्शन का निर्यात जुलाई से अक्टूबर के दौरान बहुत कम रहता है। प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने के दौरान अवधि पर निम्नरक्त करते हुए, दरें बहुत ज्यादा कम-ज्यादा हुईं। विभिन्न शीर्षों में कार्गो का समूहन एक मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि कांडला में प्रहरित शुल्क कार्गो के 50 विभिन्न प्रकार हैं और उनमें से प्रत्येक के भिन्न उत्पादकता स्तर हैं। उदाहरणार्थ, हम लकड़ी के लट्ठों पर विचार करें। जब पाइन की लकड़ी के लट्ठों की उत्पादकता कम होती है तो अन्य लकड़ी के लट्ठों की उत्पादकता बढ़ जाती है। दोषारा, कांडला में हाल ही में बहुत ज्यादा पनचकियां आयात की गई हैं बहुत कम उत्पादकता हुई है क्योंकि डिस्चार्ज करने में समय लगता है जब मशीनरी की अन्य मर्दे/सीकेडी मर्दों का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक रहा है। प्रत्येक प्रकार के कार्गो के लिए उत्पादकता संबंधित दरें निर्धारित करना पत्तन उपयोक्ताओं से प्रभारों का युक्तिकरण भी पेचीदा होगा। पत्तन उपयोक्ता भी एकल दर को वरीयता देते हैं। हारवर मोबाइल फ्रेनों के लिए निर्धारित प्रशुल्क के मामले में यह अनुभव किया जा रहा है।

(vi).	<p>ऑन-बोर्ड लेबर के लिए मौजूदा प्रति टन दर के संशोधन के लिए केपीटी का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2012 से पूर्वव्यापी प्रभाव से है। इस संघ में, यह याद करना होगा कि कार्गो प्रहरतन प्रभाग की दरों की वैधता को विस्तारित करने वाले अप्रैल 2012 के आदेश के पैरा 4 में यथा उल्लिखित, यह कहा गया है कि प्रशुल्क का पूर्वव्यापी अर्थात् 1 अप्रैल 2012 से संशोधन, केपीटी द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार, केपीटी द्वारा प्रेषित किए जाने वाले औचित्यों के आधार पर पत्तन द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर शुरू की जाने वाली कार्यवाहियों में सुविचारित किए जाएंगे। केपीटी ने अपने विचाराधीन प्रस्ताव में अपने द्वारा मांग की गई प्रस्तावित दरों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने का औचित्य नहीं दिया है।</p>	<p>पूर्वव्यापी संशोधन बहुत जरूरी है अन्यथा पत्तन को भारी नुकसान होगा। यहां तक कि सीएजी ने भी इस संघ में प्रतिकूल दिप्पणी की है। वास्तव में, टीएएमपी ने 25-03-2011 को परिस एफआ आदेश सं. टीएएमपी /37/2007-केपीटी द्वारा प्रति टन प्रशुल्क अनुमोदित करते समय, इसने 25-01-2007 से 04-06-2011 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए पीस दर के साथ ₹ 0 1084/- प्रति कामगार प्रति पाली और बिना पीस दर के ₹ 0 850/- प्रति कामगार प्रति पाली की तदर्थ दर भी अनुमोदित की थी। लगभग 58 महीनों की इस अवधि के दौरान, डॉक कामगारों के वेतनों तथा मजदूरियों में भारी वृद्धि हुई है और पत्तन की प्रचालन लागत में भारी वृद्धि हुई है और इससे पत्तन को ₹ 34.12 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। सीएजी इस मुद्दे को अपनी मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट में उठा चुका है।</p>																											
(vii).	<p>केपीटी ने मजदूरी संशोधन के लिए लेखा में 20 प्रतिशत के वृद्धि कारक को अंगीकृत किए जाने के अलावा वीडीए वृद्धि के अनुमानन के लिए 10 प्रतिशत के वृद्धि कारक को अंगीकृत किया है। जबकि 1 जनवरी 2012 से देय होने वाली मजदूरी संशोधन के लेखा पर वेतन में वृद्धि को समझा जा सकता है, यह नोट किया जाए कि लागत विवरण में सभी अन्य व्यय पूर्वनुमानों का अनुमानन हमारे पत्र सं. टीएएमपी /27/2005-विविध दिनांक 11 मई 2012 द्वारा हमारे द्वारा पहले से संप्रेषित 6.50 प्रतिशत वार्षिक के वृद्धि कारक पर अधारित होगा।</p>	<p>₹ 0 850/- और ₹ 0 1084/- की दरें आमेलन जी तारीख 24-01-2007 से पहले 01-04-2006 से 31-12-2006 तक 9 महीनों की अवधि के दौरान केडीएलबी के कार्य परिणामों के अनुसार पर पूरी तरह से तदर्थ दरें थीं। इस प्रकार, नौ महीने की लागत का आधार पर दर की अदायगी करते हुए, स्टीवडोरों ने लाभ उठाया है। इसलिए, यदि दरों का पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित नहीं किया जाता है तो इससे पत्तन को भारी नुकसान होगा।</p> <p>यह दोहराया गया है कि प्रशुल्क की अन्य मदों जैसे कार्गो प्रहस्तन उपस्कर, मरीन प्रभार के लिए सुविचारित वृद्धि प्रतिशततात् योटी कामगारों के लिए प्रशुल्क निर्धारण कार्यपद्धति पर लागू नहीं हाँगी। सेवानिवृत्ति तथा इम्पाडिंग मजदूरी संशोधन के लिए दंड कार्यों प्रहस्तन कामगारों के बड़े चक के लिए ओइग वडती सेवानिवृत्ति लागतों के अनुसार भौजूदाम हमाराई रुझानों को मददमजर रखते हुए 10 प्रतिशत वृद्धि को बिल्कुल सही माना गया है। इसके बाद, पिछले तीन वर्षों के दौरान वीडीए में औसत वार्षिक वृद्धि 12.67%</p>																											
(viii).	<p>केपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई 2012 के कवर के अंतर्गत प्रेषित संशोधित विवरणों में, यह स्पष्ट नहीं है कि केपीटी विवरण-ग में 1 जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 तक की अवधि के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के मामले में प्रोद्भूत कुल व्यय राशि ₹ 31,58,16,098/- पर कैसे पहुंचा है। विवरण - घ (जो 1 जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 तक की अवधि के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के लागत व्यापे दर्शाता है) में दिए गए अनुसार पेशन/उपदान राशियां एवं वृद्धियों सहित सभी व्यय का कुल जोड़ उक्त राशि में नहीं जोड़ा गया है। केपीटी से अनुरोध है कि रिथित स्पष्ट करे और सही स्थिति दर्शाने के लिए विवरणों में उपयुक्त वरदलाय, जहां कहीं आवश्यक हो, करे।</p>	<p>टिप्पणी: 01-01-2010 को वीडीए प्रतिशत 31 प्रतिशत था। इसके बाद, तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि ऊपर दी गई है।</p> <p>कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के मामले में प्रोद्भूत कुल व्यय ₹ 31,58,16,098/- का कुल व्यय दर्शाने वाला विवरण जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 अवधि के लिए है जो नीचे दिया गया है।</p> <table border="1" data-bbox="828 1670 1398 1959"> <thead> <tr> <th>क्र सं</th> <th>विवरण</th> <th>व्यय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>वेतन और मजदूरीय (ओवरटाइम राशि ₹ 0 782.46 लाख रुहिं)</td> <td>2,690.11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>रेंडर</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कार्यालय तथा प्रशासन व्यय</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>विकिता व्यय</td> <td>21.40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>मुख्यहास</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>पेशन उपदान तथा कम्प्यूटरशन</td> <td>520.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>31,58,15</td> </tr> </tbody> </table>	क्र सं	विवरण	व्यय	1	वेतन और मजदूरीय (ओवरटाइम राशि ₹ 0 782.46 लाख रुहिं)	2,690.11	2	रेंडर	14.00	3	कार्यालय तथा प्रशासन व्यय	1.20	4	प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय	0.50	5	विकिता व्यय	21.40	6	मुख्यहास	5.00	7	पेशन उपदान तथा कम्प्यूटरशन	520.00			31,58,15
क्र सं	विवरण	व्यय																											
1	वेतन और मजदूरीय (ओवरटाइम राशि ₹ 0 782.46 लाख रुहिं)	2,690.11																											
2	रेंडर	14.00																											
3	कार्यालय तथा प्रशासन व्यय	1.20																											
4	प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय	0.50																											
5	विकिता व्यय	21.40																											
6	मुख्यहास	5.00																											
7	पेशन उपदान तथा कम्प्यूटरशन	520.00																											
		31,58,15																											

		वेतन तथा मजदूरी शीर्ष के अधीन विवरण घा में, ओवरटाइम राशि रु0 7,82,46,087 की कटौती की गई है और जैसाकि बिन्दु सं 15 के अधीन उल्लिखित किया गया है, रु0 40,00,000 जोड़े गए हैं।						
(ix).	केपीटी से अनुरोध है कि विवरण-घ के संदर्भ में निम्नलिखित स्पष्ट करें— (क). वार्षिक लेखों की तुलना में दर निर्धारित करने के लिए जैसे तथा मजदूरियों हेतु भिन्न-भिन्न राशि पर विचार करने के कारण बताएं।	केपीटी व्यय में, बुकिंग पहले प्रभाग स्तर पर की जाती है और उसके बाद इसे केंद्रीकृत लेखांकन प्रणाली में अद्यतन किया गया है। वार्षिक लेखों को प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव जमा किए जाने के समय तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यदि कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के साथ प्रतिवेदित व्यय आंकड़े लेखांकन बही को अद्यतन नहीं किए जाने की वजह से उच्चतर थे तो उसपर विचार किया गया है।						
	(ख). भंडारों के संबंध में, केपीटी ने प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए रु0 13,60 लाख की राशि पर विचार किया है जिसमें प्रखंड वर्ष 2008-2010 के लिए एकसमान लागत के स्थान पर रोकड़ के लिए रु0 6,62 लाख की राशि शामिल है। जून 2011 से नवम्बर 2011 तक की अवधि के लिए व्यय में वर्ष 2008-2010 से संबंधित लदाई राशि के लिए कारण स्पष्ट करें और औचित्य बताएं।	यद्यपि, वर्ष 2008-10 से संबंधित, एकसमान के स्थान पर रोकड़ वर्ष 2011-12 के दौरान भुगतान किए जाने के लिए वास्तव में निर्णीत किया गया है।						
(x)	विवरण-घ में कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के लिए राजस्व अपेक्षा पर पहुंचने के लिए केपीटी द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण को 1 जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 अवधि के लिए छह महीनों का घाटा प्रतिवेदित किया है। केपीटी से अनुरोध है कि वह यह स्पष्ट करे कि यह दृष्टिकोण 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा परिकल्पित प्रशुल्क के निर्धारण की लागत जमा पद्धति के अनुसार है।	केपीटी घाटा वहन नहीं कर सकता और वैसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें इसे संशोधित दरों में इसका बोझ डाले बिना वसूल किया जा सके। टीएएमी कोई अन्य विकल्प पद्धति सुझाए जिसमें घाटा आमेलित किया जा सके।						
(xi).	(क). विवरण-घ में कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के लिए राजस्व अपेक्षा पर पहुंचने के लिए केपीटी द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण को 1 जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 अवधि के लिए छह महीनों का घाटा प्रतिवेदित किया है। केपीटी से अनुरोध है कि वह यह स्पष्ट करे कि यह दृष्टिकोण 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा परिकल्पित प्रशुल्क के निर्धारण की लागत जमा पद्धति के अनुसार है।	केपीटी आदर्शतः घाटे को बांटना नहीं चाहता है। तथापि, जैसाकि पहले बताया गया है, वीडीए दरों में वृद्धि के साथ शामिल की गई दरों के संशोधन में विलंब के परिणामस्वरूप दरों में भारी भिन्नता आई है जो ट्रेड वहन नहीं कर सकता। यह इस कारण की वजह से है कि केपीटी का पूरी तरह लगता है कि टीएएमी अपने द्वारा अनुसंधान के अधीन तत्संबंधी पत्तनों द्वारा अपनी ओर से तिमाही आधार पर वृद्धि स्वीकार करेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि दरें हर समय लागतों से बराबर की गई हैं और यहां तक कि आयातक और निर्धारित वृद्धि की संभावित मात्रा का अनुमान लगा सकता है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े प्रत्येक तिमाही में घोषित किए जाते हैं।						
	(ख). कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के लिए दर के निर्धारण हेतु पांच वर्षों की अवधि में रु0 3 करोड़ के ओवरटाइम घटक के ऐसे भाग को बांटे जो को पीछे का आधार भी बताएं।	दरों में भारी भिन्नता से बचने के मददेनजर पूरी तरह से पत्तन ने ट्रेड के अनुरोध पर पांच वर्षों की अवधि में घाटे को बांटने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। केपीटी के न्यासी मंडल का भी यही मत था कि चूंकि आगामी वर्षों के लिए स्टीवेडोरिंग करारों पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और दरों भारी संशोधन की स्थिति में, स्टीवेडोर्स दरों में भारी वृद्धि के प्रभाव को वहन नहीं कर सकते और इसे अंतिम उपयोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता, जिसके वाणिज्यिक परिणाम हों सकते हैं और विधिक समस्याएं होंगी तथा इसलिए नुकसान को बांटने का निर्णय लिया गया था जो पड़ोसी पत्तनों से प्रतिस्पर्धा के मददेनजर लागत प्रभाव सुनिश्चित करेगा।						
(xii).	विवरण-घ में सुविचारित नियोजित पूंजी रु0 2.75 करोड़ के लिए आधार भेजें। विवरण में सुविचारित नियोजित पूंजी का ब्रेकअप भी भेजें।	विवरण में सुविचारित नियोजित पूंजी का ब्रेकअप दर्शाता विवरण भेजा गया है।						
	पुष्टि करते हुए कि बल्क तथा ब्रेक बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए विवरण-घ में सुविचारित गैंग अपेक्षा 14383 छह महीनों की अवधि 1 जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार है।	<table border="1"> <tr> <td>आपेक्षित सकल प्रखंड</td> <td>44036339</td> </tr> <tr> <td>घटकों के मूल्यांक</td> <td>18466878</td> </tr> <tr> <td>लिखित मूल्य</td> <td>27541461</td> </tr> </table> <p>यह पुष्टि की गई है कि रु0 14383 की गैंग अपेक्षा 01-06-2011 से 30-11-2011 तक छह महीनों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है।</p>	आपेक्षित सकल प्रखंड	44036339	घटकों के मूल्यांक	18466878	लिखित मूल्य	27541461
आपेक्षित सकल प्रखंड	44036339							
घटकों के मूल्यांक	18466878							
लिखित मूल्य	27541461							
(xiii).	केपीटी ने अपनी नणनाओं में सीमेंट तथा सोडा एश के कार्गो थ्रुपुट दर दिखार नहीं किया है और उसके कार्गो को प्रहसित किए जाने के लिए कोई दर भी प्रस्तावित नहीं की है, शायद इस आधार पर	सोडा एश केपीटी ने लर्ब समय से प्रहसित नहीं किया जा रहा है और इन कार्गो के प्रहस्तन किए जाने के मौके भी दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। मीजूडा वित्तीय वर्ष के छह महीनों के दौरान 14604						

कि 1 जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 तक छह महीने की अद्यता के दौरान ये कागों प्रहरित नहीं किए गए थे। इस संबंध में, केपीटी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध है कि यदि भविष्य में ऐसे कागों का प्रहस्तन किया जाता है तो कौन सी दरें वसूल की जाएंगी।

मीट की बहुत ही नयाप्य मात्रा का प्रहस्तन किया गया है। दरों को संबंध में जो ऐसे कागों के प्रहरित किए जाने पर वसूल की जाएंगी, यह स्पष्ट किय गया है कि टीएमपी द्वारा यथा अनुमोदित "सभी अन्य अविनिर्दिष्ट सामान" के लिए निर्धारित दरे प्रभारित की जाएंगी। इसके अलावा, इन कागों के लिए पृथक् दरे निर्धारित करने से बहुत अधिक प्रति टन दरे होतीं। उदाहरण के लिए पहले से यथा प्रत्तावित ₹ 0 21220/- की प्रति गैंग राजस्व अपेक्षा को लेते हुए, सीमेंट के लिए प्रति टन दर ₹ 0 75.37 प्रति मीट रहती है। यह 14604 मीट सीमेंट के प्रहस्तन के लिए वास्तव में तैनात किए गए 52 गैंगों पर आधारित है। उपर्युक्त के विपरीत, पत्तन ने ₹ 0 36.26 प्रति मीट वसूल किए हैं।

(xv). यह दिखावे देता है कि विवरण-ड में ₹ 0 36 लाख पर परिणामित 17 दिनों की ओवरटाइम लागत को विवरण-घ में दिए गए लागत परिकलन ने शामिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, विवरण-ड की प्रासंगिकता स्पष्ट करें।

प्रस्ताव में सुविचारित वेतनों तथा मजदूरियों पर व्यय राशि ₹ 184764814/- में पूर्वानुमानित ओटी संबंधी ₹ 0 40,00,000/- पहले से शामिल किया गया है। हालांकि 17 दिनों के लिए ओटी ₹ 0 36 लाख परिणामित होता है जैसा विवरण-ड में दर्शाया गया है, इसे पूर्णांकित किया गया है और विवरण-घ में ₹ 0 40,00,000/- सुविचारित किया गया है।

6.1. इस मामले से संयुक्त सुनवाई 11 जनवरी 2013 को केपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। केपीटी ने अपने प्रस्ताव का पादर खाइट प्रस्तुतीकरण दिया था; संयुक्त सुनवाई में, केपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों ने अपने निवेदन रखे थे।

6.2. संयुक्त सुनवाई में, कांडला पत्तन कम्यारी संघ (कैपीकेएस) ने अपने पत्र दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा विषय प्रस्ताव पर अपने लिखित निवेदन नेतृत्वे किए। तत्पश्चात्, कांडला स्टीवडोर्स असोसिएशन लिमिटेड (कैएसए) ने अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी 2013 द्वारा और कांडला पोर्ट डॉक स्वीडोर्स असोसिएशन (कैपीडीएसए) ने अपने पत्र दिनांक 7 जनवरी 2013 द्वारा केपीटी को सम्बोधित और इस प्राधिकरण को पृथक्कित प्रति में विषय प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां भेजी थीं। इन निवेदनों की एक-एक प्रति हमारे पत्र दिनांक 30 जनवरी 2013 और 18 फरवरी 2013 द्वारा टिप्पणियों के लिए केपीटी को अग्रेषित की गई थीं। केपीटी ने उसपर अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी हैं।

7.1. संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, निम्नलिखित बिन्दु इस अनुरोध के साथ केपीटी के नोटिस में लाए गए थे कि हमारे पत्र दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएः—

- (i). केपीटी का प्रस्ताव परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर में बदलाव को लेने के लिए तिमाही आधार पर ऑन-बोर्ड लेवर की आपूर्ति के लिए प्रति टन दरों में संशोधन करने के लिए है। पत्तन ने वीडीए में बदलाव दरों के लिए अपनी ओर से प्रत्येक तिमाही में प्रति टन दरों को संशोधित करने और उसके लिए वाद में प्राधिकरण का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, केपीटी देखे कि मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देश तीन वर्षों के प्रशुल्क घटक के लिए प्रशुल्क निर्धारण की मांग करते हैं।
- (ii). वास्तविक अनुमानों के आधार पर तीन वर्षों अर्थात् 2012-13 से 2014-15 के प्रशुल्क घटक को कवर करते हुए अपने सीएचडी के ऑन-बोर्ड लेवर की आपूर्ति के लिए दरों की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव दोबारा तैयार करे। प्रस्ताव तैयार करते समय, वर्ष 2012-13 के लिए अनुमान अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 अवधि के वास्तविक आंकड़ों और वर्ष 2012-13 के अनुवर्ती तीन महीनों के लिए अनुमानों पर निर्धारित किए जाएँ।
- (iii). केपीटी के सीएचडी के लिए दरें संबद्ध प्रशुल्क आदेश में रिकार्ड किए गए कारणों से एक वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए आखिरी बार निर्धारित की गई थी। प्रशुल्क दिशानिर्देश निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि की समाप्ति पर वास्तविक भौतिक तथा वित्तीय कार्यान्वयन की समीक्षा किए जाने की अपेक्षा करते हैं; इसलिए, केपीटी से अनुरोध है कि वर्ष 2011-12 के लिए सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित सीएचडी के लेखा द्वारा समर्थित वर्ष 2011-12 के दोरान अपने सीएचडी द्वारा प्रोद्भूत लागत, प्रहस्तन किए गए घटक-घर यातायात की वार्तादिक सात्रा और वसूल की गई आय के ब्यांजे भेजें।
- (iv). संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत घाटशुल्क में सीएचडी के ऑन-बोर्ड लेवर प्रभार शामिल करने के लिए कांडला पोर्टस स्टीवडोर्स असोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव की जांच करें।

7.2. हमारे पत्र दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसरण में, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 21 फरवरी 2013 द्वारा अपना पुनः तैयार किया गया प्रस्ताव दाखिल किया था और अपना प्रत्युत्तर/निवेदन भी भेजे थे। केपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातें नीचे सारबद्ध की गई हैं:-

- (i). संशोधित प्रस्ताव वास्तविक अनुमानों के आधार पर तीन वर्षों 2012-13 से 2014-15 के प्रशुल्क चक्र के लिए तैयार किया गया है। यथा निदेश, वर्ष 2012-13 के लिए अनुमान अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों और वर्ष 2012-13 के अनुरूपी तीन महीनों के अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- (ii). संशोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित विन्दुओं को लेखा में लिया गया है:-
 - (क). 01-01-2012 से देय मजदूरी संशोधन की वजह से वेतन और मजदूरी में वृद्धि के लिए 20 प्रतिशत प्रावधान।
मूल वेतन पर 10 प्रतिशत की वीडीए वृद्धि।
 - (ख). वर्ष 2011-12 के दौरान आय पर व्यय की अधिकता राशि ₹ 0 9,17,01,747/- और वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 0 11,05,54,557/- क्रमशः वर्ष 2012-13 और 2013-14 में सुविचारित किए गए हैं।
 - (ग). ओवरटाइम राशि ₹ 0 6,00,00,000/- को 5 वर्षों में बाटा गया है और तदनुसार प्रत्येक वर्ष में ₹ 0 1,20,00,000/- सुविचारित किया गया है।
 - (घ). वर्ष 2013-14 और 2014-15 के अनुमानन में मजदूरी बिल (वीडीए से इतर) में सामान्य वृद्धि के लिए 3 प्रतिशत वृद्धि पर विचार किया गया है। अन्य व्यय टीएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार 6.5 प्रतिशत का वृद्धि कारक लागू करते हुए अनुमानित किया गया है।
- (iii). पत्तन ने सीएचडी का संशोधित लागत विवरण दाखिल किया है। 2011-12 से 2014-15 अवधि के लिए केपीटी द्वारा प्रेषित लागत स्थिति का सार नीचे तालिकाबद्द किया गया है-

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक आंकड़े	अनुमान			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(1)	कुल व्यय	420514847	496039764	524762792	554769573	
(2)	उपदान	25372723	37146748	29002949	24648265	
(3)	पेशन का संधान	12799998	18739742	18364993	14839349	
(4)	पेशन	63027279	92274622	103033294	120799844	
(5)	वर्ष 2011-12 के दौरान (ओटी के अलावा) आय पर व्यय की अधिकता ₹ 0 91701747 + वोई द्वारा यथा निर्णीत 5 वर्षों के लिए बाटी गई ओटी राशि अर्थात् ₹ 0 (3 करोड़ * 2/5) = ₹ 0 12000000	108459654	103701738	122554551	12000000	
(6)	कुल व्यय (1+2+3+4+5)	630174501	747902614	797718579	727057031	
(7)	नियोजित पूँजी	27541000	27541000	27541000	27541000	
(8)	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ @ 16% वार्षिक	4406560	4406560	4406560	4406560	
(9)	राजस्व अपेक्षा	634581061	752309174	802125139	731403551	
(10)	अपूर्ति किए गए कुल मैग (रु.)	27554	28139	28139	28139	
(11)	अपेक्षित राजस्व प्रति मैग	23030	26735	28506	25995	

(iv). पत्तन ने अपेक्षित राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग की पूर्ति करने के लिए घटक-वार प्रति टन दर पर पहुंचने के लिए गणना भेजी है।

(v). तदनुसार, मौजूदा दरों की तुलनात्मक स्थिति और अब प्रस्तावित की गई दरों के साथ ऑन-बोर्ड लेबर के लिए केपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित दरें नीचे तालिकाबद्ध की गई हैं:-

क्र. सं	कार्गो बद्दे	मौजूदा दरें (प्रति टन)				प्रस्तावित दरें (प्रति टन)				वृद्धि का %			
		बल्क		इंडेक्स बल्क		बल्क		इंडेक्स बल्क		बल्क		इंडेक्स बल्क	
		विदेशी रुपय	तटीय रुपय	विदेशी रुपय	तटीय रुपय	विदेशी रुपय	तटीय रुपय	विदेशी रुपय	तटीय रुपय	विदेशी रुपय	तटीय रुपय	विदेशी रुपय	तटीय रुपय
1	जर्वरक / उर्वरक कच्चा माल	13.96	8.37	42.92	25.75	24.36	14.61	-	-	74.79%	74.55%	--	--
2	चादल और अन्य खाद्याल्य	21.62	12.97	27.23	16.34	40.63	24.38	65.63	39.38	87.92%	87.97%	141.02%	141%
3	सीमेट	-	-	21.05	12.63	-	-	129.75	77.85	--	--	516.38%	516.38%
4	स्टील कोइल और स्टील पाइप	-	-	17.55	10.53	--	-	34.9	20.94	--	-	98.86%	98.86%
5	टिक्का तथा अन्य लद्दू	-	-	38.64	23.18	-	-	53.13	31.88	-	-	37.5%	37.53%
6	सोडा एता	-	-	60.89	36.54	-	-	32.41	19.45	-	-	(-55.51%)	(-55.51%)
7	वशीनी पैकेज और अन्य पैकेज	-	-	72.84	43.71	-	-	-	-	-	-	-	-
8	लोह अयस्क	11.14	11.14	-	-	22.59	22.59	-	--	102.76%	102.78%	--	--
9	लोह अयस्क से इतर अयस्क	12.20	7.32	-	-	22.22	13.33	-	-	82.13%	82.10%	--	--
10	कबाड़	20.45	12.27	-	-	45.25	27.15	-	-	121.27%	121.27%	--	--
11	तेल एम्बर्ट्स्ट्रेस	18.95	11.37	-	-	28.31	16.98	40.01	24.01	49.39%	49.34%	--	--
12	ताप ऊर्ध्वता	10.39	10.39	-	-	27.33	27.33	-	--	163.04%	163.04%	--	--
13	अन्य जोखना	9.11	5.46	-	-	12.15	7.29	-	-	33.36%	33.51%	--	--
14	नमक	11.12	6.67	32.59	19.55	16.84	10.11	35.49	21.29	51.43%	51.57%	8.89%	8.9%
15	वीनी	17.42	13.45	25.80	15.48	28.16	16.89	73.98	44.39	61.65%	51.62%	186.74%	186.75%
16	स्टील अन्य अविनियोन्द्र तापान्न	10.85	9.51	36.26	21.75	14.70	8.82	-	--	35.48%	35.48%	131.77%	--
17	यैनहॉल और भारवल	--	--	--	--	--	--	50.79	30.48	--	--	--	--

(vi). केपीटी ने वर्ष 2011-12 के दौरान प्रहसित घटक-वार यातायात की वास्तविक मात्रा, वसूल की गई आय और सीएचडी द्वारा प्रोद्भूत लागत के ब्यारे भेजे हैं।

(vii). वीडीए में तिमाही वृद्धि आमेलित करने के लिए तिमाही आधार पर दरें संशोधित किए जाने के अपने प्रस्ताव पर हमारे द्वारा कही गई बात के संबंध में, केपीटी ने एक बार दोबारा 11 जनवरी 2013 को हुई संयुक्त सुनवाई में यथा चर्चा किए गए तीन वर्ष प्रश्नलूप वैधता चक्र के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में प्रति टन दर पर (संविधी आधार पर) निश्चित प्रतिशत वृद्धि स्वीकार करने का अनुरोध किया है। इसने बताया है कि यह पट्टा किरायों/अपफ्रंट प्रश्नलूप निर्धारण पर टीएमपी द्वारा स्वीकृत की गई वार्षिक वृद्धि के अनुसार है।

(viii). संयुक्त सुनवाई में घाटशुल्क में सीएचडी के ऑन-बोर्ड लेबर प्रभार को शामिल करने के लिए काडला पाठौरीडोस असोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव के संदर्भ में, केपीटी ने निम्नलिखित निवेदन किए थे:-

(क). स्टीवडोरिंग प्रभार महासागर मालभाड़ा का लगभग अपरिवर्तनीय भाग है और सामान्य तौर पर पोत एजेंटों द्वारा स्टीवडोर्स को भुगतान किया जाता है, जबकि घाटशुल्क प्रभार निर्धारणीय मूल्य का हिस्सा नहीं है, जबकि इन्हे सामानों की उत्तराई के बाद प्रोद्भूत किया जाता है। आयातक अपने शुल्क दावों के लिए घाटशुल्क और ऑन-बोर्ड लेबर प्रभारों हेतु पत्तन द्वारा जारी किए गए पृथक बिलों/रसीदों की अपेक्षा कर सकते हैं।

(ख). स्टीवडोरिंग प्रभार उत्तराई प्रभारों में शामिल करते हुए कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम द्वारा सामानों की सीआईएफ कीमत के प्रतिशत रूप में वसूल किए जाते हैं, के प्रयोजन के लिए सामानों का "निर्धारणीय मूल्य" का हिस्सा है, जबकि घाटशुल्क प्रभार निर्धारणीय मूल्य का हिस्सा नहीं है, जबकि इन्हे सामानों की उत्तराई के बाद प्रोद्भूत किया जाता है। आयातक अपने शुल्क दावों के लिए घाटशुल्क और ऑन-बोर्ड लेबर प्रभारों हेतु पत्तन द्वारा जारी किए गए पृथक बिलों/रसीदों की अपेक्षा कर सकते हैं।

(ग). घाटशुल्क प्रभारों और ऑन बोर्ड लेबर प्रभारों के प्रयोजन के लिए घटकों का वर्गीकरण बहुत अधिक भिन्न हैं और यह दोनों प्रभारों को जोड़ा जाता है तो घटकों का वर्गीकरण एकसमान होगा।

(घ). घाटशुल्क प्रभारों की वसूली और ऑन-बोर्ड लेबर प्रभारों की इकाईयां भिन्न हैं। जब घाटशुल्क प्रभारों की वसूली के लिए विभिन्न इकाईयां निर्धारित की जाती हैं जैसे घन मीटर, मीट्रिक टन, संख्याएं, यथामूल्य, ऑन बोर्ड लेबर प्रभारों की वसूली की इकाई केवल मीट्रिक टन है। इसलिए वसूली की इकाई के मामले में एकलपता समेकन से पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ङ). घाटशुल्क और स्टीवडोरिंग प्रभारों का समेकन कुछ व्यावहारिक मुश्किलें पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि सीआईएफ आधार पर कांडला पत्तन को विदेशी पत्तन से सामान्य निर्यात किए जाते हैं तो विदेशी पत्तन में स्थित निर्यातक को कांडला में सामानों की उत्तराई के लिए स्टीवडोरिंग प्रभार शामिल करने होंगे और कांडला में स्थित आयातक से प्रभारों की वसूली पहले ही कर ली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में, स्टीवडोर घाटशुल्क प्रभारों का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होगा क्योंकि वह अपने स्टीवडोरिंग प्रभारों का भुगतान पहले ही कर चुका है और सीएचए भी ऑन-बोर्ड लेबर प्रभार अदा करने के लिए कभी भी सहमत नहीं होगा क्योंकि वह निर्यातक को समेकित दर का भुगतान पहले ही कर चुका है। इसी तरह की स्थिति सीआईएफ आधार पर विदेशी पत्तन को कांडला से निर्यात किए गए सामानों पर भी उत्पन्न होगी। यह समस्या आगे और बढ़ जाएगी यदि कुछ आयातकों ने एफओबी आधार पर कारों का आयात किया हो जबकि कुछ आयातकों ने एफओबी आधार पर कारों का आयात किया हो। इसलिए, यह राय दी गई है कि घाटशुल्क में ऑन-बोर्ड लेबर प्रभारों को जोड़ जाने का मुददा बाद में सभी संबंधितों से सुविचारित राय प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

7.3 केपीटी से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव उपयोक्ता/उपयोक्ता असोसिएशन को हमारे पत्र दिनांक 27 फरवरी 2013 द्वारा परिवार्ता किया गया था। ऐसे प्राप्त हुई टिप्पणियां केपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेप्ति की गई थीं। तथापि, केपीटी ने उसपर अपना प्रत्युत्तर नहीं भेजा है।

8 संशोधित प्रस्ताव दिनांक 21 फरवरी 2013 की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, केपीटी से हमारे पत्र दिनांक 12 जुलाई 2013 द्वारा कुछ विन्दुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 19 जुलाई 2013 द्वारा हमारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया था। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों और केपीटी के जवाब का सार नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं-

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	केपीटी से प्राप्त प्रत्युत्तर																																																				
(i).	कृपया अनुबंध-I, क्र.सं. (त) में वर्ष 2011-12 में सुविचारित रु 10,845,9654 का ब्रेकअप भेजें।	यह निवेदन है कि वर्ष 2012-13 में ₹ 103701747/- सुविचारित किया गया है जिके लिए पत्तन ने ब्रेकअप भेजा है।																																																				
(ii).	आरई 2012-13 तथा बीई 2013-14 और आरई 2011-12 तथा बीई 2012-13 में सीएचडी से संबंधित आंकड़ों का अवलोकन करने पर, यह देखा गया है कि वर्ष 2011-12 के लिए वार्सविक ओवरटाइम ₹ 1670 76 लाख है जो वार्सविक मूल वेतन जमा डी.ए. (₹ 1959.39) का 85 प्रतिशत होता है। तत्काल पिछले वर्ष 2010-11 में, सीएचडी के लिए ओवरटाइम व्यय ₹ 1001.59 लाख प्रतिवेदित किया गया है जो मूल वेतन जमा डी.ए. ₹ 2041.09 लाख का 50 प्रतिशत होता है। इस सदर्म में, निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट करें-	(क). प्राथमिक कारण जो ओवरटाइम व्यय में वृद्धि की वजह से हो सकता है सीएचडी गैंगों के सापेक्ष उनकी आपूर्ति के लिए मांग की अधिकता है। मह-वार भाग बनाम सीएचडी गैंगों की आपूर्ति और घाटा निम्नवत है:-																																																				
	(क). वर्ष 2011-12 में ओवरटाइम लागत में तीव्र वृद्धि के कारण स्पष्ट करें।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>माह</th><th>सीएचडी गैंगों की मांग</th><th>सीएचडी गैंगों की आपूर्ति</th><th>घाटा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अप्रैल 2011</td><td>1928</td><td>1594</td><td>334</td></tr> <tr> <td>मई 2011</td><td>1986</td><td>1643</td><td>343</td></tr> <tr> <td>जून 2011</td><td>2031</td><td>1614</td><td>417</td></tr> <tr> <td>जुलाई 2011</td><td>2350</td><td>1668</td><td>682</td></tr> <tr> <td>अगस्त 2011</td><td>2350</td><td>1668</td><td>682</td></tr> <tr> <td>सितं 2011</td><td>2440</td><td>1620</td><td>820</td></tr> <tr> <td>अक्टू 2011</td><td>2161</td><td>1654</td><td>507</td></tr> <tr> <td>नव. 2011</td><td>2223</td><td>1611</td><td>612</td></tr> <tr> <td>दिस. 2011</td><td>2467</td><td>1672</td><td>795</td></tr> <tr> <td>जन. 2012</td><td>2200</td><td>1669</td><td>531</td></tr> <tr> <td>फर. 2012</td><td>2028</td><td>1496</td><td>532</td></tr> <tr> <td>मार्च 2012</td><td>1747</td><td>1544</td><td>203</td></tr> </tbody> </table>	माह	सीएचडी गैंगों की मांग	सीएचडी गैंगों की आपूर्ति	घाटा	अप्रैल 2011	1928	1594	334	मई 2011	1986	1643	343	जून 2011	2031	1614	417	जुलाई 2011	2350	1668	682	अगस्त 2011	2350	1668	682	सितं 2011	2440	1620	820	अक्टू 2011	2161	1654	507	नव. 2011	2223	1611	612	दिस. 2011	2467	1672	795	जन. 2012	2200	1669	531	फर. 2012	2028	1496	532	मार्च 2012	1747	1544	203
माह	सीएचडी गैंगों की मांग	सीएचडी गैंगों की आपूर्ति	घाटा																																																			
अप्रैल 2011	1928	1594	334																																																			
मई 2011	1986	1643	343																																																			
जून 2011	2031	1614	417																																																			
जुलाई 2011	2350	1668	682																																																			
अगस्त 2011	2350	1668	682																																																			
सितं 2011	2440	1620	820																																																			
अक्टू 2011	2161	1654	507																																																			
नव. 2011	2223	1611	612																																																			
दिस. 2011	2467	1672	795																																																			
जन. 2012	2200	1669	531																																																			
फर. 2012	2028	1496	532																																																			
मार्च 2012	1747	1544	203																																																			
	(ख). यह दिखाई देता है कि वर्ष 2011-12 में प्रतिवेदित ओवरटाइम लागत में मजदूरी संशोधन वकाया राशियों का प्रभाव शामिल है। यदि ऐसा है तो कृपया इस लागत में शामिल पूर्व अवधि के मजदूरी संशोधन वकाया राशियों की मात्रा दर्शाएं।	(ख). गैंगों की मांग तथा आपूर्ति के बीच बेमेल के अलावा, दूसरे																																																				

		<p>कारक जो 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान आठी. में बढ़ोतरी में योगदान दे सकते हैं, मजदूरी संशोधन के परिणाम के रूप में प्रति घटा ओटी. में वृद्धि है। मजदूरी संशोधन से पहले तथा मजदूरी संशोधन के बाद सीएचडी कामगारों 36%। टिण्डल तथा आरपी कामगार की प्रत्येक दो श्रेणियों वरिष्ठतम् और कनिष्ठतम् कर्मचारी की प्रति घटा ओटी दर दर्शाते हुए तालिका नीचे तालिकाबद्द की गई है:-</p>			
अवधि	माह	प्रति घटा ओटी. दर			
		टिण्डल		आरपी कामगार	
	वरिष्ठ	कनिष्ठ	वरिष्ठ	कनिष्ठ	
मजदूरी संशोधन के बाद	अप्रै-11	110.25	52.68	107.25	49.61
मजदूरी संशोधन से पहले	फर.-10	83.58	42.75	78.34	42.75
% घमार		31.91	23.23	36.90	16.05

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि ओटी. दर प्रति घटा में मजदूरी संशोधन की वजह से 16 से 32 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है।

(ग) उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान प्रति घटा ओटी. दर में वृद्धि वीडीए वृद्धि की वजह से थी जिसे नीचे तालिकाबद्द किया गया है-

अवधि	माह	प्रति घटा ओटी. दर			
		टिण्डल		आरपी कामगार	
	वरिष्ठ	कनिष्ठ	वरिष्ठ	कनिष्ठ	
वर्ष की शुरूआत	Apr-11	110.25	52.68	107.25	49.61
वर्ष का अंत	Mar-12	121.56	56.26	118.01	54.63
% घमार		10.26	6.80	10.03	10.12

यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान वीडीए वृद्धि 7-10 प्रतिशत है।

(iii). प्रस्ताव दिनांक 2 जुलाई 2012 में, केपीटी ने अपने न्यासी मंडल द्वारा यथा निर्णीत रु 3 करोड़ ओवरटाइम को 5 वर्षों की अवधि (अर्थात् वार्षिक 60 लाख) में बाटने पर विचार किया था और शेष रु 3 करोड़ सामान्य संशोधन प्रस्ताव से वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया था। उसके विपरीत 21 फरवरी 2013 के संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन ने रु 6 करोड़ के ओवरटाइम पर विचार किया था और इसे पांच वर्षों की अवधि (अर्थात् 120 लाख प्रतिवर्ष) में बाटे जाने का प्रस्ताव किया था। ओवरटाइम लागत में संशोधन के लिए कारण बताएं।

(iv). पिछले आदेश में वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित उपदान, पेंशन का कम्पूटेशन और पेंशन भुगतान और मौजूदा प्रस्ताव में केपीटी द्वारा दर्शाएं गए वास्तविक भुगतानों को नीचे तालिकाबद्द किया गया है:-

(रु 0 लाखों में)

क्र. स.	विवरण	2011-12	
		अनुमान	वास्तविक
(i).	उपदान	53.11	253.73
(ii).	पेंशन का कम्पूटेशन	15.06	127.99
(iii).	पेंशन	392.93	630.31
	जोड़	461.10	1011.98

(क). पेंशन भुगतानों के अनुमानन के समय पर, अधिविष्टा वीआरएस, चिकित्सा इनकोपिसिटेशन, मृत्यु आदि की वजह से प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वालों की सख्ता पर विचार नहीं किया गया था जो वर्ष 2011-12 में 159 स. और वर्ष 2012-13 में 110 स. है।

(ख). इसके अलावा, पेंशन भुगतानों में वार्षिक वृद्धि 5.8 प्रतिशत की दर से सुविचारित की गई थी जोकि वीडीए की दर में देखी गई बहुत मामूली वृद्धि है जिसमें 2010-11 में 11 प्रतिशत तक, 2011-12 में 13 प्रतिशत और 2012-13 में 15 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

	<p>कृपया अनुमानित स्थिति के विरुद्ध इन भुगतानों में ऐसी तीव्र वृद्धि के कारण स्पष्ट करें। यदि वास्तविक भुगतानों में पूर्व अवधि से संबंधित बकाया राशियां शामिल हैं तो इसकी मात्रा दर्शाई जाए।</p>	<p>बूढ़े पेशनरों को लाभों के कम्प्यूटेशन विस्तार का रिस्टोरेशन तथा विधवा, अविवाहित तथा तलाकशुदा पुत्रियों को परिवार पेशन का विस्तार सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा विस्तारित किए गए थे और लाग 01-01-2007 से विस्तारित किए गए थे।</p> <p>(ग). यह भी जोड़ा जाए कि प्रस्ताव जमा किए जाने के समय पर पेशन भुगतानों के अनुमानन के समय, पेशन संशोधन की वजह से पेशन भुगतानों में होने वाली वृद्धि के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था।</p> <p>वास्तविक भुगतानों में पूर्व अवधि से संबंधित बकाया राशियों को शामिल नहीं किया गया है।</p>
(v).	<p>वर्ष 2011-12 में केपीटी द्वारा प्रेषित उपदान, पेशन तथा पेशन भुगतानों का कम्प्यूटेशन वार्षिक लेखों से सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस संबंध में सीएचडी प्रभाग के लिए आंकड़े लेखों में अलग से प्रतिवेदित नहीं किए गए हैं। कृपया पुष्टि करें कि वर्ष 2011-12 के लिए दर्शाएं गए थे आंकड़े पत्तन द्वारा व्यवस्थित व्योरों के अनुसार हैं।</p>	<p>2011-12 और 2012-13 के दौरान सीएचडी के वास्तविक पेशन भुगतान की राशि मासिक पेशन बिल में “सीएचडी” रूप में कागों प्रहस्तन प्रभाग की आरपीओ स. वाले चिह्नित अभिलेखों के आधार परिणित की गई है।</p>
(vi).	<p>वर्ष 2012-14 और 2014-15 में उपदान, पेशन भुगतानों और कम्प्यूटेशन पेशन का अनुमान लगाने का आधार दर्शाया जाए।</p>	<p>वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए उपदान, पेशन भुगतान और कम्प्यूटेशन का अनुमानन दर्शाती गणना भेजी गई है।</p>

9. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये व्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

10. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i). इस प्राधिकरण ने 31 मार्च 2012 तक वैधता अवधि के साथ आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के कागों प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) के लेही और अन्य प्रभागों के स्थान पर ऑन-बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर निर्धारित की थी। हमारे अनुरोध पर, इस प्राधिकरण ने भौजूदा समेकित दर की वैधता को समय-समय पर आस्थिरी बार आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2012 द्वारा 28 फरवरी 2013 तक विस्तारित किया था।
- (ii). (क). केपीटी का पूर्ववर्ती प्रस्ताव दिनांक 2 जुलाई 2012 2011-12 के छह महीनों अर्थात् 1 जून 2011 से 30 नवम्बर 2011 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित था। 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 3.1.8 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला प्रशुल्क तीन वर्षों के वैधता चक्र के लिए है। इसलिए, पत्तन को तीन वर्षों अर्थात् 2012-13 से 2014-15 के वास्तविक अनुमानों के आधार पर प्रस्ताव दोबारा तैयार करने की सलाह दी गई थी। केपीटी ने, तदनुसार, लागत विवरण को 2011-12 के वास्तविक आंकड़ों और वर्ष 2012-13 अर्थात् अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक के नीं महीनों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तीन वर्षों अर्थात् 2012-13 से 2014-15 के अनुमानों से अद्यतन करते हुए 21 फरवरी 2013 को संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया था। केपीटी द्वारा दाखिल किए गए संशोधित प्रस्ताव पर प्रासंगिक अशंधारकों से परामर्श किया गया था। इस मामले की कार्यवाही के दौरान केपीटी द्वारा प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरणों के साथ संशोधित प्रस्ताव दिनांक 21 फरवरी 2013 पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।
- (ख). कांडला स्टीवडोर्स असोसिएशन लिमिटेड (केएसएल) ने निवेदन किया था कि संशोधित प्रस्ताव दिनांक 21 फरवरी 2013 के साथ बोर्ड एजेंडा अथवा बोर्ड संकल्प के कार्यवृत्त में से कोई भी नहीं संलग्न नहीं किए गए हैं। इसलिए, संशोधित प्रस्ताव कांडला पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 3.1.4 पत्तन न्यास से अपेक्षा करता है कि वह पत्तन के न्यासी मंडल के अनुमोदन से इस प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव भेजें। इसके अलावा, मंडल के भौतिकों पर इस प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा यदि प्रस्ताव के जमा करने के दो महीनों के भीतर प्राप्त होता है। जैसाकि केएसएल द्वारा सही उल्लेख किया गया है, संशोधित प्रस्ताव दिनांक 21 फरवरी 2013 पर घोषित एजेंडा या कार्यवृत्त प्राप्त नहीं हुए थे। पत्तन ने जून 2012 के मूल प्रस्ताव पर बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त जमा किए हैं। 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 3.1.4 इस प्राधिकरण को पत्तन न्यास द्वारा उसके बोर्ड के अनुमोदन के बिना जमा किए गए प्रस्ताव पर विचार करने सही रोक जा है।

(ग) कांडला पोर्ट कर्मचारी संघ (केपीएस) ने बताया है कि 24 जनवरी 2007 को केंटीएलबी के केपीटी में विलय के बाद ऑन बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए अनुमोदन मांगे जाने की कार्यवाही 18 जून 2007 को शुरू हुई थी और अतिम दरे 5 वर्षों के बाद अर्थात् 5 मई 2011 को अनुमोदित की गई थी। केपीएस के अनुसार, स्पष्टीकरण के आंतरिक विनियम और टीएमपी द्वारा टुकड़ों में आपत्ति उठाए जाने से केपीटी को वित्तीय हानि हुई थी।

इस संबंध में, यह बताया गया है कि यह प्राधिकरण हमेशा विस्तृत तरीके से सूचना की मांग करता है। पत्र सं. टीएमपी/37/2007-केपीटी दिनांक 22 नवम्बर 2007 द्वारा केपीटी को जारी की गई विस्तृत प्रश्नावली के जवाब संशोधित प्रस्ताव के साथ दिनांक 6 जून 2008 को प्राप्त हुए थे। संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन ने प्रति कामगार प्रति पाली आधार पर वसूली के लिए अपने पूर्ववर्ती प्रस्ताव के स्थान पर प्रति टन आधार पर ऑन बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए प्रमाणों की वसूली का प्रस्ताव किया था। चूंकि 8 जून 2008 को दाखिल किया गया केपीटी का संशोधित प्रस्ताव इसके पूर्ववर्ती प्रस्ताव दिनांक 18 जून 2007 से काफी भिन्न था, इसलिए राशोधित प्रस्ताव राशद्वारा उपयोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किए जाने जरूरत थी। हमारे पत्र सं. टीएमपी/37/2007-केपीटी दिनांक 29 जुलाई 2008 द्वारा संशोधित प्रस्ताव पर मार्गी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण केपीटी द्वारा 24 सितम्बर 2008 को भेजे गए थे। भेजी गई सूचना में देखे गए अन्तरालों को 28 नवम्बर 2008 को पत्तन के नोटिस में लाए गए थे जिन्हें पत्तन द्वारा 6 गार्व 2009 को संबोधित किया गया था। 8 अप्रैल 2010 को हुई संयुक्त सुनायाइ में लिए गए गिरफ्तारों पर कार्रवाई भी केवल 11 अक्टूबर 2010 को भेजी गई थी। अतिरिक्त विवार के लिए डिपिन फांटी पर लिए गए समय पर विचार करते हुए, केपीटी को हुए वित्तीय मुकराना, जो दो कोई नहीं के लिए टीएमपी को जावाबदेह ढहशना उचित नहीं है।

केपीएस ने भी यह दावा किया है कि टीएमपी ने मध्यवर्ती अवधि 2007 से 2011 तक के लिए दरे अनुमोदित की हैं। 5 मई 2011 को अधिसूचित आदेश सं. टीएमपी/37/2007-केपीटी दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा इस प्राधिकरण को अनुमोदित की गई दरे 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू हुई थी।

केपीएस ने बताया है कि टीएमपी ने वर्ष 2007 में प्रचलित लागत के आधार पर मध्यवर्ती जल्दी 2007 से 2011 के लिए दरे अनुमोदित की थी। इस रांबध में, यह उल्लेखनीय है कि केपीटी के साथ केंटीएलबी के विलय के बाद ऑन-बोर्ड लेबर के लिए प्रारम्भिक नियरिक आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा किया गया था। चूंकि यह प्रारम्भिक नियरिक था और चूंकि अतिरिक्त सूचना दरमान में आधार पर मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1 से 2.17.3 के प्रालग्नाओं के अनुसार प्रति कामगार प्रति पाली आधार पर तदर्थ दर का प्रस्ताव किया था। चूंकि जादेश दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा अनुमोदित दरे 30 दिनों की अवधि के बाद प्रभावी होनी थी, इसके दूसरे प्राधिकरण ने नई दरे लागू होने तक प्रस्तावित तदर्थ दरों के लिए कार्यात्मक अनुमोदन प्रदान किया था।

(iii). इस मामले की कार्यवाही के दौरान, केपीटी ने गैंगिंग मान से संबोधित हमारे प्रश्नों का जवाब देते समय कहा था कि इस प्राधिकरण को स्वयं को मैनिंग मान के कार्यान्वयन से नहीं जोड़ना चाहिए जोने एक नीति गमला है और संबद्ध पत्तन न्यासों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कांडला पोर्ट कर्मचारी मंडल (केपीएस) ने भी यह टिप्पणी की थी कि इस प्राधिकरण का कामगार फैडबैक्सों के साथ राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप आरारिक मामलों से कोई लेनादेना नहीं है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि यह प्राधिकरण भारत के महापत्तनों और उनमें प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.6.2 के अनुसार, महापत्तन न्यासों से यह अपेक्षा की गई है कि वे प्रौद्योगिकी वदलावों के मददेनजर ऐनिंग मान की नियमित समीक्षा करें और राष्ट्रीय स्तरीय मजदूरी समाजानों के रूप में समय-समय पर पीस-रेट योजना की दरों और डेटम में संशोधन करें। ऐनिंग मान/डेटम के कार्यान्वयन का पत्तन प्रशुल्क के निर्धारण पर प्रभाव रहा है और ज्यादा विशेषतः सीएचडी जो एक लेबर गहन प्रभाव है। यह प्राधिकरण मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों से बंधा हुआ है जोकि एमपीटी एक्ट, 1963 की धारा 111 के अधीन इस प्राधिकरण को जारी किया गया था। अधिकार की नीति निर्देश है। इसलिए, यह प्राधिकरण ऐनिंग मान तथा डेटम के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

- (iv). केपीटी ने बताया है कि डेटम 1979 में निर्धारित किए गए थे और यूनियनों ने डेटम में वट्ठि का विरोध किया था। उन्होंने पीस टरों में वट्ठि की मांग की थी। पत्तन ने कहा था कि उसने डेटम के संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया है और इसे प्रयामर्श तरीके से हल करना होगा।

ऐनिंग मान के सबध में, केपीटी ने सूचित किया है कि ऐनिंग मान का प्रथम चरण 22 अप्रैल 2012 से कार्यान्वयन किया गया है। इसने स्पष्ट किया है कि ऐनिंग मान के कार्यान्वयन के मददेनजर, गैंग संख्या में कटौती की गई है और ओवरटाइम लागत में भी कमी की गई है। केपीटी ने पुष्टि की है कि 80 प्रतिशत की सीमा एक ऐनिंग मान कार्यान्वयन किया गया है। यह आशका है कि ऐनिंग मान के पूर्ण कार्यान्वयन से मैनपावर का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अधिशेष हो जाएगा और इसलिए उनकी पुनर्तैनाती अथवा रिट्रैट अथवा पुनर्प्रशिक्षण के लिए बिना सही योजना बनाए। ऐनिंग मानों का 100 प्रतिशत कार्यान्वयन रिट्रैट में जाएगा। अत्यवधि योजना सही योजना बनाए। ऐनिंग मानों का 100 प्रतिशत कार्यान्वयन करने से पत्तन में विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और पत्तन क्षेत्र में भारी औद्योगिक अशांति पैदा हो जाएगी। पत्तन ने बताया है कि संशोधित ऐनिंग मान का दूसरा चरण कामगारों की सेवानिवृत्ति/मौत पर विचार करते हुए धीरे-धीरे कार्यान्वयन करने पर विचार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैंग अधिशेष न हो जाए जिससे औद्योगिक अशांति न पैदा हो जाए।

इस नामले में नीति निर्णय लिए जाने तक, पत्तन स्टीवडोरों से उनके वेतनों तथा मजदूरियों की वसूली करने का प्रस्ताव करता है।

यह बताया प्रासंगिक है कि ऐनिंग मान/डेटम के कार्यान्वयन से आखिरकार लागत में कटौती होगी। केपीटी द्वारा स्टीवडोरों से लेबर प्रदत्त अधिशेष की लागत वसूल करने के मददेनजर, संशोधित ऐनिंग मान के कार्यान्वयन का अपेक्षित उददेश्य पूरा नहीं होगा। 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.6.1 गैर-यातायात राजस्व से शेषजमा से राजस्व सोरों और संपदा किराये/प्रीमियम, संचयित आरक्षित निधिया और यातायात राजस्व से शेषजमा से अधिशेष लंबर लागत के प्रभाजन की अनुमति देता है। दिशानिर्देशों का खंड 2.8.3. पहले अधिशेष लंबर की लागत यदि कोई हो, की पूरा करने के लिए राजस्व डिसेंदारी प्राप्तियां लागू करने के लिए पत्तन न्यासों की अधिकार प्रदान करता है और शेषजमा का कम से कम 50 प्रतिशत एस्क्री खाते में अंतरित किया जाना चाहिए। केपीटी को सलाह दी जाती है कि ऐनिंग मान का दूसरा चरण कार्यान्वयन करने के समय मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में किए गए निर्धारण के अनुसार अधिशेष लंबर, यदि कोई हो, की लागत को पूरा करें।

उपर्युक्त स्थिति हांग के बावजूद, तथापि, पत्तन द्वारा दिए गए आश्वासन के मददेनजर कि संशोधित ऐनिंग मान का दूसरा चरण सीएचडी में अधिशेष मैनपावर के मुददे को संबोधित करने के बाद धीरे-धीरे कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें कुछ अधिशेष मैनपावर के साथ विचार-विमर्श से संशोधित किया जाएगा, किया जाएगा जिसमें कुछ समय लगेगा और डेटम यूनियन के साथ विचार-विमर्श से संशोधित किया जाएगा। यह नामला पत्तन द्वारा यथा प्रतिवेदित अनुमानों से सुविळारित डेटम और आंशिक रूप से संशोधित ऐनिंग मान के आधार पर केपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रति टन लंबी निर्धारित करने के लिए विश्लेषित किया गया है। मैन के आधार पर केपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रति टन लंबी निर्धारित करने के लिए विश्लेषित किया गया है। पत्तन को सलाह दी जाती है कि सीएचडी के लिए दरों की अगली समीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करते हुम अपलोड संशोधन और इसके प्रभाव को लेने से पहले संशोधित ऐनिंग मान और डेटम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए असरही कदम उठाए जाए।

- (v). केपीटी स्टीवडोर्स असोसिएशन (केपीएसए) और कुछ अन्य उपयोक्ता असोसिएशनों ने कुछ कारों के अभियांत्रिकत प्रहरान के लिए गैंगों की कल्पित बुकिंग, बाह्य लंगरगाह में प्रचालन करने वाले गैंगों के लिए अल्लान नींग प्रति दुक की अनिवार्य बुकिंग आदि के बारे में शिकायत की थी। पत्तन ने इस संबंध में अल्लान नींग प्रति दुक की अनिवार्य बुकिंग आदि के बारे में शिकायत की थी। पत्तन को सलाह दी जाती है कि यह पत्तन

अमोसिएशनों द्वारा जड़ाए गए इन मुद्रणों को प्रमुखतः से संबोधित करे और ऐसी पद्धति को समाप्त करे और कार्य करने की अपनी प्रणाली में पारदर्शिता लाए।?

कॉर्पोरेशन ने यह भी निवेदन किया है कि बीओटी प्रचालकों जैसे एवीजी कांडला कटेनर टर्मिनल लिमिटेड, आरएस इफार्स्ट के नामदों में गैंग बुक नहीं किए गए हैं क्योंकि पत्तन ने तत्सम्बन्धी बीओटी प्रचालकों के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका बत है कि बीओटी प्रचालकों से पत्तन द्वारा अर्जित राजस्व हिस्सेदारी लेवरों की नियुक्ति और प्राप्तशुल्क प्रभारों के स्थान पर है और इसलिए कॉर्पोरेशन ने सुझाव दिया है कि पत्तन को प्रत्येक पाली में एक गैंग प्रति हुक की लागत पर विदार करना चाहिए और इसे राजस्व हिस्सेदारी प्राप्ति से नामं छाहिए। अमोसिएशन द्वारा कही गई बात प्राप्तिक नहीं पाई गई है क्योंकि कॉर्पोटी संघर्ष बीओटी प्रचालकों के साथ उनके द्वारा किए गए अलग-अलग लाइसेंस करार द्वारा शासित है। इसके अलावा, बीओटी प्रचालकों ने समेकित कटेनर कार्गो/प्रहस्तन सेवा ऑफर की है जिसके लिए प्रशुल्क लागू दिग्निर्देशों के आधार पर अलग से निर्धारित किया गया है।

- (vi) अंडला पोर्ट कर्मचारी संघ (कॉर्पोरेशन) ने उल्लेख किया है कि कॉर्पोटी द्वारा वहनित ₹0.36 करोड़ का नुकसान लेवी को प्रति कामगाम प्रति पाली से प्रति टन आधार में परिवर्तित करने की ज़ज़ह से है। कॉर्पोरेशन ने भजदूरी और प्रतिशत लेवी प्रणाली की वसूली की पूर्ववर्ती प्रणाली में बदलियों का सुझाव दिया है। कॉर्पोरेशन द्वारा कही गई बात आधार वसान है और किसी विश्लेषण द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

यह उत्तरेखण्डीय है कि योग्य परिवहन मन्त्रालय ने अपने एन्डला सं. एलवी-13018/4/05-एन-॥ दिनांक 24 जून 2009 द्वारा सभी भारतीय न्यायों को स्टीवलोरिंग प्रचालनों के लिए प्रभारों पर आधारित टनभार अनीकृत करने की सलाह दी गई थी। पिछले प्रशुल्क आदेश एवं मौजूदा प्रस्ताव में स्टीवलोरिंग सेवाओं के लिए सीएचडी से लेवर की आपूर्ति के लिए वस्तुतः प्रति टन दर हेतु कॉर्पोटी का प्रस्ताव मन्त्रालय द्वारा प्रदत्त राशि के अनुसार है। टनभार से प्रतिशत आधार में लेवी का आधार परिवर्तित करने के लिए कॉर्पोरेशन का अनुरोध मन्त्रालय की सलाह की अनुसार नहीं है।

- (vii). (क) भार्ज 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.13 इस प्राधिकरण से अपेक्षा करता है कि प्रवालित प्रशुल्क निर्धारित किए जाने के समय विश्वास किए गए पूर्वानुमानों के सर्वभूमि में निर्धारित अवधि की समर्पित पर वास्तविक भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की जाए। यदि वारतविक निष्पादन में भिन्नता पूर्वानुमानों की तुलना में + या - 20 प्रतिशत देखी जाती है तो अनुरोधित किया जाने वाला प्रशुल्क भावी प्रभाव से समायोजित किया जाएगा।

- (ज) पिछले प्रशुल्क आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 में अनुमोदित सीएचडी से तैनात किए गए ऑन-लाइन लेवर के लिए समेकित दर वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानों पर आधारित थी। वर्ष 2011-12 के लिए लागत विधि का अनुमान लगाने के लिए पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुसरित दृष्टिकोण वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए अनीकृत किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए कॉर्पोटी द्वारा प्रेसित वारतविक आंकड़ों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं-

- (i). वर्ष 2011-12 के लिए वारतविक विधि प्रस्तुत करते समय, यथा अर्थात् भड़ा कर्त्तव्यालय और प्रशासन व्यय प्रशासन तथा अनुक्रमण व्यय, दिविज्ञप्ति व्यय, गूल्फास एवं कॉर्पोटी द्वारा सुविधारित किए गए हैं जैसा सीएचडी के लिए कॉर्पोटी के लेखापरीक्षण। वार्षिक लेखों में बताया गया है और इसलिए सिवाय इसके समीकरण किया गया है तो राशोंका विधि किए गए हैं जिन्हे नीचे ख्याल दिया गया है।

- (क). वार्षिक लेखों में ₹0.549156 लाख पर प्रतिवेदित कुल वारतविक वेतनों वाला भजदूरी लायत से, पत्तन ने वर्ष 2011-12 में प्रोटमूल ₹0.167576 लाख की ओपरेटराइम लायत के अलावा ₹0.3815.91 लाख पर वेतन वाला भजदूरी पर विवार किया है। पूर्ववर्ती प्रस्ताव दिनांक 2 जुलाई 2012 में, कॉर्पोटी ने अपने न्यायी एडल द्वारा यथा निर्णीत ₹0.3 करोड़ की वात वर्षों की अवधि में बांटने का प्रस्ताव किया है और शेष इसके दरमान के समान्य सशोधन में समाधेजित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था।

वर्तमान 21 फरवरी 2013 के संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन में ₹0.6 करोड़ के लिए ओपरेटराइम पर विवार किया है और इसे वात वर्षों की अवधि निर्धारित किया गया है।

लाख प्रतिवर्ष) में बाटने का प्रस्ताव किया है। जब वर्ष 2011-12 में ओवरटाइम व्यय को ₹० ३ करोड़ से ₹० ६ करोड़ करने के कारण ₹०४ गए थे तो पत्तन ने स्पष्ट किया था कि पूर्ववर्ती प्रस्ताव के बल एह महीनों के आँखों पर आशारित था जबकि फरवरी 2013 का संशोधित प्रस्ताव पूरे वर्ष के वारतापिक आंकड़ों पर विचार करता है।

वर्ष 2011-12 के वारतापिक आंकड़ों की जांच करने पर, यह देखा गया है कि ओवरटाइम सहित कुल बेतन तथा मजदूरी ₹० ५४९१.६६ लाख है जो पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमानित बेतनों तथा मजदूरी लागत की अपेक्षा ५६ प्रतिशत अधिक होंगे। वारतापिक बेतनों तथा मजदूरी में तीव्र वृद्धि के लिए प्रतिशत अधिक होंगे। वारतापिक बेतनों तथा मजदूरी में तीव्र वृद्धि के लिए मुख्य कारण ओवरटाइम तत्व में वृद्धि की वजह से है। जब कारण पूछे गए थे तो पत्तन ने स्पष्ट किया था कि सीएचडी गैंग के सापक्ष उनको आपूर्ति के तिए मांग की अधिकता, प्रति घंटा ओवरटाइम लागत में दृढ़ और मजदूरी संशोधन का प्रभाव ओवरटाइम लागत में तीव्र वृद्धि के लिए मुख्य कारण है।

पत्तन ने घोषित किया है कि पूर्ण तरह से दरों में भारी भिन्नता से दर्शाएँ के लिए, इसने ट्रेड द्वारा किए गए अनुरोध पर पाच वर्षों की अवधि में ओवरटाइम लागत के भाग को बांटने का परसार सहमति से निर्णय लिया था। केपीटी के चारों नडल का भत्ता था कि स्टीवडारों के लिए यह साध्य नहीं होगा कि इस अतिम उपयोक्ताओं पर डाला जाए, जिसके वाणिजिक परिणाम ही सकते हैं और विधिक समस्याएँ बढ़ सकती हैं और इसके अलावा स्टीवडार स्वयं भी भारी योड़ इहन कर नहीं सकते और इसलिए वर्ष 2011-12 की ओवरटाइम लागत को पांच वर्षों में बाटने का सहमति निर्णय लिया गया है।

(ख). निष्पादन की समीक्षा करते समय वर्ष 2011-12 की वारतापिक ओवरटाइम लागत के संबंध में निर्णय लिए जाने वाले दो विन्दु हैं -

(i). सीएचडी से संबंधित वर्ष 2011-12 के लिए वारिंग लेखों में प्रतिवेदित ₹० १६.७६ करोड़ की वारतापिक ओवरटाइम लागत में से, केपीटी ने सीएचडी गतिविधि में ₹० ६ करोड़ वर्ष २०१३-१४ के था और शेष ₹० १०.७६ करोड़ सामान्य राशीयन प्रस्ताव सुविळारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ii). ₹० ६ करोड़ की ओवरटाइम लागत को पांच वर्षों की अवधि में बांटना।

उपर्युक्त (i) के संदर्भ में, यह देखा गया है कि सामान्य प्रस्ताव से सीएचडी के लिए प्रोद्धृत ओवरटाइम के हिस्से पर दिक्षार करने के लिए केपीटी के प्रस्ताव से सामान्य संशोधन से सीएचडी में प्रति-सहायिकी प्रवाह होगा। तथापि, सामान्य संशोधन प्रस्ताव से ओवरटाइम लागत के हिस्से पर दिक्षार करने के लिए पत्तन का प्रयास ट्रेड से मांग पर आशारित बताया गया है और सीएचडी दरों में तीव्र वृद्धि के प्रभाव को कम करने का प्रयास है।

यह देखा गया है कि गतिविधियों/उप-गतिविधियों के बीच प्रति-रहायिकी का सदैव प्रवाह रहा है। यदि इस गतिविधि को सामान्य संशोधन प्रस्ताव का हिस्सा माना गया था तो इस गतिविधि में अन्य भत्तिविधियों से प्रति-सहायिकी के प्रवाह से नहीं बचा जा सकता था। उपर्युक्त स्थिति के नदेनजर, इसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव में ₹० १०.७६ करोड़ की अवशिष्ट ओवरटाइम लागत ₹० ६ करोड़ के लिए सीएचडी से ₹० ६ करोड़ की ओवरटाइम लागत वे उत्तरों को बदूल करने के लिए केपीटी के प्रस्ताव को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त बिन्दु (ii) के संबंध में, यह बताना प्रासारिक है कि पिछले निधारण के समय, ओवरटाइम लागत वेतनों की लागत के घटकों में से ५९% भाग गई थी। पाच वर्षों की अवधि में ओवरटाइम वाटने की कैपीटी द्वारा अधिकृत दृष्टिकोण पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुसारित दृष्टिकोण के अनुसार नहीं पाया गया है। इसलिए, ओवरटाइम लागत को पिछले प्रशुल्क आदेश में अंगीकृत दृष्टिकोण के अनुसार हमारे विश्लेषण में वर्ष 2011-12 के लिए वेतनों तथा मजदूरी लागत के हिस्से के रूप में माना गया है।

- (ग). कैपीटी ने वर्ष 2011-12 में मूल वेतन के 10 प्रतिशत पर परिवर्तनीय भंडारण भत्ता (वीडीए) में वृद्धि पर विचार किया गया है। चूंकि वर्ष 2011-12 के लिए सीएचडी हेतु प्रतिवेदित वास्तविक वेतन तथा मजदूरी पर विचार किया गया है जिसे वीडीए में वृद्धि के प्रभाव को पहले से लिया गया है, वर्ष 2011-12 के लिए अलग-से वीडीए में वृद्धि के प्रभाव का विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (घ). पत्तन ने वर्ष 2011-12 में वेतनों तथा मजदूरियों के 20 प्रतिशत की दर से 1 जनवरी 2012 से मजदूरी संशोधन के प्रभाव पर विचार किया है। पेश 13(xii) में यथा प्रतिवेदित पिछले प्रशुल्क संशोधन के दारान, 1 जनवरी 2012 से मजदूरी संशोधन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए अनुमानों के साथ वास्तविक आंकड़ों की तुलना करते समय, मजदूरी संशोधन का प्रभाव अनुमानों के साथ इस तरह की तुलना के लिए विचार नहीं किया गया है।
- (ङ). वास्तविक स्तर पर वर्ष 2011-12 के लिए पेशन भुगतान, उपदान भुगतान और कम्यूटेशन भुगतान कैपीटी द्वारा भेजा गया है। सोएचडी से संबंधित इन मदावों को कैपीटी के वार्षिक लेखों में अलग से नहीं दर्शाया गया है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि पेशन, उपदान तथा कम्यूटेशन पेशन के वास्तविक भुगतान मासिक पेशन बिल में पत्तन द्वारा अनुरक्षित सीएचडी के लिए अभिलेखों के आधार पर सुविचारित किए गए हैं। पिछले प्रशुल्क आदेश में इस प्राधिकरण ने इसी आधार पर इस संबंध में कैपीटी द्वारा प्रेषित अनुमानों पर विश्वास किया था। कैपीटी ने पुष्टि की है कि वास्तविक भुगतानों में पिछली अवधि से संबंधित बकाया राशियों को शामिल नहीं किया गया है। पत्तन द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के आधार पर, पत्तन द्वारा वथा निर्दिष्ट वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक पेशन, उपदान भुगतान तथा कम्यूटेशन भुगतान पर विश्वास किया गया है।
- (च). नियोजित पूँजी अर्थात् लागत विवरण में कैपीटी द्वारा सुविचारित नियंत्रित अचल परिस्पत्तियां रु 27,541,000 हैं। यह राशि सोएचडी के लिए परिस्पत्तियों के विवरण में कैपीटी द्वारा प्रेषित परिस्पत्तियों के नियंत्रित मूल्य से मामूली तौर पर भिन्न है। वर्ष 2011-12 के लिए नियोजित पूँजी रु 27,541,461 सुविचारित की गई है जैसा सीएचडी के लिए परिस्पत्तियों से संबंधित विवरण में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ भी संशोधित किया गया है।
- (छ). पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान प्रति गैंग औसत राजस्व लागत जू. ५३३ तथा उत्पादकता तुपारों के लिए 5 प्रतिशत तक दर्या विहार समय ००. अनुमानों के साथ इस तरह की तुलना के लिए वास्तविक आंकड़ा विश्लेषण करते समय इसी समायोजन पर विचार किया गया है।

(viii) पिछले प्रशुल्क आदेश में विश्वास किए गए अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2011-12 के लागत विवरण की प्रति अनुबंध-। इस में सलमन किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए सीएचडी के वास्तविक वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित अनुमानों के विश्लेषण का सार नीचे तालिकाबद्द किया गया है-
(रु0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	पिछले आदेश में		वास्तविक आंकड़े	मिन्ता % में (पूर्णकित)
		सुविचारित अनुमान	2011-12		
(i)	कुल व्यय (मूल्यहास सहित)	4037.78	5496.72	36%	
(ii)	आरओसीई	45.74	42.62	-7%	
(iii)	व्यय जमा आरओसीई की पूर्ति के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (i + ii)	4083.51	5539.34	36%	
(iv)	आनुपूर्ति कुल गैंग (रु. में)	23843	27554	16%	
(v)	अपेक्षित राजस्व प्रति गैंग (iii/iv)	17127	20104	17%	
(vi)	लागत कटौती/उत्पादकता सुधार/लेवर युक्तिकरण, आदि के लिए 5 प्रतिशत	856	1005	17%	
(vii)	प्रस्तुत व्यापक अपेक्षित राजस्व प्रति गैंग अपेक्षित राजस्व (v-vi)	16271	19098	17%	

सीएचडी में निवल घाटे के निर्धारण के लिए वर्ष 2011-12 में सीएचडी द्वारा अंजित वास्तविक राजस्व कुल वास्तविक व्यय जमा रखीकार्य आरओसीई से कम किया गया है और लागत कटौती/उत्पादकता के लिए 5 प्रतिशत पर भी विवाह किया गया है। वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सीएचडी में निवल घाटा नीचे दिया गया है-

		(रु0 लाखों में)
(i)	कुल व्यय जमा आरओसीई (उपर्युक्त तालिका में क्र.सं. (iii) से)	5539.34
(ii)	2011-12 में सृजित वास्तविक राजस्व (वास्तविक लेखा के अनुसार)	4023.77
(iii)	(निवल घाटा) (ii-i)	-1515.57
(iv)	घटाया पिछले आदेश में व्यथा सुविचारित लागत कटौती/उत्पादकता सुधार/लेवर युक्तिकरण, आदि के लिए 5 प्रतिशत कटौती	75.78
(v)	(iv) पर समायोजन के बाद निवल घाटा	-1439.79

पिछले प्रशुल्क आदेश के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक पैरामीटर में सुविचारित वित्तीय पैसामीटरों में भिन्नता का विश्लेषण नीचे किया गया है-

- (a) निवल आदेश में निर्धारित सीएचडी के लिए कागों-वार लेवी वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित ₹0 4,083.51 लाख के घाटे को पूरा करने के लिए था। इसके विपरीत, लेवी से केवीटी द्वारा अंजित वास्तविक आय तटनुकूली अपेक्षा के लिए ₹0 4023.77 लाख है जिसका अर्थ है पिछले आदेश में अनुमानित राजस्व अपेक्षा से - 14 प्रतिशत की कमी।
- (b) नीचे दरखास्त में भिन्नता गैंगों की अनुमानित संख्या से 16 प्रतिशत अधिक है।
- (c) वास्तविक नियोजित पूरी और उत्पाद प्रतिलिपि के सापेक्ष पिछले आदेश में सुविचारित अनुमानों में भिन्नता 7 प्रतिशत है।
- (d) वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक राजस्व अपेक्षा ₹0 5,539.34 लाख परिणामित होती है जो ₹0 4,083.51 लाख की अनुमानित राजस्व अपेक्षा से 36 प्रतिशत अधिक है। यह मुख्यतः सीएचडी के समग्र व्ययों में टेस्टी गैंग भारी भिन्नता के कारण है जो अनुमानित स्तर से 36 प्रतिशत अधिक है। यह भिन्नता सामान्य संशोधन प्रस्ताव से केवीटी द्वारा कवर किए जाने के लिए प्रतिवर्षित ₹0 10.76 करोड़ के गरणादेक ओवरटाइम व्यय के अतिरिक्त हिस्से के बाद है। वास्तविक अनुमानों के सापेक्ष अनुमानित व्ययों में भारी वृद्धि वर्ष 2007 के मनदूरी संशोधन के कारण बेतनों तथा प्रतिवर्षित, पेशनाश, उपदान मुग्धतानों में वृद्धि की वजह से है।

रु0 5,534.34 लाख की वास्तविक राजस्व अपेक्षा के विपरीत, सीएचडी से अंजिंल वास्तविक राजस्व रु0 4023.77 लाख है जिसके परिणामस्वरूप सीएचडी में घाटा है।

- (ड). यहां पर यह बताना प्रासादिक है कि हालाकि गाँवों की संख्या और नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ में भिन्नता +/-20 प्रतिशत से कम है, वास्तविक समग्र व्ययों में भिन्नता अनुमानित स्तर की अपेक्षा 36 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, राजस्व अपेक्षा जो वास्तविक रूप से दर निर्धारित करने के लिए आधार तैयार करती है अनुमानित स्तर की अपेक्षा 36 प्रतिशत अधिक है। यूकी इन दो पैरामीटरों में भिन्नता प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए भविष्य प्रशुल्क में सीएचडी में घाटे के समायोजन के लिए मामला है।

पत्तन ने वर्ष 2011-12 के लिए रु0 9.17 करोड़ पर इसके द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण घाटे और पाच वर्षों की अवधि में बाटे जाने वाले रु0 6 करोड़ अर्थात् रु0 1.20 करोड़ वार्षिक अनुवर्ती वर्ष 2012-13 में कुल 10.37 करोड़ की ओवरटाइम लागत की आशिक वसूली और प्रस्तावित दर पर पहुँचने के समय गणना की गई है।

यदि भौतिक/वित्तीय पैरामीटरों में अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों में भिन्नता (+)/(-) 20 प्रतिशत अधिक हो तो 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.13 भविष्य प्रशुल्क में सुविचारित किए जाने वाला घाटा/अधिकारों के 50 प्रतिशत के समायोजन की अनुमति देता है जो कि 100 प्रतिशत जैसाकि पत्तन द्वारा दावा किया गया है। दिशानिर्देशों में प्रावधान के अनुसार सीएचडी में निर्धारित वास्तविक घाटे का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 719.90 लाख (रु0 1439.79 लख का 50 प्रतिशत) भविष्य प्रशुल्क में समायोजन के लिए सुविचारित किया गया है।

- (ix) हमारी सलाह पर, पत्तन ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अनुमानों के साथ अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 अवधि के लिए नौ महीनों के वास्तविक आंकड़ों पर यथानुपात आधार पर वर्ष 2012-13 के लिए अनुमान भेजे हैं; वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए केपीटी द्वारा प्रेषित किए गए अनुमानों में किए गए विश्लेषण/संशोधन अनुवर्ती अनुच्छेदों में स्पष्ट किए गए हैं।

- (x) केपीटी ने अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक नौ महीनों में सीएचडी द्वारा प्रहसित वास्तविक यातायात के आधार पर वर्ष 2012-13 के लिए सीएचडी द्वारा प्रहसित किए जाने वाले अनुमानित 63.37 लाख टन ब्रेक वर्ल्क और 205.54 लाख टन बल्क कार्गो कुल 268.91 लाख टन का अनुमान लगाया है। वर्ष 2012-13 के लिए केपीटी द्वारा यथा अनुमानित यातायात पर विश्वास किया गया है।

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए, पत्तन ने 2012-13 के समान स्तर पर यातायात का अनुमान लगाया है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए केपीटी द्वारा अनुमानित ताप क्षेत्रों तथा उर्वरक जैसी कुछ कारों मदों का यातायात इन वर्षों के लिए सामान्य संशोधन प्रस्ताव में केपीटी द्वारा पूर्वानुमानित यातायात के अनुसार पाए गए हैं। अन्य कारों के लिए, विस्तृत घटक-वर विस्तृत ब्रेक अप सामान्य संशोधन प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है। यह देखा गया है कि पत्तन ने सीएचडी के यातायात में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया है। यह सामान्य संशोधन प्रस्ताव के अनुसार पाया गया है जहां पत्तन ने वर्ष 2013-14 के यातायात पूर्वानुमानों में वर्ष 2014-15 में पत्तन के समग्र यातायात में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया है।

इस कार्यालय के प्रयोजन के लिए, केपीटी द्वारा यथा पूर्वानुमानित सीएचडी का यातायात पर विश्वास किया गया है और विचार किया गया है। यदि पत्तन द्वारा अनुमानित यातायात पर विश्वास करते हुए केपीटी का कोई अग्रावश्यक लाभ होता है तो अग्री प्रशुल्क समीक्षा के समय ऐसा अनावश्यक लाभ/पूँजी सीएचडी के प्रगल्भ प्रशुल्क संशोधन में पूर्ण समायोजन के लिए सुविचारित किया जाएगा।

- (xi). केपीटी ने वर्ष 2012-13 के लिए रु0 3974.28 लाख के देनामो और मजदूरियों लागत का अनुमान लगाया है जोकि पूर्ण वर्ष के लिए यथानुपातित अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 अवधि के लिए नौ महीनों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। पत्तन ने वर्ष 2012-13 के लिए अलग-अलग वेतनों तथा भजदूरी के 20 प्रतिशत पर मजदूरी संशोधन के प्रभाव का अनुमान लगाया है। अनुवर्ती वर्ष 2013-14 के लिए, पत्तन ने 2012-13 के अनुमानों में 27 प्रतिशत वृद्धि पर विचार किया है जिसमें 20 प्रतिशत की दर से मजदूरी संशोधन का प्रभाव शामिल है।

वर्ष 2014–15 के लिए, पत्तन ने पिछले वर्ष के अनुमानों में 5.8 प्रतिशत तक इस लागत मद में वृद्धि की है। इसके अलावा, पत्तन ने बीड़ीए में 25 प्रतिशत त्रैगासिक वृद्धि के प्रभाव की गणना करने के लिए वर्ष 2012–13 से 2014–15 के प्रत्येक वर्ष के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत पर परिवर्तीय महंगाई भत्ता में वृद्धि पर विचार किया है। वेतनों के अनुमान और केपीटी द्वारा अनुमानित मजदूरी संशोधन लागत का विवरण किया गया है और जहां कहीं आवश्यक समझा गया है संशोधन किया गया है जैसाकि नीचे स्पष्ट किया गया है—

(क) पत्तन ने नौ महीनों के वास्तविक वेतनों और मजदूरी लागत जिसमें ओवरटाइम लागत शामिल बताए गए हैं के यथानुपात में वर्ष 2012–13 के लिए वेतनों और मजदूरियों का अनुमान लगाया है। केपीटी ने बताया है कि मांग की वजह से लेबर ओवरटाइम पर बुक किया जाना अपेक्षित होता है और वह न्यूनतम ओवरटाइम इस प्रस्ताव में सुविचारित किया गया है। यह देखा गया है होता है और वह न्यूनतम ओवरटाइम पर बुक किया जाना अपेक्षित है। यह देखा गया है कि वर्ष 2011–12 में प्रतिवेदित ₹ 16.76 करोड़ के वास्तविक ओवरटाइम के विपरीत, नौ महीनों के वास्तविक आकड़ों के आधार पर वर्ष 2012–13 में सुविचारित ओवरटाइम ₹ 6 करोड़ है। के वास्तविक आकड़ों के आधार पर वर्ष 2012–13 में सुविचारित ओवरटाइम ₹ 6 करोड़ है।

(ख) कामगारों के वेतनों तथा मजदूरी लागत 1 जनवरी 2012 से संशोधन किया जाना देय है। पत्तन ने वेतनों तथा मजदूरी लागत के 20 प्रतिशत पर वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मजदूरी संशोधन के प्रभाव पर विचार किया है और इसे अलग प्रविष्टि के रूप में दर्शाया है। वर्ष 2013–14 और 2012–13 के लिए, राज्य स्तर पर मजदूरी संशोधन का प्रभाव पत्तन द्वारा वेतनों तथा मजदूरी 2014–15 के लिए हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 1 जनवरी 2012 से देय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मजदूरी संशोधन का प्रभाव मुम्बई पत्तन न्यास और न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास के सामान्य संशोधन प्रस्तावों में 15 प्रतिशत पर सुविचारित किए गए थे। यह भी 2007 के पूर्ववर्ती गजदूरी संशोधन के सदर्भ में महापत्तन न्यासों के अन्य सामान्य संशोधन मामलों में स्वीकृत किए गए मजदूरी संशोधन प्रभाव के अनुसार है।

1 जनवरी 2012 से देय मजदूरी संशोधन का प्रभाव महापत्तन न्यासों के पूर्ववर्ती प्रशुल्क मामलों में लिए गए निर्णय के अनुसार वेतनों तथा मजदूरी लागत के 15 प्रतिशत पर स्वीकार किया गया है। यह स्वीकार करना पत्तन ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ब्रेकअप नहीं भेजा है। यह स्वीकार करना होगा कि सीएचडी एक लेबर गहन प्रभाग होने के नाते, यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा। मजदूरी संशोधन कि वेतनों तथा मजदूरी लागत में कर्मचारियों की ये दो श्रेणियां शामिल होंगी। मजदूरी संशोधन का प्रभाव वर्ष 2012–13 से अनुमानित वेतनों तथा मजदूरी लागत के 15 प्रतिशत पर सुविचारित किया गया है। अनुवर्ती वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए, 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि वर्ष किया गया है। 2013–14 में निर्णीत किए जाने वाले प्रशुल्क मामलों में इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जाने का निर्णय किए जाने वाली वार्षिक वृद्धि के अनुसार स्वीकृत किया गया है।

तदनुसार, वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लिए मजदूरी संशोधन का प्रभाव क्रमशः ₹ 0 596.14 लाख, ₹ 0 637.88 लाख और ₹ 0 686.52 लाख सुविचारित किया गया है। हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में, मजदूरी संशोधन का प्रभाव तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक प्रविष्टि के स्पष्ट में दर्शाया गया है।

(ग) केपीटी द्वारा दाखिल किया गया लागत विवरण दर्शाता है कि पत्तन ने तत्सम्बन्धी पिछले वर्ष के अनुमानों से वर्ष 2013–14 और 2014–15 में 5.8 प्रतिशत तक वेतनों तथा मजदूरी लागत में वृद्धि की है। 5.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के अलावा, पत्तन ने वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत पर परिवर्तीय महंगाई भत्ता (बीड़ीए) में वृद्धि पर भी विचार किया है।

पत्तन ने बताया है कि प्रशुल्क संशोधन में अन्य लागत मर्दों के लिए लागू वार्षिक वृद्धि पत्तन के गोदी कामगारों पर लागू नहीं की जा सकती क्योंकि बीड़ीए में वृद्धि सीधे तौर पर उपभोक्ता मूल्य सुवधाक (ओटोगिक डीए प्लाइटस) पर आधारित है। पिछले तीन वर्षों के लिए बीड़ीए में औसत वार्षिक वृद्धि 12 प्रतिशत होना बताया गया है। इसके मद्देनजर, मौजूदा महंगाई रुझानों पर विचार करते हुए और बीड़ीए में 25 प्रतिशत की त्रैगासिक वृद्धि पर विचार करते हुए भी, पत्तन

के यह अधिकार देना होया कि पत्तन द्वारा यावाकृत बीड़ीर में १० प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है।

भार्च २००५ के प्रश्नुक दिशानिर्देशों का खड २६। अपेक्षा करता है कि वर्ष २०१२-१३ के दौरान भी यूरोपीय और अनुमानों के अनुसार होने याहिए और सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूखकरके दौरान बढ़ने याहिए। यहां पर बताना प्रासंगिक है कि दिशानिर्देश पत्तन में कार्गो प्रमाणन का लिए वार्षिक वृद्धि स्थीकृत किए जाने हेतु कोई भिन्न कार्यपद्धति निर्धारित नहीं करता है। दिशानिर्देश पत्तन न्यास, न्यू मेगलूर पत्तन न्यास आदि जैसे अन्य महापत्तन द्वारा ने कार्गो प्रक्रिया के लिए दर्दे प्रासंगिक वर्ष में निर्णीत प्रश्नुक मानवों के लिए इस प्रतिशत द्वारा द्वय विकारिक वृद्धि स्थीकार करते हुए निर्धारित की गई है। इस प्रासंगिकरण में पृष्ठांत के प्रमाण का उपयोग करने के लिए वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में निर्णीत किए जाने वाले सभी प्रश्नुक मानवों ने उपर्युक्तों के लिए ७ प्रतिशत के अधिकतम वृद्धि कारक को स्थीकार करने का निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में, वर्ष २०१३-१४ और २०१४-१५ के लिए वेतनों तथा मजदूरीयों के अनुमान निर्धारित द्वारा लागू किए गए ५८ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के विपरीत तत्सम्बन्धी पिछले वर्ष के वेतनों तथा मजदूरी लागत के समग्र अनुमानों पर ७ प्रतिशत वार्षिक की वार्षिक वृद्धि द्वारा कठत तुम्हारा नियांत्रित किए गए हैं।

जैसाकि पहले बताया गया है, कार्गो प्रहसन प्रभाग एक लेवर गहन हैकाहिं है और इन्हें उपर्युक्त लागत तत्व निर्धारित किए गए हैं और यातायात से भिन्न होने की समाझन नहीं है। किंतु ये मामले में, पत्तन ने सीएचडी द्वारा प्रहसित किए जाने वाले कार्गो के यातायात में निर्णीत वृद्धि के अनुमान नहीं लगाया है।

(घ) व्यय की अन्य मर्दे अर्थात् भंडार, कार्यालय तथा प्रशासन व्यय, प्रधालन तथा अनुशासन व्यय, वर्ष २०१२-१३ के लिए घिकित्सा व्यय नौ महीनों के वास्तविक आकड़ों के आधार पर कठीन है। वर्ष २०१२-१३ के लिए इन व्ययों के अनुमानों पर विश्वास सिया गया है।

अनुबर्ती दो वर्ष २०१३-१४ और २०१४-१५ के लिए, कंपीटी ने ६.५ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि द्वारा करते हुए इन व्ययों का अनुमान लगाया है। जैसाकि पहले बताया गया है, इस प्रासंगिकरण में वर्ष २०१३-१४ में निर्णीत किए जाने वाले महापत्तनों तभी निजी टम्पिनलों के सभी प्रश्नुक मानवों व्यय पूर्वानुमानों के लिए ७ प्रतिशत का वृद्धि कारक अन्वेषक करने का निर्धारित है। अनुभव ७ प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि कारक इन लागत मर्दों की प्रत्येक मर्द का अनुभव लगाये के लिए लागू किया गया है।

(इ) पत्तन ने वर्ष २०१२-१३ से २०१४-१५ के लिए रु० १० लाख प्रतिवर्ष की दर से मूल्यांकन का अनुमान लगाया है; यह देखा गया है कि पत्तन ने इस अवधि के दौरान रोएचडी से अन्य सकल प्रखंड में किन्हों संवर्धनों/हटाए जाने का प्रताव नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, वर्ष २०१२-१३ से २०१४-१५ के लिए मूल्यांकन २०११-१२ के वास्तविक आकड़ों (अधारों) कंपीटी द्वारा सुविचारित रु० 10,00,000 की बजाय रु० 9,05,441 के स्तर पर सुविचारित किया गया है।

(इ) पत्तन ने वर्ष २०१२-१३ के लिए उपदान भुगतान, पेशन भुगतान और पेशन भुगतान का क्रमशः रु० ३७१,४७ लाख, रु० ९२२,७४ लाख और रु० १८७,४० लाख का अनुमान लगाया है। वर्ष २०११-१२ के वास्तविक भुगतानों की अपेक्षा ४६.४ प्रतिशत अधिक भाग दृढ़ है।

पेशन भुगतानों, उपदान भुगतानों तथा पेशन भुगतान के कम्प्यूटेशन से अधिक लगाये जाने वाले प्रहरतन प्रभाग के लिए वार्षिक लेखों में अलग से नहीं दर्शाए गए हैं। पत्तन ने युरिं जैसे है, वर्ष २०१२-१३ के दौरान सीएचडी कामगारों को वास्तविक पेशन भुगतानों उपदान लगा दिया है। भुगतान सीएचडी के लिए पत्तन द्वारा अलग से व्यवस्थित रिकार्डों के आधार पर वार्षिक वृद्धि दर गए हैं और यह भी पुष्टि की है कि इसमें पिछली अवधि से संवधित कोई वृक्षालय वासियों नहीं की गई हैं। पत्तन ने बताया है कि वर्ष २०१२-१३ के लिए अनुमान भर्जन रा दैवतिर २०११ तक नौ महीनों की अवधि के लिए वर्ष २०१२-१३ में किए गए वास्तविक भुगतानों पर अनुमान और इसने १ जनवरी २०१२ से मजदूरी संशोधन का प्रभाव २० प्रतिशत सुविचारित किया है। वर्ष २०१२-१३ भुगतानों के कम्प्यूटेशन के अनुमान वेतनों तथा नजदूरियों में तरीका दिए गए वर्ष २०१२-१३

प्रभाव के अनुसार 15 प्रतिशत पर मजदूरी संशोधन के प्रभाव को संशोधित किए जाने को छोड़कर विचार किए गए हैं।

पत्तन द्वारा प्रेषित विस्तृत गणना से, यह देखा गया है कि वर्ष 2013714 और 2014-15 में पत्तन द्वारा प्रेषित विस्तृत गणना से, यह देखा गया है कि वर्ष 2013714 और 2014-15 में (मजदूरी संशोधन के प्रभाव को छोड़कर) उपदान भुगतानों और पेशन भुगतानों के कम्पूटेशन तत्संबंधी पिछले वर्षों के अनुमानों से कम अनुमानित किए गए हैं। तथापि, पेशन भुगतान तत्संबंधी पिछले वर्षों के अनुमानों से वर्ष 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 11.6 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत द्वारा वृद्धि किए जाने का अनुमान लगाया गया है। पत्तन ने बताया है कि इसमें 3 प्रतिशत द्वारा वृद्धि किए जाने का अनुमान लगाया गया है। पत्तन ने बताया है कि इसके अलावा, पत्तन ने इन भुगतानों के प्रत्येक भुगतान पर 20 प्रतिशत की दर से मजदूरी संशोधन के प्रभाव पर विचार किया है।

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए केपीटी द्वारा लागू किए गए पेशन भुगतान के अनुमानों में वृद्धि 7 प्रतिशत की स्थीकार्य सीमा से अधिक है। इसलिए, वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए पेशन भुगतान के अनुमानों में वार्षिक वृद्धि तत्संबंधी पिछले वर्षों के अनुमानों से 7 प्रतिशत वार्षिक पर सीमित किया गया है। वेतनों तथा मजदूरियों के लिए स्थीकृत मजदूरी संशोधन के प्रभाव के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक पेशन भुगतानों, उपदान भुगतानों तथा कम्प्यूटेशन भुगतान पर मजदूरी संशोधन का प्रभाव 15 प्रतिशत स्थीकृत किया गया है।

चूंकि सीएचडी से संबंधित पेशन तथा उपदान भुगतान केपीटी के वार्षिक लेखों में अलग से नहीं दर्शाएँ गए हैं, इसलिए पत्तन को सलाह दी जाती है कि व्ययों के दोहराव से बचने के लिए अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में इन शीर्षों पर व्यय को अलग रखा जाए।

- (xii). केपीटी ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 के प्रत्येक वर्ष के लिए गैंगों की 28139 सख्त्या का अनुमान लगाया है। इसपर विश्वास किया गया है और प्रति गैंग राजस्व अपेक्षा पर पहुँचने के लिए विचार किया गया है।

- (xiii). केपीटी ने 1 अप्रैल 2012 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सीएचडी की दरों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। केसए और अन्य उपयोक्ता असोसिएशनों ने 1 अप्रैल 2012 से पूर्वव्यापी प्रभाव से दरों के निर्धारण हेतु केपीटी के प्रस्ताव पर सम्मत आपत्ति उठाई है। उहोने निवेदन किया है कि पूर्व देयताएं आयातकों / निर्यातकों से बसूल नहीं किए जा सकते जब पोत एक बार उत्तराई/लदाई प्रचालन पूरा कर लेता है। उसी समय ट्रेड पूर्व भिन्न देयताओं के बोझ को वहन नहीं कर सकता क्योंकि नई दरों का निर्धारण का प्रभाव पूर्वव्यापी है।

- इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2012 में कार्गो प्रहस्तन प्रभाग की दरों की वैधता को विस्तारित करते समय निर्णय दिया था कि 1 अप्रैल 2012 से प्रशुल्क के पूर्वव्यापी संशोधन के लिए पतन का प्रस्ताव इस मामले की कार्यवाही के दौरान केपीटी द्वारा प्रेषित किए जाने वाले औचित्यों के आधार पर सुविचारित किया जाएगा।

- 1 अप्रैल 2012 से पूर्वव्यापी संशोधन के लिए मांग करने वाले अपने प्रस्ताव के संदर्भ में, केपीटी ने निवेदन किया है कि सीएचडी प्रभाग को मुख्यतः गोदी कामगारों के वेतनों तथा मजदूरियों में भारी बढ़ोतारी की वजह से रु 34.12 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। पत्तन ने आगे यह निवेदन भी किया है कि पिछले आदेश में सीएचडी दर के लिए प्रति टन दर के निर्धारण के दौरान, ₹ 850/- और ₹ 1084/- प्रति व्याचारित घोषित दर 01-04-2006 से 31-12-2006 तक 9 महीने की अवधि के दौरान केडीएलबी के कार्य परिणामों के

आधार पर पूरी तरह से तब्दील हो गई है। इसके अलावा, केपीटी ने सीएचडी के पिछले प्रशुल्क निर्धारण में 1 जनवरी 2007 से भवित्वमें राशीधन प्रभाव को लागू किए जाने को नहीं लिया था। सभी उपर्युक्त कारकों का प्रभाव सीएचडी नियमोंमें भारी घाटे में बदल गया है और सीएजी ने इस सब्द में प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की हैं।

2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 328 के अनुसार, टीएमपी द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला सशोधित प्रशुल्क भारी प्रभाव से होगा। पिछली देयताओं के एकत्रण के बारे में कैसे और अन्य उपयोगका असारिंगेशन द्वारा स्पष्ट किए गए कारणों के मददेनजर कि यदि दरे पूर्वव्यापी प्रभाव से सशोधित की जाती है और प्रशुल्क में भारी प्रभाव के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देशों में विशिष्ट खड़ के मददेनजर भी, यह प्राधिकरण पूर्वव्यापी संशोधन के लिए गए अनुरोध पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है।

उक्तपूर्व तरीं समय गोपनीयों में भारी घाटे के कारणों को स्पष्ट करते हुए केपीटी द्वारा किए गए विवरण के मुताबिक यह तरीं नहीं प्रभाव लिया गया है कि पत्तन से यह अपेक्षा की जाए कि वह वर्ष 2012-13 में वलन वाले प्रशुल्क दिशानिर्देश वर्तमान वर्तन में पूर्वव्यापी की वजह से सीएचडी में होने वाले घाटे को बहन कर जा सकता है और विवरण द्वारा दिया गया समय वर्ष 2012-13 में अनुमानित सम्पूर्ण घाटे पर समायोजन करने के लिए उपयोग है।

परं यद्यपि यह गोपनीयों के मददेनजर, वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित सम्पूर्ण घटा विश्लेषण के अनुपर्याप्ती भाग में वथा उपयोगिता के लिए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजन के लिए सुविचारित किया गया है।

वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक आकड़ द्वारा मामगम के विश्लेषण के समय उपलब्ध नहीं है; केपीटी द्वारा योग्यता किए गए अनुमान इस विश्लेषण के पिछले हिस्से में वथा स्पष्ट किए गए कुछ सशाधनों के अधीन विवरित किए गए हैं। यूके वर्ष 2012-13 के लिए विश्लेषण अनुमानों के अधार पर किया जाता है, उर्वरोपीय वास्तविक आकड़ भाशाधन कार्यवाही के दौरान समीक्षा किए जाने के अधीन होगी। यदि विवरण उपशुल्क दिशानिर्देशों में विशिष्ट रूप से विवरण के लिए विश्लेषण के लिए अधिक पापा जाता है तो इसे प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2013 के अनुसार अगले प्रशुल्क वैधता वर्तन में समायोजित किया जाएगा।

(xvi) यह इस वास्तविक आकड़ द्वारा स. टीएमपी/37/2007 के पिछीटी दिनांक 9 अप्रैल 2012 द्वारा 31 मार्च 2012 के बाद 30 अग्र 2012 तक ऑग-वोर्ड लेबर के लिए दरों की वंदेता को विस्तारित किया है और उपरोक्त दिशानिर्देश इस शर्त के अधीन 28 फरवरी 2013 तक स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए इस वास्तविक आकड़ के दौरान केपीटी को प्रोट्रॉफ्ट होने वाला अतिरिक्त अधिशेष, यदि काउंसल विकास के लिए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णता समायोजित किया जाएगा।

(xvii) पत्तन के 2011-12 के पूर्व अधिक घाटे को छोड़कर वर्ष 2012-13 के लिए कुल लागत जमा गयी तरीं रु 6,498.07 लाख का अनुमान लगाया है। नीं महीनों के वास्तविक आकड़ों के अधार पर रु 5,380.53 पर सीएनडी से अनुमानित राजस्व पर विचार करने के बाद, पत्तन ने वर्ष 2012-13 के लिए रु 1105.55 लाख के निवल घाटे का अनुमान लगाया है।

केपीटी ने वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित रु 1105.55 लाख और रु 120 लाख के आवरटाइम व्यष्ट के बादन की दूसरी फैसला कुल रु 1225.54 लाख वर्ष 2013-14 में सम्पूर्ण घाटे के समायोजन की काम की है। वर्ष 2014-15 में, पत्तन ने वर्ष 2011-12 से सब्दित आवरटाइम वाले के लिए रु 120 लाख के समायोजन पर विचार किया है। वर्ष 2011-12 से सब्दित आवरटाइम के सव्यवहार पूर्वव्यापी अनुच्छेदों में दिए गए विश्लेषण में स्पष्ट किया गया है और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए घाटे का समायोजन तालिकाबद्ध किया गया है और इस विश्लेषण के अनुपर्याप्ती हिस्से में स्पष्ट किया गया है।

(xviii) विश्लेषण के आपानी हिस्सों में स्पष्ट किए गए संशोधनों के अधीन हमारे द्वारा तैयार किए गए अपेक्षाकों के लिए लागत विवरण वर्ष 2012-13 के लिए कुल लागत जमा आरओरीई रु 6,988 के लिए दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए केपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व रु 5,380.53 लाख की लागत फैला के बाद, नामता विवरण वर्ष 2012-13 के लिए रु 708.22 का निवल घाटा दर्शाया गया है।

(xix) विवरण पशुल्क अधिकारी, उत्पादकता सुधार/लेबर युक्तिकरण के लिए सारांश अपेक्षा में 5 प्रतिशत की कटौती दिखाई गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए कि मैनिंग मान जगी तक पूरी तरह अद्यावधि नहीं दिखा गया है और कलिया गैंग बुकिंग पत्तन में जारी है, अंदि इन मुद्दों को लापूर करने के लिए अनुमानित राजस्व अपेक्षा में 5 प्रतिशत की कटौती उत्पादकता सुधार/लेबर युक्तिकरण और लागत कटौती के लिए वर्ष 2012-13 से 2014-15 में दिखाई गई है। 5 प्रतिशत की एसी कटौती पिछले प्रशुल्क आदेश में भी सुविचारित की गई थी, जैसाकि पहले बताया गया है।

(३) ५ प्रतिशत के समायोजन के बाद वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक निवल घाटा ₹ 672.80 लाख होता है।

विश्लेषण के पूर्ववर्ती भाग में स्पष्ट किए गए कारणों से, वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित सम्पूर्ण घाटा निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजन के लिए सुविचारित किया गया है।

(च) सक्षेप में, भविष्य प्रशुल्क में समायोजन के लिए सुविचारित वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए सीएचडी हेतु घाटा नीचे दिया गया है:-

(₹० लाखों में)

वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित वास्तविक निवल घाटा का 50 प्रतिशत	719.90
(₹० 1439.79 लाख * 50%)	
वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित घाटा का 100%	672.80
प्रशुल्क में समायोजन के लिए निर्धारित कुल घाटा	1392.70

इस प्रशुल्क चक्र में लेनी के निर्धारण के लिए सुविचारित लागत स्थिति दो वर्षों अर्थात् 2013-14 और 2014-15 के लिए है। इसपर विचार करते हुए कि आदेश अक्टूबर 2013 से लागू होगा, सशोधित प्रशुल्क तीन वर्षों के सामान्य प्रशुल्क चक्र के विपरीत अठारह महीनों की अवधि अर्थात् अक्टूबर 2013 से मार्च 2015 के लिए लागू होगा।

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रशुल्क में उत्तार-चढ़ाव को सुगम बनाने के लिए और एक चक्र में प्रशुल्क को कृत्रिम रूप से नीचे लाने से बचने के लिए, अन्य महापत्तन न्यासों और निजी टमिनलों जहां निर्धारित किया गया अधिशेष पर्याप्ति था के मामलों में इस प्राधिकरण ने पांच वर्षों की अवधि में पूर्व अधिशेष के समायोजन का निर्णय लिया है।

मौजूदा गामले में, प्रशुल्क में तीव्र वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए और दो चक्रों के बीच प्रशुल्क में अनावश्यक उत्तार-चढ़ाव से बचने के लिए, वर्ष 2011-12 और 2012-13 में निर्धारित घाटा प्रशुल्क में अनावश्यक प्रशुल्क चक्र जो अक्टूबर 2013 से अठारह महीनों की अवधि के लिए है ₹ 1392.70 लाख मौजूदा प्रशुल्क चक्र जो अक्टूबर 2013 से अठारह महीनों की अवधि तक सीमित करने की बजाय तीन वर्षों की अवधि के सामान्य प्रशुल्क वैधता चक्र में समायोजित किया गया है।

तदनुसार, ₹ 696.35 लाख इस प्रशुल्क चक्र में अठारह महीनों अर्थात् अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2015 तक समायोजित किया गया है और ₹ 696.35 लाख का अवशिष्ट घाटा अगले प्रशुल्क चक्र के प्रथम अठारह महीनों में समायोजन के लिए बाटा जाएगा।

(xv). केंद्रीय द्वारा दाखिल किया गया सीएचडी का लागत विवरण उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार संशोधित किया गया है। कार्गो प्रहस्तन प्रभाग का लागत विवरण अनुबंध-II रूप में संलग्न किया गया है। सशोधित लागत विवरण में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अनुमानित राजस्व अपेक्षा का सार नीचे दिया गया है-

(₹० लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14 (अनुमान)	2014-15 (अनुमान)
(i).	कुल अनुमानित व्यय	6,583.26	7,152.03
(ii).	16% आरोसीई	39.72	38.27
(iii).	राजस्व अपेक्षा (i+ii)	6,622.98	7,190.30
(iv).	घटाया लागत कटौती/उत्पादकता सुधार के लिए समायोजित 5 प्रतिशत	331.14	359.51
(v).	जोड़ः वर्ष 2011-12 और 2012-13 और अक्टूबर 2013 से आगे वर्ष 2013-14 (6 महीने) और 2014-15 के लिए पूर्ण घाटे का समायोजन	232.11	464.23
(vi).	अनुमानित राजस्व अपेक्षा (iii-iv+v)	6,523.95	7,295.02
(vii).	कुल आपूर्ति गैंग (स.)	28,139	28,139
(viii).	राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग (₹० / गैंग)	23,185	25,925
(ix).	औसत राजस्व अपेक्षा (₹० / गैंग)		24,555

(xvi). (क) पत्तन ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 26,735, वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 60,8506 और वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 25,995 प्रति गैंग औसतन ₹ 27,079 प्रति गैंग वर्ष 2012-13 पहले ही खत्म हो चुका है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अनुमानित औसत राजस्व अपेक्षा ₹ 24,555 प्रति गैंग कार्गो वार प्रति दर पर पहुंचने के लिए सुविचारित किया गया है।

(ख). केपीटी ने अनुमानित राजस्व अपेक्षा प्रति टैग की पूर्ति करने के लिए वस्तुवार दर पर पहुंचने के लिए विस्तृत गणना भेजी है। वस्तुवार प्रति टन दर पर पहुंचने के लिए केपीटी द्वारा आगीकृत कार्यपद्धति संशोधित अनुमानित राजस्व अपेक्षा पर आधारित संशोधित दर पर पहुंचने के समय अनुसरित की गई है।

पत्तन ने ताप कोयला और लौह अयस्क के सिवाय प्रति टन दर पर पहुंचने के लिए तटीय रूप में 10 प्रतिशत कार्गों और विदेशी रूप में कार्गो मात्रा के 90 प्रतिशत का अनुमान लगाया है जहाँ इसने सम्पूर्ण कार्गों के विदेशी होने का अनुमान लगाया है। कार्गो और केपीटी द्वारा यथा पूर्वानुमानित इसकी हिस्सेदारी पर विश्वास किया गया है।

(ग). लौह अयस्क और ताप कोयला के लिए क्रमशः ₹ 22.59 और ₹ 27.33 हेतु केपीटी द्वारा प्रस्तावित दर इसकी गणना से मेल नहीं खाती है। इन दो कार्गो मदों के लिए प्रस्तावित दर पर राजस्व सूजन पत्तन द्वारा इन कार्गो श्रेणी से अनुमानित राजस्व अपेक्षा की अपेक्षा अधिक परिणामित होगा। पत्तन की गणना में कुछ असंगतता दिखाई देती है जिसे हमारी गणना में सही किया गया है। हमारी गणना में, दर इस तरह निर्धारित की गई ताकि कार्गो मदों के लिए अनुमानित संशोधित राजस्व अपेक्षा से मिलान किया जा सके। बल्कि कार्गो और ब्रेक बल्कि कार्गो के लिए प्रति टन दर पर पहुंचने के लिए कार्य पत्रक क्रमशः अनुबंध-III (क) और (ख) रूप में संलग्न किया गया है।

(घ). पिछले प्रश्नुल्क आदेश में अन्य कार्गो मदों में सोडा एश, सीमेट, ऑयल एक्सट्रेक्शन्स (ब्रेक बल्क) के लिए प्रति टन दर निर्धारित की गई थी। केपीटी के प्रारंभिक प्रस्ताव दिनांक 2 जुलाई 2012 में पत्तन ने इन तीन कार्गो मदों के लिए दर का प्रस्ताव नहीं किया था। इस सब्ध में उठाए गए प्रश्न पर, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि सोडा एश केपीटी में लम्बे समय से प्रहसित नहीं किया जा रहा है और प्रहसित किए जा रहे इन कार्गो की सामानारंभी भी बहुत दूर दिखाई देती है। इसलिए किसी दर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। केपीटी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के मद्देनजर सोडा एश से संबंधित प्रश्नुल्क मद को सीएचडी हेतु दरों की अनुसूची से हटाया गया है।

संशोधित प्रस्ताव दिनांक 21 फरवरी 2013 में, केपीटी ने सीमेट तथा ऑयल एक्सट्रेक्शन्स (ब्रेक बल्क) के लिए दर निर्धारित की गई थी। केपीटी के प्रारंभिक प्रस्ताव दिनांक 2 जुलाई 2012 में पूर्वानुमानित यातायात को शामिल किया है। संशोधित प्रस्ताव उपयोक्ताओं से विचार विमश कर लाया गया था और इस संबंध में किसी उपयोक्ता से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली है। तदनुसार, सीमेट तथा ऑयल एक्सट्रेक्शन्स (ब्रेक बल्क) केपीटी द्वारा दाखिल किए गए राशीयित प्रस्ताव के अनुसार प्रति टन दर पर पहुंचने के लिए हमारी गणना में सुविधारित किए गए हैं।

(इ). संशोधित प्रस्ताव दिनांक 21 फरवरी 2013 में, केपीटी ने ग्रेनाइट और मार्खल के यातायात का शामिल किया है और इस कार्गो के लिए भी दर शामिल करने का प्रस्ताव किया है। संशोधित प्रस्ताव उपयोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद लाया गया था और इस संबंध में उपयोक्ताओं से कोई प्रतिकूल टिप्पणिया प्राप्त नहीं हुई थी। तदनुसार, इस कार्गो के लिए केपीटी द्वारा अनुमान यातायात और पाली आउटपुट पर विश्वास किया गया है और ग्रेनाइट तथा मार्खल के लिए दर पर पहुंचने के लिए हमारी गणना में विचार किया गया है।

(xvii). प्रारंभिक प्रस्ताव में, केपीटी ने परिवर्तनीय महंगाई भल्ता (वीडीए) की दर में परिवर्तन को लेने के लिए तिमाही आधार पर ऑन बोर्ड लेबर की आपूर्ति के लिए प्रति टन दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने वीडीए में बदलाव दर्शाने के लिए प्रत्येक तिमाही में अपनी ओर से प्रति टन दरों को संशोधित करने के बाद में उसके लिए इस प्राधिकरण का अनुसरण कराया करने का प्रस्ताव किया है। केपीटी ने फरवरी 2013 के अपने संशोधित प्रस्ताव में वीडीए में वृद्धि के प्रभाव को लेने के लिए पूर्ववर्ती प्रस्ताव में माम की गई तिमाही वृद्धि की बजाय तीन वर्षों के प्रश्नुल्क वैयता चक्र के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुल्काता में प्रोत्तर दर के आधार पर संवयी आधार पर निर्धारित प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति देने का अनुरेख किया है। 2005 के प्रश्नुल्क दिशानिर्देशों का खंड 3.1.8 विनिर्दिष्ट करता है कि एक बार निर्धारित किया गया प्रश्नुल्क तीन वर्षों के लिए प्रभावी होगा। ऐसी स्थिति में, तिमाही/वार्षिक (संचयी आधार पर) दरों में वृद्धि करने के लिए केपीटी का प्रस्ताव 2005 के प्रश्नुल्क दिशानिर्देशों में प्रावधान के अनुसार नहीं पाया गया है और इसलिए सौमन्त्र नहीं किया गया है। वीडीए में तिमाही वृद्धि के बारे में केपीटी के दावे के संबंध में, यह नोट किया जाए है। निर्धारित प्रश्नुल्क वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए अनुमानित औसत राजरव अपेक्षा पर आणारित है। वीडीए जो वेतन तथा मार्गदूरियों का घटक है, सहित सभी मदों में महंगाई लागत को पूरा करने के लिए 7 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि में राजरव अपेक्षा कारकों का अनुमानन।

(xviii). पिछले प्रश्नुल्क आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2012 में विस्तारित सीएचडी के लिए दरों की वेता 28 फरवरी 2013 को समाप्त हो गई थी। पत्तन पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा अनुमोदित दरों की वर्तुली करता रहा है। मौजूदा दरों की वेता 1 मार्च 2013 से इस आदेश में अनुमोदित संशोधित दर के कायांनवयन की प्रभावी तारीख तक विस्तारित की गई मानी गई है।

2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देश 3 वर्षों का प्रशुल्क वैधता चक्र विनिर्दिष्ट करते हैं। चूंकि सीएचडी के लिए दर के निर्धारण हेतु सुविचारित लागत स्थिति दो वर्षों अर्थात् 2013–14 और 2014–15 के लिए है, इसलिए निर्धारित प्रशुल्क अठारह महीनों की अवधि के लिए होगा। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सुविचारित वित्तीय स्थिति केवल 31 मार्च 2015 तक है, इसलिए संशोधित दरों की वैधता भी 31 मार्च 2015 को समाप्त हो जाएगी।

(xix) केपीटी से घाटशुल्क में सीएचडी के ऑन-बोर्ड लेबर प्रभार को शामिल करने के लिए काडला पोर्टस र्हीडोर्स असोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव की जांच करने की सलाह दी गई थी। केपीटी ने इस संबंध में रपट किया है कि स्टीवडोरिंग प्रभार समुद्रीय मालभाड़े का हिस्सा है और सामान्यतः पोत एजेंटों द्वारा स्टीवडोरों को भुगतान किया जाता है जबकि घाटशुल्क प्रभार निर्यातक/आयात द्वारा सीमाशुल्क हाउस एजेंटों को प्रतिपूर्ति किए जाते हैं। इसके अलावा, इसने कुछ अन्य व्यावहारिक मुश्किलों के बारे में बताया है जैसे शुल्क का दावा करने के लिए घाटशुल्क तथा ऑन-बोर्ड लेबर प्रभारों के लिए आयातकों द्वारा पृथक बिलों/प्राप्तियों की आवश्यकता, घाटशुल्क और ऑन-बोर्ड स्टीवडोरिंग के लिए घटकों के वर्गीकरण में एकलपता लाना, आदि। दो घटकों को आमेलित करने में केपीटी द्वारा अभिव्यक्त की गई व्यावहारिक मुश्किलों के मददेनजर, सीएचडी से ऑन बोर्ड लेबर की तैनाती के लिए पृथक लेवी की मोजूदा प्रणाली वर्तमान के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई है। पत्तन को सलाह दी जाती है कि ट्रेड के साथ विधार-विमर्श से अगली समीक्षा हेतु प्रस्ताव दाखिल किए जाने के समय घाटशुल्क के साथ ऑन-बोर्ड लेबर प्रभारों को आमेलित करने की समावना की जांच करें।

(xx) पत्तन ने यह उद्धरित करते हुए उत्पादकता संबंधित दरों का प्रस्ताव करने में मुश्किले अभिव्यक्त की हैं कि काडला में प्रधान मिन्न-मिन्न प्रकार के शुक्क कार्गो प्रहस्तित किए जाते हैं और प्रत्येक कार्गो के भिन्न-भिन्न उत्पादकता स्तर हैं और इन कार्गो मर्दों का समूहीकरण एक मुश्किल प्रक्रिया है। केपीटी का मत है कि प्रत्येक प्रकार के कार्गो के लिए उत्पादकता संबंधित दरें निर्धारित करने से पत्तन उपयोक्ताओं से प्रभारों की वसूली पैदीद हो जाएगी।

पत्तन ने उत्पादकता संबंधित दर का प्रस्ताव नहीं किया है, परन्तु यह उल्लेख किया है कि इस बिन्दु का उसके प्रस्ताव में ध्यान रखा गया है। पत्तन ने बताया है कि यदि प्रति गैंग वास्तविक राजस्व प्रति गैंग राजाविता अधिकतम राजस्व अपेक्षा से अधिक है तो पत्तन द्वारा स्टीवडोरों को अधिरेष वर्पिस किया जाएगा और जब यदि कमी रहती है तो इसे स्टीवडोरों से वसूल किया जाएगा। पत्तन ने राय व्यक्त की है कि यह कार्यपद्धति उत्पादकता तुरन्त स्थीकार करेगा और कार्यान्वित करना बहुत आसान है तथा स्टीवडोरों तथा प्रयालन रसाफ द्वारा दिवित है।

तथापि, पत्तन ने सीएचडी से संबंधित अनुसूची में इस प्रोप्रेसिशन को प्रचालन में लाने के लिए उपयुक्त शर्त शामिल नहीं की है। केपीटी का उक्त प्रोप्रेसिशन बहुत वैज्ञानिक तथा अच्छा जाऊ गया प्रस्ताव नहीं दिखाई देता है। उत्पादकता कारक विभिन्न कारकों जैसे पोतों के साथ ग्रैबों की उपलब्धता, ग्रैबों की क्षमता को बढ़ाना, ग्रैबों का खराब होना, अन्य उपरकर जैसे क्रेन का खराब होना, अपक्षीय वातावरणीय स्थिति, अपर्याप्त कार्गो, उपयुक्त थार्ड लेय योजना आदि पर निर्भर करता है। केपीटी ने संभावित प्रति गैंग राजस्व अपेक्षा से अधिक/कम वसूली के लिए स्टीवडोरों से वसूली और को वापसी प्रस्तावित किए जाने के समय उत्पादकता अंजित करने के लिए प्रारंभिक इन कारकों पर विधार नहीं किया है। इसलिए, केपीटी को पुनः सलाह दी जाती है कि सीएचडी के लिए दरों के अगले संशोधन के समय उपयुक्त कारकों पर विचार करते हुए सुविश्लेषित प्रस्ताव दाखिल करें और बहतर उत्पादकता अंजित करने के लिए स्टीवडोरों का प्रात्ताहन रूप में कार्य करने और प्रयालन की समय लागत को कम करने के लिए उत्पादकता संबंधित दरों का प्रस्ताव करें। उस समय तक, केपीटी का उत्पादकता संबंधित प्रस्ताव अनुसूची में शर्त के रूप में शामिल किया गया है।

111. उत्पादकता संबंधित अनुसूची का रूपों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केपीटी के दरमान के अन्तर्गत III में खंड 3 में अनुबंध-IV रूप में संलग्न किए गए केपीटी के कार्गो प्रहस्तन प्रभार की ऑन बोर्ड लेबर के लिए संशोधित समेकित दर अनुमोदित और शामिल करता है।

112. सीएचडी के लिए संशोधित समेकित ऑन-बोर्ड प्रभार भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होंगे और 31 मार्च 2015 तक प्रभागी रहेंगे। इसे प्रदान किया गया अनुमोदन उसके बाद खत ही समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विस्तारित नहीं किया गया हो।

113. इस प्राधिकरण ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के अनुमानों पर विश्वास किया है। उक्त वर्षों में वास्तविक निष्पादन माननामाकी वज्रांत से प्रकट होने वाला प्रतिशत अधिशेष यदि कोई हो, अगली समीक्षा में 2005 के प्रशुल्क दिशानिरेशों के खंड 2-3 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा। जब तक कि किसी भी विशिष्ट मद के सव्यवहार की मिन्न वर्द्धति को उपर्युक्त विश्लेषण में नहीं दर्शाया जाता है।

टो.एम.बाल्नासब्रह्मण्यम्, सदम्य (विज्ञ)

मुख्यमंत्री द्वारा अनुबंध विभाग के माध्यम से जारी कराया गया अनुबंध अधिकारी द्वारा जारी कराया गया अनुबंध

क्र. सं.	विवरण	लिंगायती आदरश दिनांक २५-३-२०११ दे अपान		2011-12 के लिए वास्तविक आकड़े	साशोधित आकड़ों में प्रतिशत में विवरण
		लिंगायती आदरश दिनांक २५-३-२०११ दे अपान	लिंगायती आदरश दिनांक २५-३-२०११ दे अपान		
1	कुल व्यय				
(i).	देशन और मजदूरी (रु 16,716 करोड़ के अंतराइम सहित)	353,124,503	549,166,577	56%	
	घटाया... के पीछे क्या प्रस्तावित सामाचर संशोधन प्रस्ताव में समाचारित किए जाने वाले १०७६ करोड़ का अंतराइम				
	2011-12 के लिए वास्तविक लगात स्थिति का निर्धारण करने के लिए सुनियोजित कुल युवन तथा महिला				
(ii).	मजदूर		441,590,566	25%	
(iii).	कार्यालय और प्रशासन व्यय	2,441	697,718		
(iv).	प्रचालन और अनुस्काण व्यय	128,310	282,268		
(v).	चिकित्सा व्यय	96,737	86,418		
(vi).	प्रलैंगिक	3,325,314	4,910,008		
(vii).	उपचार	988,412	905,441		
(viii).	ऐचन का कामदेशन	5,310,715	25,372,723		
(ix).	ऐचन का कामदेशन	1,506,465	12,799,998		
	जोड़	39,293,053	63,027,279		
2	नियोजित फूटी	403,775,950	549,672,419	36%	
3	नियोजित फूटी पर प्रतिलाम	28,590,658	27,541,461		
4	राजस्व अपेक्षा (1-3)	4,574,505	4,261,763	-7%	
5	कुल अपेक्षा किए गए भाग	408,350,455	553,934,182	36%	
6	वास्तविक राजस्व अपेक्षित प्रति रैम (4/5)	23,843	27,554	16%	
7	लगात कटौती / उत्पादकता के लेखा पर 5 प्रतिशत कटौती	17,127	20,104	17%	
8	वास्तविक राजस्व अपेक्षित प्रति रैम उपर्युक्त 5 प्रतिशत कटौती के बाद (6-7)	856	1,005		
		16,271	19,098	17%	
क.	राष्ट्र 2011-12 के लिए वास्तविक आकड़ों का सार				
(i).	2011-12 के लिए वास्तविक कुल व्यय				
(ii).	वास्तविक तेज्ज्वल के अनुसार 2011-12 में सूचित वास्तविक राजस्व		553,934,182		
(iii).	राजस्व की अधिकता में व्यय		402,377,241		
(iv).	प्रियों अदेश में द्वा सुनियोजित कटौती / उत्पादकता सुचारो आदि के लिए 5 प्रतिशत का समाधान		151,556,941		
(v).	उपर्युक्त समाचारोंजन के बाद वास्तविक उत्पादान		7,577,847		
(vi).	01-10-2013 से 30-09-2016 तक अन्यत नहीं में समाचारोंजन किए जाने वाले राष्ट्रयुक्त रुकमान (क्र. स. ७) या 50 प्रतिशत		143,979,094		
			71,989,547		

अनुबंध-III

काइला परतन व्यास के कार्य प्रहसन प्रमाण का लागत विवरण

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध-III से 2011-12 तक सारांशिक आकड़े					कर्मी द्वारा याचाप्रेत अनुमान	टीएमपी द्वारा सांकेतिक अनुमान	
		2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14			
(रिपोर्ट राज्यों में)									
1	कुल याच	441590586	397427867	504923894	534185754	397427867	425247818	455015165	
(i)	26-2-3 मेरिन उपर्याके के द्वारा याचाप्रेत अनुमान लिए मतदूर्द नियमानुसार है। कि स (१) में सुनियोगी दृष्टिपूर्वक अनुमान लिया गया है।	697718	813795	86869132	9230262558	813795	870761	93714	
(ii)	मानव व्यायाम अनुमान लिया गया है।	282268	139964	14961.66	158750.8679	139964	149761	160245	
(iii)	व्यायाम अनुमान लिया गया है।	86418	6483	6804 04	7352 8026	6483	6937	7422	
(iv)	दरावाह अनुमान लिया गया है।	4910008	3662149	4113189 04	4380546 328	3862149	4132499	4421774	
(v)	कैरियर अनुमान लिया गया है।	905441	100000	1000000	1000000	905441	905441	905441	
(vi)	व्यायाम अनुमान लिया गया है। प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	25372723	37146748	28002849	24648265	35598966	27794493	23621254	
(vii)	८३.५% अनुबंध-III से 2012-13 के दरावाह अनुमान के ५% प्रतिशत पर सुनियोगी दृष्टिपूर्वक अनुमान लिया गया है।	12799988	18739742	18364993	14839349	17958920	17599785	14221043	
(viii)	८३.५% अनुबंध-III के १५ प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	63027279	92274622	10303294	120799844	88429846	94619935	101243330	
(ix)	८३.५% अनुबंध-III के १५ प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	549672419	550511370	661460976	700942888	545143431	571327430	600527389	
(x)	प्रै-वोड	0	13303933	1370305128	14114143	0	0	0	
(xi)	प्रै-वोड अनुबंध-III के ५% प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है। इसका क्रमांक १०१ है।	0	79485573	0	0	59,614,180	63,787,173	68,252,275	
(xii)	८३.५% अनुबंध-III के ५% प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	0	103701738	122254551	12000000	0	0	0	
(xiii)	८३.५% अनुबंध-III के ५% प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	0	103701738	122254551	12000000	0	0	0	
(xiv)	८३.५% अनुबंध-III के ५% प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	549,672,419	747902614	797718579	727057031	604757611	638,326,284	715,203,025	
1	नियोजित और प्रतिलिपि	27541461	27541000	27541000	27541000	25730579	24925138	23919687	
2	नियोजित और प्रतिलिपि	4406560	4406560	4406560	4406560	4116893	3972022	3827152	
3	नियोजित और प्रतिलिपि	553,934,182	752309174	80225139	731463591	608874504	662298306	719030177	
4	वर्ष के लिए अनुमान लिया गया है।	402,377,241	538052885	0	0	538052885	0	0	
5	२०११-१२ और २०१२-१३ के दौरान जारी किया गया राजस्व	151,556,941	110554551	0	0	70821619	0	0	
6	२०११-१२ और २०१२-१३ के लिए अनुमान लिया गया है।	7,577,847	0	0	0	3541081	33114915	33951509	
7	परमाणुकरण अनुमान लिया गया है।	7,577,847	0	0	0	67280538	0	0	
8	प्रियंक अनुराध याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	143,979,094	0	0	0	0	0	0	
9	समायोजन के लिए सुनियोगी दृष्टिपूर्वक अनुमान की जागा	0	0	0	0	0	0	0	
10	८३.५% अनुबंध-III के ५% प्रतिशत पर याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	0	0	0	0	139270085	0	0	
11	०१-१०-२०१५ से ३१-३-२०१६ तक ३ लाख से अधिक दूरक्षमता लिया गया है।	0	0	0	0	23,211,681	46,423,362		
12	कुल याचाप्रेत अनुमान लिया गया है।	0	752309174	802125139	731463591	0	632,395,071	729,502,030	
13	आपूर्ति किए गए कुल याच	27,554	28139	28139	28139	28139	28139	28139	
14	आपूर्ति राजस्व प्रति रुपय (१/-०)	19098	26735	28506	25995	0	23185	25925	
15	प्रति रुपय प्रति रुपय (१/-०)		27079				24555		

क्र. सं	विवरण	गांग की संख्या	राजस्व अपेक्षा प्रति गांग (रु.)	प्रदर्शित मात्रा (भीट)	गांग पाली आरटप्पु (भीट)	दर प्रति गांग (रु.)	विवरण गांग (रु.)	राजस्व अपेक्षा (रु.)	विवरण गांग (रु.)	राजस्व अपेक्षा (रु.)	
(i).	उर्दूक / उर्दूक गांग माल	4273	24555	4947647	1158	21.21	4422882	494765	104922817	4749741	22.09
(ii).	गरबल और फूच खाईन्स	2429	24555	1686309	694	35.37	1517678	168631	59643698	1618857	36.84
(iii).	लौह अमरक	621	24555	1000000	1610	15.25	1000000	0	15248554	1000000	15.25
(iv).	लौह अमरक से इतर अलास्क	661	24555	839067	1269	19.34	755160	83907	16230747	805504	20.15
(v).	फूच	77	24555	48000	623	39.39	43200	4800	1890722	46080	41.03
(vi).	अंगाल और बंगाल	2531	24555	2522039	996	24.64	2269835	252204	62148292	2421157	25.67
(vii).	तथा कंधारा	1808	24555	3863787	2137	11.49	3863787	0	44395145	3863787	11.49
(viii).	अच्यु फौराला	140	24555	325000	2321	10.58	292500	32500	3437677	312000	11.02
(ix).	नमक	2032	24555	3403000	1675	14.66	3062700	340300	49895428	3266880	15.27
(x).	रीनी	589	24555	590000	1002	24.51	531000	59000	14462799	566400	25.53
(xi).	समी अंग अविनिहित सामान	693	24555	1329536	1919	12.80	1196582	132954	17016502	1276355	13.33
											8.00

अनुद्ध-III (अ)

काँड़ागांव प्रतान न्यास में कानून प्रहसन-प्रमाण के अन्तर्भूत लेवर के लिए ब्रेक बल्क कानून हेतु घटकार प्रति टन. दर

क्र. सं	विवरण	गांग की संख्या	राजस्व अपेक्षा प्रति गांग (रु.)	प्रदर्शित मात्रा (भीट)	गांग पाली आरटप्पु (भीट)	दर प्रति गांग (रु.)	विवरण गांग (रु.)	राजस्व अपेक्षा (रु.)	आनुपातिक विदेशी चालायत	विदेशी कारों के सिए दर (रु.)	तटीय कारों के लिए दर (रु.)	
(i).	उर्दूक / उर्दूक गांग माल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ii).	चावल और अच्यु खाईन्स	2868	24555	1232691	430	57	1109422	123269	70423272	1183383.36	59.51	35.71
(iii).	सिंघट	69	24555	150000	217	113	13500	1500	1694284	14400	117.66	70.60
(iv).	स्टील कोइले और स्टील पहाड़	1278	24555	1032886	808	30	929597	103289	31381081	991570.56	31.65	18.99
(v).	लकड़ी और बन्दू लद्दाह	5392	24555	2862253	531	46	2576271	286252	132399630	2748022.08	48.18	28.91
(vi).	सिंक	161	24555	12769	795	31	115172	12797	3953329	122850.24	32.18	19.31
(vii).	वीनी	1600	24555	610000	381	64	549000	61000	39287739	585600	67.09	40.25
(viii).	संगाट और मावलस	569	24555	316000	555	44	284400	31600	13971702	303360	46.06	27.63
(ix).	मणीनी पीपुल और अच्यु लौंग	17	24555	14796	870	28	13316	1480	417432	14204.16	29.39	17.63
(x).	अंगाल एस्ट्रेसन	39	24555	27492	705	35	24743	2749	957639	26392.32	36.28	21.77
(xi).	समी अच्यु अविनिहित सामान	292	24555	98000	336	73	88200	9800	7170012	94080	76.21	45.73

कांडला पत्तन न्यास के दरमान के अध्याय-II में निम्नलिखित अनुसूची शामिल करें

खड़ 3 - कांडला पत्तन न्यास में कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के ऑन-बोर्ड लेबर के लिए समेकित दर हेतु प्रभार

क्र. सं	कार्गो मदे	बल्क		ब्रेक बल्क	
		विदेशी रु०	तटीय रु०	विदेशी रु०	तटीय रु०
1	स्टीविंग/ट्रैकरक फल्सा भाले	22.09	13.25	-	-
2	वावलन और जन्य ल्यालान	36.84	22.10	59.51	35.71
3	स्पेशल	-	-	117.66	70.60
4	स्टील फोइल्स और स्टील पाइप	-	-	31.65	18.99
5	लकड़ी और अन्य लद्दं	-	-	48.18	28.91
6	पश्चीनी पैकेज और जन्य पैकेज	-	-	29.39	17.63
7	जन्य लाइस्ट	15.25	15.25	-	-
8	जन्य लाइस्ट में इतर अग्रस्क	20.15	12.09	-	-
9	लेवल	41.03	24.62	-	-
10	ऑफल रक्स्ट्रैक्शन्स	25.67	15.40	36.28	21.77
11	वाल कायला	11.49	11.49	-	-
12	जन्य कोयला	11.02	6.61	-	-
13	नमक	15.27	9.16	32.18	19.31
14	सीनी	25.53	15.32	67.09	40.25
15	प्रेनेंट और मारबल्स	-	-	46.06	27.63
16	सभी जन्य अविनियोजित सामान	13.33	8.00	76.21	45.73

ठिप्पणी

स्टीविंग द्वारा प्रहस्तित वास्तविक मात्रा के लिए राजस्व को प्रति गैंग लागत पर पहुँचने के लिए आपूर्ति किए गए गैंगों की वास्तविक संख्या से विभाजित किया जाए और इसकी प्रति गैंग राजस्व अपेक्षा से तुलना करें। यदि वास्तविक राजस्व प्रति गैंग अधिकतम औसत राजस्व अपेक्षा प्रति गैंग से अधिक रहता है तो अधिशेष स्टीविंग द्वारा को वापिस किया जाएगा जबकि कमी होने के मामले में इसे स्टीविंग द्वारा से वसूल किया जाएगा।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th August, 2013

No. TAMP/41/2012-KPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes the proposal received from the Kandla Port Trust (KPT) for revision of composite rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division of KPT as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/41/2012-KPT

Kandla Port Trust

...

Applicant

QUORUM:

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on 13th day of August 2013)

This case relates to a proposal filed by the Kandla Port Trust (KPT) for revision of composite rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division of KPT.

2.1. This Authority had passed an Order No.TAMP/37/2007-KPT dated 25 March 2011 approving the proposal of Kandla Port Trust to fix a commodity wise per tonne composite rate for on-board labour in lieu of levy of other charges of its cargo handling division for a period of one year i.e. upto 31 March 2012. The charges were incorporated as clause 3 in Chapter III of the Scale of Rates (SOR) of KPT. In the said Order, the KPT was advised to submit a well analyzed proposal by 31 December 2011 for the rates to be applied with effect from 1 April 2012.

2.2. In this regard, the KPT vide its letter dated 30 March 2012 has, inter alia submitted that the proposal for fixation of revised per ton rate for on-board labour of Cargo Handling Division of KPT is under discussion with the Trade to arrive at consensus before finalization of revision of per tonne rate for on-board labour. The KPT, therefore, requested to allow the port to continue collecting at existing rate provisionally for a further period of three months i.e. upto 30 June 2012 and submitted that the proposal for revision of rate retrospectively w.e.f. 1 April 2012 will be submitted after discussion with Unions/ Trade & Board.

2.3. At the request of KPT, this Authority vide its Order No.TAMP/37/2007-KPT dated 9 April 2012 has extended the validity of the rates for on-board labour beyond 31 March 2012 upto 30 June 2012 subject to the condition that the additional surplus, if any, that may accrue to KPT during the extended period of validity will be adjusted fully in the tariff to be fixed, and advised KPT to file proposal for fixation of on-board labour by 30 April 2012. With regard to retrospective revision of tariff with effect from 1 April 2012, as suggested by KPT, this Authority held that the same may be considered, based on justifications to be furnished by the KPT, in the proceedings to be initiated based on the proposal to be filed by the Port.

2.4. Subsequently, based on the request of the KPT, this Authority further extended the validity of the existing rates till 31 October 2012 vide Order dated 8 August 2012 and later till 28 February 2013 vide Order dated 17 December 2012. The extensions granted were subject to the adjustment of additional surplus, if any, that may accrue to KPT beyond 31 March 2012.

3.1. In this backdrop, the KPT under cover of its letter dated 6 June 2012 and 29 June 2012 has submitted its proposal for revision of per tonne rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division of the Port. The main points made by KPT in its proposal are summarised below:

- (i). The rates have been proposed considering the actual income, cost, traffic handled and gang of on-board labour of cargo handling division supplied for a period from 1 April 2012 to 30 June 2012.
- (ii). In the Order dated 25 March 2011, the Authority had directed KPT to implement the Manning Scales. In this regard, it is informed that the first phase of Manning Scale has been implemented with effect from 22 April 2012. As a result of implementation of Manning Scale, the gang strength has been reduced and the

overtime expenditure has been treated as NIL except Overtime in respect of 17 closed Holidays in a year.

- (iii) As decided by the Board, the excess of expenditure over income excluding overtime cost during the six month period from 01.06.2011 to 30.11.2011 amounting to ₹1.25 crores + 0.78 crores (50% of over time amount to be spread out for 5 years) is considered in the current revision proposal and remaining 50% of overtime amount will be considered in the general revision of Scale of Rates.
- (iv). 20% increase in salary and wages cost, due to ensuing wage revision due w.e.f. 01.01.2012 has been factored in the proposal.
- (v). An anticipated 10% increase in Variable DA (VDA) considering average quarterly increase of 2.5% has also been considered. VDA accounts for more than 10% of the operating expenditure of the Cargo Handling Division. Hence, rates are proposed to be revised on a quarterly basis otherwise port will suffer heavy loss till the VDA increase is reflected in the rates.
- (vi). In order to recognise productivity, KPT has proposed the revenue for actual quantity handled by a stevedore to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the revenue per gang is more than the maximum revenue requirement per gang, the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedore. This methodology will not only recognize productivity instantly but will also be very easy to implement and understand by the stevedores and operating staff.
- (vii). A meeting was also held with the concerned user organisations on 9 May 2012 to seek their consent/ comments/ suggestions, before sending the proposal to TAMP. From the copy of the minutes of the meeting, it is seen that all the members of the Stevedoring Associations are opposed to the proposal mainly in terms of its timing as well as loading of shortfall in revenue due to payment of overtime on the proposed rates. However, it has also been decided that the KPT would submit their proposal to TAMP and then the user associations would furnish their views directly to TAMP, when TAMP would seek their comments on the proposal of KPT.

3.2. The existing per tonne rate and the rate proposed by KPT in its proposal dated 6 June 2012 is summarised below:

Sr. no	Cargo Items	Existing rates (per tonne)				Proposed rates (per tonne)			
		Bulk		Break Bulk		Bulk		Break Bulk	
		Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹
1	Fertiliser/ Fertiliser Raw Material	13.96	8.37	42.92	25.75	20.80	12.48	111.03	66.62
2	Rice and other food grains	21.62	12.97	27.23	16.34	29.71	17.83	49.44	29.66
3	Cement	-	-	21.05	12.63	-	-	-	-
4	Steel Coils and Steel pipes	-	-	17.55	10.53	-	-	28.34	17
5	Timber and other logs	-	-	38.64	23.18	-	-	48.22	28.93
6	Soda Ash	-	-	60.89	36.54	-	-	-	-
7	Machinery Packages and other packages	-	-	72.84	43.71	-	-	117.78	70.67
8	Iron ore	11.14	11.14	-	-	22.59	22.59	-	-
9	Ores other than iron ore	12.20	7.32	-	-	17.57	10.54	-	-
10	Scraps	20.45	12.27	-	-	31.99	19.19	-	-
11	Oil Extractions	18.95	11.37	-	-	24.47	14.68	-	-
12	Thermal Coal	10.39	10.39	-	-	27.33	27.33	-	-
13	Other Coal	9.11	5.46	-	-	12.97	7.78	-	-
14	Salt	11.12	6.67	32.59	19.55	12.12	7.27	23.48	14.09
15	Sugar	17.42	10.45	25.80	15.48	36.08	21.65	44.34	26.60
16	All other unspecified goods	10.85	6.51	36.26	21.75	19.41	11.63	50.78	30.47

3.3. Subsequently, the KPT vide its letter dated 2 July 2012 has submitted that while confirming the minutes in the Board Meeting held on 30 June 2012, the trustees observed that there was deviation regarding element of Overtime considered for revision at ₹3.91 crores. The port has clarified that the Board decided to recover overtime of ₹3.00 crores over five years period and balance to be adjusted in the general revision of its Scale of Rates. In view of the observation, the KPT filed a revised proposal considering the over time amount to the extent of ₹3.00 crores (spread over 5 years). The KPT has under cover of its letter dated 2 July 2012 furnished the revised calculation to that effect. The revised per tonne rates proposed by the KPT in its letter dated 2 July 2012 vis-à-vis the existing rates for deployment of on-board labour from CHD is tabulated below:

Sr. No	Cargo Items	Proposed rates (As per proposal dated 6 June 2012)				Proposed rates (As per proposal dated 2 July 2012)			
		Bulk		Break Bulk		Bulk		Break Bulk	
		Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹
1	Fertiliser/ Fertiliser Raw Material	20.80	12.48	111.03	66.62	20.68	12.41	110.37	66.22
2	Rice and other food grains	29.71	17.83	49.44	29.66	29.53	17.72	49.14	29.48
3	Cement	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Steel Coils and Steel pipes	-	-	28.34	17.00	-	-	28.17	18.90
5	Timber and other logs	-	-	48.22	28.93	-	-	47.93	28.76
6	Soda Ash								
7	Machinery Packages and other packages			117.78	70.67			117.08	70.25
8	Iron ore	22.59	22.59	-	-	22.59	22.59	-	-
9	Ores other than iron ore	17.57	10.54	-	-	17.46	10.48	-	-
10	Scrap	31.99	19.19	-	-	31.80	19.08	-	-
11	Oil Extractions	24.47	14.68	-	-	24.32	14.59	-	-
12	Thermal Coal	27.33	27.33	-	-	27.33	27.33	-	-
13	Other Coal	12.97	7.78	-	-	12.89	7.73	-	-
14	Salt	12.12	7.27	23.48	14.09	12.05	7.23	23.34	14.00
15	Sugar	36.08	21.65	44.34	26.60	35.87	21.52	44.08	26.45
16	All other unspecified goods	19.41	11.65	50.78	30.47	19.30	11.58	50.48	30.29

4. In accordance with the consultation process prescribed, the proposal dated 6 June 2012 and the revised proposal dated 2 July 2012 were circulated to the users / user organisations seeking their comments. The comments received from the users / user organisations were forwarded to the KPT as feedback information. The KPT has responded vide its letter dated 7 November 2012.

5. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the KPT was requested vide our letter dated 8 October 2012 to furnish information/ clarifications on various points. The KPT vide its letter dated 24 December 2012 has responded to our queries. A summary of the queries raised by us and the response of KPT are tabulated below:

Sl. No.	Queries raised by us	Response from KPT
(i).	On the ground that the Variable DA (VDA) accounts for more than 10% of the operating expenditure of the Cargo Handling Division and to reflect the VDA increase in the rates, the KPT in its proposal has proposed that the rates be revised on a quarterly basis. In this regard, it is relevant to mention here that Clause 3.1.8 of the tariff guidelines of 2005 prescribes a tariff validity period of 3 years. Further, it may be recalled that in the tariff Order of March 2011, it has been indicated that the rates are normally approved for a period of three years and that only for the reasons mentioned in the Order, it was approved for a period of one year with a validity upto 31 March 2012 in case of KPT. In view of the above position, the KPT is requested to furnish the Cost	(a). Since decades, Dock Labour Boards in the country were revising the levy every quarter to factor in the increase / decrease in the VDA rates and the stevedores were paying the same. By doing so the charges for supply of labour were always closer to realistic costs. In fact, the quarterly increase/ decrease in VDA rates when implemented, is already based on the average inflation prevailing during the three months preceding the month from it is paid. For instance, the percentage increase or decrease in VDA rates for the quarter October 2012 to December 2012 is based on historic data for the months of June 2011 – August 2012. The cost increase due to this which is directly based on Consumer Price Index (Industrial DA Points) is not susceptible for...

statements relating to the Cargo handling Division for a period of three years from April 2012 onwards in the prescribed format to determine the per tonne on-board labour levy. The Revised Estimates Budget Estimates relied upon by the KPT to formulate its cost statements for a period of 3 years may also be furnished.

estimation that VDA in VDA rate is almost always on the high side.

(b). Cargo Handling Labour Unit being purely a labour supply unit the entire operating cost of the unit is the salaries Wages and other allowances. When these costs rise a whopping 10-15% every year the port cannot afford to wait for completion of the tariff validity cycle of three years to absorb the huge increase in cost that would have occurred by the time the next tariff revision cycle begins.

(c). Besides this exercise would unduly enrich present day exporter at the cost of the future importers who who may not even handle the port directly. Whereas if the rates are revised on a quarterly or monthly basis the effect would be immediate.

(d). Also, if the increase in VDA is carried forward till the next tariff revision cycle the rates that will be obtained will be very high and the trade will not be ready to pay for the same as has happened in the instant case.

(e). The tariff guidelines were framed during the year 2005 whereas the merger of many Dock Labour Boards with the respective port trusts has taken place after the formulation of the tariff guidelines. For instance, KDLB was merged with KPT in 2007, VDLB was merged with VPT in 2008. Merger of Tuticorin and Kolkata DLBs also happened after the formulation of tariff guidelines.

Hence, it is felt that the rates for supply of Cargo Handling Labour may be revised every quarter or atleast every six monthly basis.

The statement showing actual Income & Cost relating to CHD for the year 2011-12 is as given below. The figures taken in statement are as per Annual Accounts, hence reconciliation statement is not required.

ACTUAL INCOME & COST RELATING TO CHD FOR THE YEAR 2011-12:

Particulars	₹. in lakhs
Income	4023.77
Expenditure	
Salaries & Wages	5491.66
Stores	6.98
Office & Admin Expenses	2.92
Operation & Maintenance Expenses	0.86
Medical Expenses	49.10
Depreciation	9.05
Pension Gratuity & Commutation	1012.00
Return on Capital Employed @ 16%	44.07
Deficit	6616.55
	-2592.78

- (ii) The KPT is also requested to furnish the actuals relating to the Cargo handling Division for the year 2011-12 in the prescribed format. The Annual Accounts relied upon by the KPT to reflect the actuals may also be furnished along with a Reconciliation Statement to reconcile the differences, if any, between the figures in the Annual Accounts and the Cost statements.

- (iii) As mentioned at para 13(vii)(b) of the Order of 3 March 2011, the KPT has been advised to take steps relating to implementation of the Tribunal

award for revision of manning scales and datum. The KPT in its proposal has stated that the Phase I of manning scale has been implemented from 01 April 2012, as a result of which the gang strength has been reduced. In this regard, the KPT is requested to clarify/furnish the following:

(a) The extent of reduction in the gang strength on account of implementation of the manning scales has not been furnished, which may be furnished along with the entire effect of phase I implementation of manning scales including reduction in manpower achieved. A comparative position of the manning scale with reference to on-board workers per one hook irrespective of the types of cargo (except salt in bulk) and the manning scale for salt in bulk obtaining prior to implementation and after implementation of the Tribunal award may also be furnished.

(a). It is felt that implementation of manning scale is a policy decision and has far reaching impact on the working of the port and requires extensive negotiations with the Trade Unions and any hasty decision in this direction can jeopardize the entire functioning of the port.

(b). The Report of Working Group for Port Sector for the 12th Five year plan prepared by the Ministry of Shipping clearly recognizes at paragraph 11.6.2.1 that the award is yet to be implemented in some of the ports. (The KPT has furnished a copy of the relevant extract of the Report of Working Group for Port Sector for the 12th 5 year plan prepared by the Ministry of Shipping.) Thus Ministry of Shipping is already seized of the matter. The decision with regard to the extent of implementation of the manning scales, the phases of implementation should be left to the port management and should not be linked to Tariff Fixation.

(c). In fact, full implementation of the manning scale will result in majority of the workers being surplus. Without a proper planning for their redeployment or retrenchment via Special Voluntary Retirement Schemes or their retraining, 100% implementation of the manning scales will create chaos in the port and may lead to huge industrial unrest in the port sector. Also, who will bear the cost of their committed Salaries and Wages is a question to be addressed. Port cannot be expected to pay the salaries, wages, allowances and retirement benefits as per wage board settlement without recovering the same from the port users.

(d). The KPT has furnished a statement showing the impact of implementation of manning scale based on the actual data for the period from October 2011 to March 2012. It is seen from the statement that 82358 man shifts of RP worker and 1830 man-shifts of Tindal would have been surplus. This amounts to 85% of the available man-shifts of RP Worker and 21% of the available man shifts of Tindal.

(e). Hence, till a decision is taken about either retrenchment or redeployment of this huge surplus manpower, KPT has to recover their salaries and wages from the stevedores and cannot be expected to bear their salaries and wages from its reserves.

(f). Moreover, these workers cannot be retrenched overnight as the Trade Unions will vehemently oppose any such move. Hence, it is felt that TAMP may not associate itself with this policy implementation and the same should be left to the local port managements.

(g). A comparative position of the manning scale with reference to on-board workers per one hook irrespective of the types of cargo (except salt in bulk) and the manning scale for salt in bulk obtaining prior to implementation and after implementation of the Tribunal Award is furnished below:

Type of Cargoes	Gang Composition prior to implementation of Tribunal Award on Manning Scales			Gang Composition after implementation of Tribunal Award on Manning Scales		
	RPW (Per Hook)	Tindal (Per Hook)	Signalman (Per Hook)	RPW (per Hook)	Tindal (Per Shift)	Signalman (Per Shift)
All cargoes (other than salt in bulk)	10	1	1	5	1	1
Salt in bulk	2	1	1	2	1	1

*RPW – Registered Pool Worker

(b) It appears that the KPT has envisaged phase wise implementation of manning Scales. Please furnish a detailed note on the remaining phase wise implementation of manning Scales.

In the first phase of implementation of manning scales, the deployment of Registered Pool Workers (RPW) has been halved and deployment has also been continued on Dry Bulk Cargoes. In the second phase, the deployment of RPW will be done keeping in view the demand / supply position with a view to ensure that there are no surplus gangs. The strategy of the port is to gradually achieve the deployment levels as per the manning scale taking into consideration the retirement / death of workers and ensuring that the gangs are not rendered surplus which could lead to industrial unrest.

(c) The KPT is silent regarding the revision of datum on account of implementation of the Tribunal award. The KPT is requested to clarify the existing position in this regard.

The datums have not yet been revised as no consensus has yet been reached with the Major Trade Unions operating at the Port. In this regard a series of meetings have been held with the Trade Unions. However, the Trade Unions are taking a stand that piece rates were finalized 25 years ago and the same rates are continuing even today without any revision despite there being 5 wage revisions during this period. The unions are also taking a stand that revision should lead to more benefit for the worker without which there cannot be any amicable settlement. As this is highly labour sensitive issue the same will have to be sorted out by consultative and bargaining approach so that port operations are not disrupted. In fact the unions agreed for partial implementation of Manning Scale only after being assured that the piece rate incentives being paid presently will be protected. As such being a policy decision, it is felt that TAMP may not associate itself with the same and the issue of implementation should be left to the local port management. Also, there may not be any net financial implication as the Trade Unions will never agree to downward revision of existing benefits. Thus, while on one hand datums will be revised, on the other hand the piece rate will increase leading to neutral impact. Also, the wage

	<p>agreements signed with the unions contain ubiquitous clause to the effect that existing levels of benefits enjoyed by the workers will invariably be protected.</p>
(i)	<p>As mentioned at para 13(xviii) of the Order of March 2011, the KPT was advised to consider the various factors as listed in the said paragraph and to submit its proposal linked to productivity levels. In this context, the KPT is requested to clarify / furnish the following:</p> <p>(a) Though the KPT has proposed for refund to/ recovery from the stevedore based on the productivity of the gang supplied by the port, it does not appear that the KPT has taken into account the various factors listed in the Order of March 2011 at the above mentioned paragraph to base its proposal linked to productivity as advised by this Authority. The KPT is requested to clarify and review the position in this regard.</p>
	<p>Implementation of the National Tribunal Award on Manning Scale has resulted in significant reduction in cost by cutting down the expenditure on overtime. The per ton rates prescribed for various cargoes are based on the actual gangs deployed during the period from May 2011 to November 2011 and already factor in the productivity achieved.</p> <p>Apart from this, the KPT has reiterated its submissions made in its reply to our query at (v) above expressing the difficulties in proposing cargo-wise productivity linked rates</p>
	<p>(b) A draft conditionality towards incentive for better performance and disincentive for under performance for incorporation in the Scale of Rates may be proposed</p>
	<p>As mentioned at para 13(xv) of the Order of March 2011, the KPT was advised to initiate steps to improve efficiency and reduce costs. The steps taken by the port in this regard may be listed and the financial impact on account of taking such steps may be quantified and furnished.</p>
	<p>In view of the above no note is required to be given.</p>
	<p>Implementation of the National Tribunal Award on Manning Scale has resulted in significant reduction in cost by cutting down the expenditure on overtime. The per ton rates prescribed for various cargoes are based on the actual gangs deployed during the period from May 2011 to November 2011 and already factor in the productivity achieved.</p> <p>Many cargoes at Kandla are very seasonal in nature. For instance Fertilizer imports rise during the period from May to October after which there is a marked reduction in the imports. Exports of Food grain and soya extractions are very less during July to October. So depending upon the period during which the tariff revision proposal gets approved, the rates could fluctuate heavily. Grouping of the cargoes into various heads becomes a tedious task as there are more than 50 different types of dry cargoes handled at Kandla each having different productivity levels. For instance let us consider Timber Logs. While Pine Timber Logs have less productivity, the other timber logs have much higher productivity. Again huge windmills being recently imported at Kandla have a very less productivity as discharging takes time while other items of machinery / CKD items have comparatively higher productivity. Prescribing productivity linked rates for each cargo type will also complicate the realization of charges from port users. Even Port users prefer a single</p>

		rate. This is being experienced in case of tariff fixed for Harbour Mobile Cranes.																																																				
(vi)	The proposal of KPT for revision of the existing per tonne rate for on-board labour is with retrospective effect from 1 April 2012. In this regard, it may be recalled that as mentioned at para 4 of the Order of April 2012 extending the validity of the rates of the Cargo handling division, it has been stated that retrospective revision of tariff w.e.f. 1 April 2012, as suggested by KPT, would be considered, based on justifications to be furnished by the KPT, in the proceedings to be initiated based on the proposal to be filed by the Port. The KPT in its proposal under consideration has not justified the retrospective effect for the proposed rates sought by it.	The retrospective revision is absolutely essential as otherwise the port will suffer a huge loss. Even the CAG has adversely commented in this regard. In fact, TAMP while approving the per ton tariff vide its Order No.TAMP/37/2007-KPT passed on 25.03.2011, has also approved the adhoc rate of ₹850/- per worker per shift without piece rate and ₹1084/- per worker per shift with Piece Rate for the entire period from 25.01.2007 till 04.06.2011. During this approximately 58 months period there was a huge rise in the salaries and wages of the dock workers and a huge increase in operating cost of the port and the same has resulted in a massive loss of ₹34.12 crore for the port. The CAG has already raised this issue in its draft inspection report. The rates of ₹850/- and ₹1084/- were purely adhoc rates based on the working results of the erstwhile KDLB during the 9 month period from 01.04.2006 to 31.12.2006 preceding the date of merger w.e.f. 24.01.2007. Thus, by paying a rate based on a nine month cost, the stevedores have made windfall gains. Hence, if the rates are not approved with retrospective effect, it will amount to bleeding the port.																																																				
(vii).	KPT has adopted an escalation factor of 10% for estimation of VDA increase apart from adopting an escalation factor of 20% to account for the wage revision. While the increase in salary on account of wage revision to be due from 1 January 2012 can be understood, it may be noted that the estimation of all the other expenditure projections in the cost statement would be based on an escalation factor of 6.50% per annum as already communicated by us vide our letter No.TAMP/27/2005-Misc. dated 11 May 2012.	It is reiterated that escalation percentages considered for other items of Tariff like Cargo Handling Equipment, Marine Charges may not be applicable to the tariff fixation methodology for Dock Workers. With mounting retirement costs owing to a large chunk of Cargo Handling Workers due for retirement and impending wage revision and keeping in view the current inflationary trends the 10% increase considered is perfectly justified. Further during the past three years the average yearly increase in VDA has been to the tune of 12.67% as detailed below:-																																																				
(viii)	in the revised Statements furnished by the KPT under cover of its letter dated 2 July 2012, it is not clear as to how the KPT has arrived at the amount of ₹31,58,16,098/- being the total expenditure	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Quarter</th> <th>Increase in VDA over previous qtr</th> <th>Calendar Year Increase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>Q2</td> <td>4.30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q3</td> <td>0.70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q4</td> <td>4.00%</td> <td>9.00%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>Q1</td> <td>4.10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q2</td> <td>2.90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q3</td> <td>1.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q4</td> <td>4.00%</td> <td>12.00%</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Q1</td> <td>5.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q2</td> <td>1.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q3</td> <td>3.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q4</td> <td>7.00%</td> <td>17.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Average Yearly Increase</td><td colspan="2">12.67%</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Note: The VDA percentage as on 01.01.2010 was 31%. The increase thereafter Q-o-Q is as given above.</i></p> <p>Statement showing the total expenditure of ₹31,58,16,098/- being the total expenditure incurred in respect of Cargo Handling Division is for the period from June 2011 to 30 November</p>	Year	Quarter	Increase in VDA over previous qtr	Calendar Year Increase	2010	Q2	4.30%			Q3	0.70%			Q4	4.00%	9.00%	2011	Q1	4.10%			Q2	2.90%			Q3	1.00%			Q4	4.00%	12.00%	2012	Q1	5.00%			Q2	1.00%			Q3	3.00%			Q4	7.00%	17.00%	Average Yearly Increase		12.67%	
Year	Quarter	Increase in VDA over previous qtr	Calendar Year Increase																																																			
2010	Q2	4.30%																																																				
	Q3	0.70%																																																				
	Q4	4.00%	9.00%																																																			
2011	Q1	4.10%																																																				
	Q2	2.90%																																																				
	Q3	1.00%																																																				
	Q4	4.00%	12.00%																																																			
2012	Q1	5.00%																																																				
	Q2	1.00%																																																				
	Q3	3.00%																																																				
	Q4	7.00%	17.00%																																																			
Average Yearly Increase		12.67%																																																				

incurred in respect of Cargo Handling Division for the period from 1 June 2011 to 30 November 2011 in the Statement - C. The sum total of all the expenditure including escalations as well as the pension/ gratuity amounts as given in the Statement - D (which reflects the Cost details of Cargo Handling Division for the period from 1 June 2011 to 30 November 2011) does not add up to the said amount. The KPT is requested to clarify the position and make suitable changes in the Statements, wherever necessary, to reflect the correct position.

2011 is given below:

Sl. No.	Particulars	₹ in lakhs
1	Salaries & Wages (inclusive of Overtime to the tune of ₹782.46 lakhs)	2590.11
2	Stores	13.60
3	Office & Admin Expenses	1.29
4	Operation & Maintenance Expenses	0.68
5	Medical Expenses	21.49
6	Depreciation	5.00
7	Pension Gratuity & Commutation	526.00
	Total	3158.16

In the statement 'D' under the head salary & wages, Over Time amount of ₹7,82,46087 has been deducted and as stated under point No. 15 ₹40,00,000 has been added.

(ix) The KPT is requested to clarify the following with reference to Statement - D:

(a) The reasons for considering a different amount towards Salaries and Wages for fixing rate as compared to the Annual Accounts figure may be brought out.

In KPT expenditure booking is done firstly at division level and thereafter the same is updated in the centralized accounting system. The annual accounts were not finalized at the time of submission of tariff revision proposal. In case the expenditure figures recorded with the Cargo Handling Division were higher due to non-updation of the accounts ledger, the same have been considered.

The cash in lieu of uniform although pertaining to the year 2008-10 has actually been decided to be paid during the year 2011-12

(b) With regard to Stores, the KPT has considered an amount of ₹13.60 lakhs for the purpose of fixing tariff which includes an amount of ₹6.62 lakhs towards cash in lieu of uniform cost for the block year 2008-2010. The reason for loading the amount pertaining to the year 2008-2010 in the expenditure for the period from June 2011 to November 2011 may be explained and justified.

(x) The approach adopted by KPT to arrive at the revenue requirement for the Cargo handling division in Statement - D takes into account the reported deficit of six months for the period from 1 June 2011 to 30 November 2011. The KPT is requested to clarify whether this approach is in line with the Cost plus method of fixation of tariff envisaged by the tariff guidelines of 2005.

(a) The rationales behind factoring only a part of the overtime component out of the total actual overtime amount of ₹7.82 crores relating to the period from 1 June 2011 to 30 November 2011, to arrive at the revenue requirement for the Cargo handling division in Statement - D and the remaining overtime component in the general revision may be explained. In this regard, it may be noted that by factoring the remaining overtime component in the general revision, the other divisions like Kandla and Vadinar may have to cross subsidise the cargo handling division, which may not be desirable.

KPT cannot afford to bear the deficit and as such there is no other way in which the same can be recovered except to load it in the revised rates. TAMP may suggest any alternate method in which the deficit can be absorbed.

KPT would not ideally like to spread the deficit. However as already brought out, the delay in revision of rates coupled with increasing VDA rates results in huge variation in the rates which the trade cannot afford to bear. It is due to this reason that KPT strongly feels that TAMP should consider allowing increase on a quarterly basis suo motu by the respective ports subject to ratification by the TAMP. This will ensure that the rates are aligned with the costs at all times and even the importers and exporters can predict before hand the likely quantum of increase as the figures of Consumer Price Index is declared every quarter.

(ii) The rationale behind spreading such part of the overtime component of ₹3 crores over a period of five years for fixation of rate for Cargo handling division may also be brought out.

Purely with a view to avoid huge variation in the rates the port has consciously taken a decision to spread the deficit over a period of five years on the request of Trade. Also the Board of Trustees of the KPT were of the view that since the stevedoring contracts for the forthcoming years have already been finalized and in the event of huge revision in rates, the stevedores themselves cannot bear the impact of huge increase in rates and cannot pass it on the final users, which may attract commercial consequences and lead to legal problems and hence a conscious decision was taken to spread the loss which will ensure cost effectiveness in view of the competition from neighbouring ports

(iii) Furnish the basis for the capital employed considered at ₹2.75 crores in the Statement - D. Also furnish the breakup of the Capital Employed considered in the Statement.

The statement showing the breakup of the Capital Employed considered in the statement is furnished.

	(Amt. in ₹)
Opening Gross Block	44038339
Less Acc Depreciation	16455876
Written Down Value	27541461

(iv) Confirm that the gang requirement at 14383 considered in the Statement - D for handling bulk and break bulk cargo is as per the actuals for a period of six months from 1 June 2011 to 30 November 2011.

It is confirmed that Gang Requirement of ₹14383 is based on actuals for the six months from 01.06.2011 to 30.11.2011.

(v) The KPT has not considered cargo throughput of cement and soda ash in its workings and has also not proposed any rates to handle the said cargoes, probably on the ground that these cargoes were not handled during the period of six months for the period from 1 June 2011 to 30 November 2011. In this regard, the KPT is requested to clarify as to what rates it would levy incase it happens to handle such cargoes in future.

Of late Soda Ash is no longer being handled at KPT and the chances of these cargoes being handled also appear to be very remote. A very negligible quantity of 14604 MT has been handled during the six months of the current financial year. As regards the rates that will be levied in case such cargoes are handled it is clarified that, the rates prescribed for "All other unspecified goods" as approved by TAMP will be charged. Further, prescribing separate rates for these cargoes would have lead to very high per ton rates. For instance taking the revenue requirement per gang of ₹21220/- as already proposed, the per ton rate for cement would have been ₹75.37 per MT. This based on 52 gangs actually deployed for handling 14604 MT of Cement. As against the above the port has recovered ₹35.26 per MT.

(vi) It appears that the overtime cost of 17 days calculated at ₹36 Lakhs in Statement-E has not been factored in the cost computation furnished in Statement-D. That being so, the relevance of Statement-E may be explained.

The expenditure on Salaries & Wages amounting to ₹184764814/- considered in the proposal already includes ₹40,00,000/- towards projected OT. Although the OT for 17 days works out ₹36 lacs as reflected at Statement E the same has been rounded and considered as ₹40,00,000/- in Statement -D

6.1. A joint hearing in this case was held on 11 January 2013 at the KPT premises. The KPT made a power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the KPT and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

6.2. At the joint hearing the Kandla Port Karmachari Sangh (KPKS) vide its letter dated 11 January 2013 furnished its written submissions on the subject proposal. Subsequently, the Kandla Stevedores' Association Limited (KSA) vide its letter dated 28 January 2013 and the Kandla Port Dock Stevedores Association (KPDSA) vide its letter dated 7 February 2013 addressed to KPT and copy endorsed to the Authority furnished its comments on the subject proposal. A copy each of these submissions were forwarded to the KPT vide our letter dated 30 January 2013 and 18 February 2013 for comments. The KPT has not furnished its comments thereon

7.1 As decided at the joint hearing, the following points were brought to the notice of the KPT with a request to initiate action vide our letter dated 17 January 2013 :

- (i). The proposal of the KPT is to revise the per tonne rates for supply of on-board labour on a quarterly basis to capture the change in the rate of variable Dearness Allowance (VDA). The port has proposed to modify the per tonne rates suo motu every quarter to reflect the change in the VDA and obtain the ratification of the Authority therefor subsequently. In this regard, KPT may note that the tariff guidelines of March 2005 call for fixation of tariff for a tariff cycle of three years.
- (ii). Reformulate its proposal for review of the rates for supply of on-board labour of its CHD covering the tariff cycle of three years viz. 2012-13 to 2014-15 based on realistic estimates. While formulating the proposal, the estimates for the year 2012-13 may be framed on actuals for the period April 2012 to December 2012 and estimates for the subsequent three months of the year 2012-13.
- (iii) The rates for CHD of KPT was last fixed for truncated period of one year 2011-12 for reasons recorded in the concerned tariff Order. The tariff guidelines require review of the actual physical and financial performance at the end of the prescribed tariff validity period. The KPT is, therefore, requested to furnish the details of actual volume of commodity-wise traffic handled, income realised and cost incurred by its CHD during the years 2011-12 supported by Accounts of CHD certified by a Chartered Accountant for the year 2011-12.
- (iv). Examine the suggestion made by the Kandla Ports Stevedores Association to include the on-board labour charge of CHD in the wharfage as agreed at the joint hearing.

7.2 In pursuance to our letter dated 17 January 2013, the KPT vide its letter dated 21 February 2013 has filed its reformulated proposal and has also furnished its response/ submissions. The main points made by the KPT are summarised below:

- (i). The revised proposal has been prepared for the tariff cycle of three years 2012-13 to 2014-15 based on realistic estimates. As directed, the estimates for the year 2012-13 has been framed based on actuals for the period April 2012 to December 2012 and the estimates for the subsequent three months of the year 2012-13.
- (ii). The following points have been taken into account in the revised proposal:
 - (a). 20% towards provision for increase in salary and wages due to wage revision due w.e.f.01.01.2012.
VDA increase of 10% on basic pay.
 - (b). Excess of expenditure over income during the year 2011-12 amounting to ₹9,17,01,747/- and ₹11,05,54,557/- for the year 2012-13 has been considered in the year 2012-13 and 2013-14 respectively.
 - (c). Overtime amount of ₹6,00,00,000/- has been spread for 5 years and accordingly ₹1,20,00,000/- has been considered in each years.
 - (d). Increase of 3% has been considered for normal increase in wage bill (other than VDA) in the estimation for the years 2013-14 and 2014-15 Other expenditure has been estimated applying escalation factor of 6.5% as per TAMP Guidelines.

(iii) The port has filed a revised cost statement of CHD. A summary of the cost position furnished by KPT for the period 2011-12 to 2014-15 is tabulated below:

(in ₹)

Sr. No	Particulars	Actuals		Estimates	
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(1)	Total Expenses	420514847	496039764	524762792	554769573
(2)	Gratuity	25372723	37146748	29002949	24648265
(3)	Commutation of Pension	12799998	18739742	18364993	14839349
(4)	Pension	63027279	92274622	103033294	120799844
(5)	Excess of Expenditure over income during the year 2011-12 (excluding OT) ₹91701747 + OT amount spread for 5 years as decided by Board i.e. ₹(3 crore * 2/5) = ₹12000000	108459654	103701738	122554551	12000000
(6)	TOTAL EXPENSES (1+2+3+4+5)	630174501	747902614	797718579	727057031
(7)	Capital Employed	27541000	27541000	27541000	27541000
(8)	Return on Capital Employed @ 16% per annum	4406560	4406560	4406560	4406560
(9)	Revenue Requirement	634581061	752309174	802125139	731463591
(10)	Total Gangs Supplied (Nos.)	27554	28139	28139	28139
(11)	Revenue Expected per Gang	23030	26735	28506	25995

(iv). The port has furnished a working for arriving at commodity-wise per tonne rate to meet expected revenue requirement per gang

(v). Accordingly, the revised rates proposed by KPT for on-board labour along with comparative position of the existing rates and the rates now proposed is tabulated below:

Sr. No	Cargo Items	Existing rates (per tonne)				Proposed rates(per tonne)				% of increase			
		Buik		Break Bulk		Bulk		Break Bulk		Bulk		Break Bulk	
		Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹
1	Fertiliser/ Fertiliser Raw Material	13.96	8.37	42.92	25.75	24.36	14.61	-	--	74.79%	74.55%	--	--
2	Rice and other food grains	21.62	12.97	27.23	16.34	40.63	24.38	55.63	39.38	87.92%	87.97%	141.02%	141%
3	Cement	-	-	21.05	12.63			129.75	77.85	--		516.38%	516.38%
4	Steel Coils and Steel pipes	-	-	17.55	10.53	-		34.9	20.94	--		98.86%	98.86%
5	Timber and other logs	-	-	38.64	23.18			53.13	31.88	--		37.5%	37.53%
6	Soda Ash	-	-	60.89	36.54			--	--	--			
7	Machinery Packages and other packages	-	-	72.84	43.71			32.41	19.45	--		(-55.51%)	(-55.51%)
8	Iron ore	11.14	11.14	-	-	22.59	22.59	--	--	102.78%	102.78%	--	
9	Ores other than iron ore	12.20	7.32	-	-	22.22	13.33	-	-	82.13%	82.10%	--	
10	Scraps	20.45	12.27	-	-	45.25	27.15	-	-	121.27%	121.27%	--	--
11	Oil Extractions	18.95	11.37	-	-	28.31	16.98	40.01	24.01	49.39%	49.34%	--	--
12	Thermal Coal	10.39	10.39	-	-	27.33	27.33	-	-	163.04%	163.04%	--	--
13	Other Coal	9.11	5.46	-	-	12.15	7.29	-	--	33.36%	33.51%	--	--
14	Salt	11.12	6.67	32.59	19.55	16.84	10.11	35.49	21.29	51.43%	51.57%	8.89%	8.9%
15	Sugar	17.42	10.45	25.80	15.48	28.16	16.89	73.98	44.39	61.65%	61.62%	186.74%	186.75%
16	All other unspecified goods	10.65	6.51	36.26	21.75	14.70	8.82	-	-	35.48%	35.48%	131.77%	
17	Granites & Marbles	--	--	--	--	--	--	50.79	30.48	--	--	--	--

- (vi) The KPT has furnished the details of actual volume of commodity-wise traffic handled, income realized and cost incurred by CHD during the year 2011-12
- (vii). As regard the point made by us on its proposal to revise the rates on quarterly basis to absorb quarterly increase in VDA, the KPT has once again requested to allow fixed percentage increase (on a cumulative basis) on the per tonne rate at the beginning of each year during the three year tariff validity cycle as discussed in the joint hearing held on 11 January 2013. It has stated that this is in line with the annual escalation allowed by TAMP on the lease rentals/ upfront tariff fixation
- (viii). With reference to the suggestion made by the Kandla Port Stevedores Association to include the on-board labour charge of CHD in the wharfage at the joint hearing, the KPT has made following submissions:
- (a). Stevedoring Charges almost invariably form part of the ocean freight and are usually paid by vessel agents to stevedores, while wharfage charges are reimbursed by the exporter/ importer to the Custom House Agents.
 - (b). Stevedoring Charges form part of "Assessable Value" of goods for the purpose of Custom Duty by virtue of being included in the landing charges which are levied as a percentage of CIF value of the goods by the Custom, whereas wharfage charges do not form part of the assessable value as the same are incurred after landing of the goods. Importers may require separate bills/ receipts issued by Port for wharfage & On Board Labour Charges for their duty claims.
 - (c). Classification of commodities for the purpose of Wharfage Charges and On Board Labour Charges are very much different and if both the charges are to be integrated the classification of commodities has to be uniform.
 - (d). Units of levy of wharfage charges and On- Board Labour Charges are different. While different units are prescribed for levy of wharfage charges like Cubic Meter, Metric Tonnes, Numbers, Ad-valorem, the unit of levy of On Board Labour Charges is Metric Tonne only. Hence, uniformity in the matter of unit of levy has to be ensured prior to integration.
 - (e). The integration of wharfage and stevedoring charges may create some practical difficulties. For instance if the goods are exported from a foreign port to Kandla Port on CIF basis then the Exporter stationed in foreign port would have included the stevedoring charges for unloading of goods at Kandla and in all probability would have already recovered the charges from the importer stationed at Kandla. In such a situation the Stevedore will not agree to pay the Wharfage Charges as he has already paid his stevedoring charges and also the CHA will never agree to pay On Board Labour Charges as he has already paid a consolidated rate to the exporter. Similar situation will arise in case the goods are exported from Kandla to foreign port on CIF basis. This problem will further aggravate if there are some importers who have imported the cargo on CIF basis while some importers have imported the cargo on FOB basis. Hence, it is opined that the issue of inbuilt on-board labour charges into wharfage will be attempted at a later stage after obtaining considered opinion from all concerned.

The revised proposal received from the KPT was circulated to the user / user association for comments vide our letter dated 27 February 2013. The comments so received were forwarded to the KPT as feedback information. The KPT has, however, not furnished its response thereon.

8 Based on the preliminary scrutiny of the revised proposal dated 21 February 2013, the KPT was requested vide our letter dated 12 July 2013 to clarify a few points. The KPT vide its letter dated 19 July 2013 has responded to our queries. A summary of the queries raised by us and the response of KPT are tabulated below:

Sl. No.	Queries raised by us	Response from KPT																																																																																																																				
(i)	Please furnish the breakup of ₹10,845.9654 considered in the year 2011-12 in Annexure-I, Sr. No.(k).	It is submitted that ₹103701747/- has been considered in the year 2012-13 for which the port has furnished the break up.																																																																																																																				
(ii)	On perusing the figures relating to CHD in RE 2012-13 & BE 2013-14 and RE 2011-12 & BE 2012-13, it is seen that for the year 2011-12 the actual overtime is ₹1675.76 lakhs which forms 85% of actual Basic Salary plus D.A. (₹1959.39 lakhs). In the immediate previous year 2010-11, the overtime expense for CHD is reported at ₹1001.59 lakhs which forms 50% of the basic plus D.A. ₹2041.09 lakhs. In this context, the following points may be clarified: (a) Explain the reason for steep increase in the overtime cost in the year 2011-12. (b) It appears that overtime cost reported in the year 2011-12 includes the impact of wage revision arrears. If so, please indicate the quantum of wage revision arrears of the past period included in this cost.	<p>(a). The primary reason that could be attributable to increase in the overtime expenditure is the excess of demand for CHD gangs vis-à-vis their supply. The month-wise demand v/s supply of CHD gangs and deficit is as under:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Month</th><th>Demand of CHO Gangs</th><th>Supply of CHD Gangs</th><th>Deficit</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>April 2011</td><td>1928</td><td>1594</td><td>334</td></tr> <tr><td>May 2011</td><td>1986</td><td>1643</td><td>343</td></tr> <tr><td>June 2011</td><td>2031</td><td>1614</td><td>417</td></tr> <tr><td>July 2011</td><td>2350</td><td>1668</td><td>682</td></tr> <tr><td>Aug 2011</td><td>2350</td><td>1668</td><td>682</td></tr> <tr><td>Sept 2011</td><td>2440</td><td>1620</td><td>820</td></tr> <tr><td>Oct 2011</td><td>2161</td><td>1654</td><td>507</td></tr> <tr><td>Nov 2011</td><td>2223</td><td>1611</td><td>612</td></tr> <tr><td>Dec 2011</td><td>2467</td><td>1672</td><td>795</td></tr> <tr><td>Jan 2012</td><td>2200</td><td>1669</td><td>531</td></tr> <tr><td>Feb 2012</td><td>2028</td><td>1496</td><td>532</td></tr> <tr><td>Mar 2012</td><td>1747</td><td>1544</td><td>203</td></tr> </tbody> </table> <p>(b). In addition to the mismatch between demand and supply of gangs, another factor that may have contributed to rise in OT during the year 2011-12 as compared to 2010-11 is the increase in per hour OT rate as a result of Wage Revision. A table showing the per hour OT rate of Senior-most and Junior-Most employee of each of two categories of CHD workers viz. Tindal & RP Worker prior to wage revision and after wage revision is tabulated below:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Period</th><th rowspan="3">Month</th><th colspan="4">Per Hour OT Rate</th></tr> <tr> <th colspan="2">Tindal</th><th colspan="2">RP Worker</th></tr> <tr> <th>Senior</th><th>Junior</th><th>Senior</th><th>Junior</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>After Wage Revision</td><td>Apr-11</td><td>110.25</td><td>52.68</td><td>107.25</td><td>49.61</td></tr> <tr> <td>Before Wage Revision</td><td>Feb-10</td><td>83.58</td><td>42.75</td><td>78.34</td><td>42.75</td></tr> <tr> <td>% Change</td><td></td><td>31.91</td><td>23.23</td><td>36.90</td><td>16.05</td></tr> </tbody> </table> <p>Thus, it can be seen that OT rate per hour has increased between 16 to 32% due to wage revision.</p> <p>(c). Apart from the above the increase in per hour OT rate during the year 2011-12 was due to VDA increase as tabulated below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Period</th><th rowspan="3">Month</th><th colspan="4">Per Hour OT Rate</th></tr> <tr> <th colspan="2">Tindal</th><th colspan="2">RP Worker</th></tr> <tr> <th>Senior</th><th>Junior</th><th>Senior</th><th>Junior</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginning of the year</td><td>Apr-11</td><td>110.25</td><td>52.68</td><td>107.25</td><td>49.61</td></tr> <tr> <td>End of the year</td><td>Mar-12</td><td>121.56</td><td>56.26</td><td>118.01</td><td>54.63</td></tr> <tr> <td>% Change</td><td></td><td>10.26</td><td>6.80</td><td>10.03</td><td>10.12</td></tr> </tbody> </table> <p>It can be seen that increase during the year</p>	Month	Demand of CHO Gangs	Supply of CHD Gangs	Deficit	April 2011	1928	1594	334	May 2011	1986	1643	343	June 2011	2031	1614	417	July 2011	2350	1668	682	Aug 2011	2350	1668	682	Sept 2011	2440	1620	820	Oct 2011	2161	1654	507	Nov 2011	2223	1611	612	Dec 2011	2467	1672	795	Jan 2012	2200	1669	531	Feb 2012	2028	1496	532	Mar 2012	1747	1544	203	Period	Month	Per Hour OT Rate				Tindal		RP Worker		Senior	Junior	Senior	Junior	After Wage Revision	Apr-11	110.25	52.68	107.25	49.61	Before Wage Revision	Feb-10	83.58	42.75	78.34	42.75	% Change		31.91	23.23	36.90	16.05	Period	Month	Per Hour OT Rate				Tindal		RP Worker		Senior	Junior	Senior	Junior	Beginning of the year	Apr-11	110.25	52.68	107.25	49.61	End of the year	Mar-12	121.56	56.26	118.01	54.63	% Change		10.26	6.80	10.03	10.12
Month	Demand of CHO Gangs	Supply of CHD Gangs	Deficit																																																																																																																			
April 2011	1928	1594	334																																																																																																																			
May 2011	1986	1643	343																																																																																																																			
June 2011	2031	1614	417																																																																																																																			
July 2011	2350	1668	682																																																																																																																			
Aug 2011	2350	1668	682																																																																																																																			
Sept 2011	2440	1620	820																																																																																																																			
Oct 2011	2161	1654	507																																																																																																																			
Nov 2011	2223	1611	612																																																																																																																			
Dec 2011	2467	1672	795																																																																																																																			
Jan 2012	2200	1669	531																																																																																																																			
Feb 2012	2028	1496	532																																																																																																																			
Mar 2012	1747	1544	203																																																																																																																			
Period	Month	Per Hour OT Rate																																																																																																																				
		Tindal		RP Worker																																																																																																																		
		Senior	Junior	Senior	Junior																																																																																																																	
After Wage Revision	Apr-11	110.25	52.68	107.25	49.61																																																																																																																	
Before Wage Revision	Feb-10	83.58	42.75	78.34	42.75																																																																																																																	
% Change		31.91	23.23	36.90	16.05																																																																																																																	
Period	Month	Per Hour OT Rate																																																																																																																				
		Tindal		RP Worker																																																																																																																		
		Senior	Junior	Senior	Junior																																																																																																																	
Beginning of the year	Apr-11	110.25	52.68	107.25	49.61																																																																																																																	
End of the year	Mar-12	121.56	56.26	118.01	54.63																																																																																																																	
% Change		10.26	6.80	10.03	10.12																																																																																																																	

	(iii) In the proposal dated 2 July 2012, the KPT had considered to spread ₹3 crores as overtime over 5 years period (i.e. annually 60 lakhs) as decided by the Board of Trustees of KPT and balance ₹3 crores was proposed to be recovered from the general revision proposal. As against that in the revised proposal of 21 February 2013, the port has considered overtime of ₹6 crores and proposed to be spread it over five years period (i.e. 120 lakhs per annum). Furnish the reasons for the modification in the overtime cost.	owing to VDA increase ranges from 7 – 10%. With regard to reasons for increase in the overtime expenditure from ₹3 crores to ₹6 crores which to be spread over a period of 5 years it is stated that in the earlier proposal only six months data was considered while in the revised proposal the data of entire 12 months was considered.
(iv)	The gratuity, commutation of pension and pension payments estimated for 2011-12 in the last Order and the actual payments indicated by KPT in the current proposal is tabulated below.	<p>(a) At the time of estimation of Pension payments number of retirees every year due to superannuation, VRS, Medical incapacitation, Deaths, etc. were not considered which is 159 Nos. in the year 2011-12 and 110 Nos. in 2012-13 respectively.</p> <p>(b) Further annual increase in pension payments were considered @ 5.8% which is very meager looking to increase in rate of VDA, which increased by 11% in 2010-11, 13% in 2011-12 and 15% in 2012-13. Restoration of commutation extension of benefits to old aged pensioners and extension of family pension to widowed, unmarried and divorced daughters were extended by Government during the year 2010-11 and benefits were extended w.e.f 01.01.2007.</p> <p>(c) It is further to add that at the time of estimation of pension payments at the time of submission of proposal, impact of recurring increase in pension payments due to pension revision was not considered.</p> <p>The actual payments does not include arrears relating to past period.</p>
(v)	The gratuity, pension and commutation of pension payments furnished by the KPT in the year 2011-12 cannot be verified with the Annual Accounts as the figures for CHD division in this regard are not reported separately in the Accounts. Please confirm that these figures indicated for the year 2011-12 are as per the details maintained by the port.	The amount of actual pension payment of CHD during 2011-12 and 2012-13 has been worked out on the basis of records identified containing PPO Nos. of Cargo Handling Division as "CHD" in the monthly pension bill.
(vi)	The basis of estimating the gratuity, pension payments and commutation pension in the years 2013-14 and 2014-15 may be indicated.	The calculation showing the Estimation of Gratuity, pension payment and commutation for the year 2013-14 and 2014-15 is furnished.

9. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) This Authority had fixed composite rate for on-board labour in lieu of levy and other charges of Cargo Handling Division (CHD) of Kandla Port Trust (KPT) vide Order dated 25 March 2011 with the validity period till 31 March 2012. At the request of the KPT, this Authority has extended the validity of the existing composite rate from time to time, the latest being till 28 February 2013 vide Order dated 17 December 2012.
- (ii)
 - (a) The earlier proposal of KPT dated 2 July 2012 was based on six months actuals of 2011-12 i.e. from 1 June 2011 to 30 November 2011. As per clause 3.1.8 of the tariff guidelines of 2005, the tariff to be prescribed by this Authority is for three years validity cycle. The port was, therefore, advised to reformulate the proposal based on realistic estimates for three years i.e. from 2012-13 to 2014-15. The KPT has, accordingly, filed the revised proposal dated 21 February 2013 updating the cost statement with actuals for 2011-12 and estimates for three years viz. 2012-13 to 2014-15 based on nine months actuals for the year 2012-13 i.e. from April 2012 to December 2012. The revised proposal filed by the KPT was taken on consultation with relevant stakeholders. The revised proposal dated 21 February 2013 along with information/ clarifications furnished by KPT during the proceedings of this case are considered in the analysis.
 - (b) The Kandla Stevedores' Association Limited (KSAL) has submitted that the revised proposal dated 21 February 2013 is not accompanied either with Board Agenda or Minutes of the Board Resolution. The revised proposal is, therefore, not approved by the Board of Trustees of the Kandla Port Trust.

In this regard, it is relevant here to mention that Clause 3.1.4 of the tariff guidelines of 2005 requires a port trust to send its proposal to this Authority with the approval of the Board of Trustees of the port. Further, the views of the Board will be considered by this Authority if received within two months of the submission of the proposal. As rightly stated by the KSAL, the board agenda or minutes on the revised proposal dated 21 February 2013 are not received. The port has submitted the minutes of the board meeting on the original proposal of June 2012. Clause 3.1.4 of the 2005 tariff guidelines does not prohibit this Authority from entertaining the proposal submitted by a port trust without the approval of its Board.

- (c) Kandla Port Karmachari Sangh (PKPS) has stated that after merger of KDLB with KPT on 24 January 2007 the process for seeking approval for supply of on-board labour was started on 18 June 2007 and the final rates were approved after 5 years i.e. on 5 May 2011. This has caused financial loss to KPT, according to PKPS because of internal exchange of clarification and piecemeal objections raised by TAMP.

In this regard, it is stated that this Authority always seeks information in a comprehensive manner. The reply to the comprehensive questionnaire issued to the KPT vide letter no. TAMP/37/2007-KPT dated 22 November 2007 was received on 6 June 2008 alongwith revised proposal. In the revised proposal, the port had proposed to recover charges for supply of on board labour on per ton basis against its earlier proposal for recovery on per worker per shift basis. Since the revised proposal of the KPT filed on 8 June 2008 substantially differed from its earlier proposal dated 18 June 2007, the revised proposal was needed to be circulated to the concerned users for their comments. The additional information/ clarification on the revised proposal sought vide our letter no.TAMP/37/2007-KPT dated 29 July 2008 was furnished by KPT on

24 September 2008. The gaps noticed in the information furnished were brought to the notice of the port on 28 November 2008 which were addressed by port on 6 March 2009. Even the action on the decisions taken at the joint hearing held on 8 April 2010 were furnished only on 11 October 2010. Considering the time taken on various fronts for the case to mature for final consideration, it is not appropriate to hold TAMP responsible for the financial loss, if any, to the KPT.

The KPKS has also contended that TAMP has approved rates for the intervening period from 2007 to 2011. The rates approved by the Authority vide Order No. TAMP/37/2007-KPT dated 25 March 2011 notified on 5 May 2011 were effective after expiry of 30 days from the date of notification.

The KPKS has stated that TAMP approved the rates for the intervening period 2007 to 2011 based on the cost prevailing in the year 2007. In this connection, it is noteworthy that the initial fixation for on-board labour after merger of KDLB with KPT was done vide Order dated 25 March 2011. Since this was initial fixation and since there was no specific rate available in the notified SOR, the KPT had proposed ad hoc rate on per worker per shift basis in line with the provisions of the clause 2.17.1. to 2.17.3. of the tariff guidelines of March 2005 based on mutual agreement with the port users. As the rates approved vide Order dated 25 March 2011 were to come into effect after a period of 30 days, this Authority accorded ex-post facto approval for the ad hoc rates proposed till the new rates came into effect.

(iii) During processing of this case, the KPT while replying to one of our queries relating to manning scale has stated that this Authority should not associate itself with the implementation of manning scale which is a policy matter and should be left to the concerned port trusts. The Kandla Port Karmachari Sangh (KPKS) has also made a remark that this Authority has nothing to do with the internal matters relating to National Agreements with the Workers Federations.

It is relevant to state here that this Authority is a corporate body mandated by Statute to regulate tariff of Major Ports of India and private terminals operating therein. As per clause 2.6.2. of the tariff guidelines of 2005, the Major Port Trusts are required to regularly review the manning scale in view of technological changes and to revise the datum and rates of piece-rate scheme from time to time in terms of the National level Wage Settlements. Implementation of manning scale/ datum has an impact on fixation of port tariff and more particularly CHD which is a labour intensive division. This Authority is bound by the tariff guidelines of March 2005, which is a policy direction of the Government issued to this Authority under Section 111 of the MPT Act, 1963. This Authority, therefore, cannot overlook the position regarding implementation of manning scale and datum.

(iv). The KPT has stated that datums were fixed in 1979 and unions oppose increase in datum. They demand increase in piece rates. The port has stated that it has given the proposal for revision of datum and it may have to be solved by consultative approach.

As regards manning scale, the KPT has informed that the first phase of manning scale has been implemented with effect from 22 April 2012. It has clarified that in view of implementation of manning scale, the gang strength has been reduced and the overtime cost has also been reduced. The KPT has confirmed that manning scale to the extent of 80% is implemented. It apprehends that full implementation of the manning scale will result in 30% to 40% of manpower rendered surplus and hence without proper planning for their re-deployment or retrenchment or retraining, 100% implementation of the manning scales may

create chaos in the port and lead to huge industrial unrest in the port sector. The port has stated that the second phase of the revised manning scale will be considered for implementation gradually taking into consideration the retirement/death of workers and ensuring that the gangs are not rendered surplus which may lead to industrial unrest.

Till a policy decision is taken in this matter, the port proposes to recover their salaries and wages from the stevedores.

It is relevant to state that the implementation of manning scale/ datum should ultimately result in reduction in the cost. The view of the KPT to recover cost of labour rendered surplus from stevedores will not serve the desired objective of implementation of the revised manning scale. Clause 2.6.1. of the tariff guidelines of 2005 allows apportionment of cost of surplus labour against non- traffic revenue sources like estate rentals/ premium, accumulated reserves, and balance over the traffic revenue. Clause 2.8.3. of the guidelines mandate the port trusts to apply revenue share receipts first to meet the cost of surplus labour, if any, and at least 50% of the balance should be transferred to the Escrow account. The KPT is advised to meet the cost of surplus labour, if any, in line with the prescription made in the tariff guidelines of March 2005 while implementing the second phase of manning scale.

Notwithstanding the above position, however, in view of the assurance given by the port that the second phase of revised manning scale will be implemented gradually after addressing the issue of surplus manpower in CHD which will involve some time and datum will be revised in consultation with union, this case is analysed to fix per tonne levy proposed by KPT based on the partially revised manning scale and the datum considered in the estimates as reported by the port. The port is advised to initiate necessary steps for full implementation of the revised manning scale and datum before the next revision and capture its effect while formulating proposal for next review of the rates for CHD.

(v). Kandla Port Stevedores Association (KPSA) and few other user associations have complained about notional booking of gangs for mechanized handling of a few cargo, mandatory booking of notional gang per hook for vessels operating at outer anchorage, etc. The port has not responded to the users comments in this regard. The port is advised to frontally address these issues raised by user associations and eliminate such practice and bring in transparency in their system of working.

KPSA has also submitted that in case of BOT operators like ABG Kandla Container Terminal Limited, RAS Infraport, gangs are not booked as port has signed concessional agreement with the respective BOT operators. They are of the view that the revenue share earned by the port from BOT operators is in lieu of engagement of labourers and wharfage charges and hence KPSA has suggested that port should consider cost of one gang per hook in each shift and debit it from revenue share receipt. The point made by the Association is not found relevant as KPT is governed by individual License Agreement entered by them with the concerned BOT operators. Moreover, BOT operators offer composite container cargo/ handling service for which tariff is determined separately based on the applicable guidelines.

(vi). Kandla Port Karmachari Sangh (KPKS) has mentioned that a loss of ₹36 crores sustained by KPT is due to change in levy from per worker per shift to per tonne basis. The KPKS has requested to revert to the earlier system of recovery of wages and percentage levy system. The point made by KPKS is mere statement and not established with any analysis.

It is noteworthy that the Ministry of Shipping vide its letter No.LB-13018/4/05-L-II dated 24 June 2009 has advised all the Major Port Trusts to adopt tonnage based charges for stevedoring operations. The proposal of KPT for commodity-wise per

tonne rate for supply of labour from CHD for stevedoring services in the last tariff order as well as the current proposal is in line with the advice rendered by the Ministry. The request of KPKS to change the basis of levy from tonnage to percentage basis is not in line with the advice of the Ministry.

- (vii) (a). Clause 2.13 of the tariff guidelines of March 2005 requires this Authority to review the actual physical and financial performance at the end of the prescribed period with reference to the projections relied upon at the time of fixing the prevailing tariff. If variation in actual performance of more than + or - 20% is observed as compared to the projections, the tariff to be approved has to be adjusted prospectively.
- (b) The composite rate for on-board labour deployed from CHD approved in the last tariff Order dated 25 March 2011 was based on the estimates for the year 2011-12. The approach followed in the last tariff Order to estimate the cost position for the year 2011-12 is adopted to analyse the actuals for the year 2011-12. The following modifications are done in the actuals furnished by the KPT for the year 2011-12:
 - (i). While presenting the actual position for the year 2011-12, the expenses viz., stores, office & administration expenses, operation and maintenance expense, medical expense, depreciation are considered by KPT as reported in the Audited Annual Accounts of KPT for the CHD and hence accepted except for a few items which are modified as explained below:

- (a). From the total actual salaries and wage cost reported at ₹5491.66 lakhs in the Annual accounts, the port has considered salaries and wages at ₹3815.91 lakhs excluding the overtime cost of ₹1675.76 lakhs incurred in the year 2011-12. In the earlier proposal dated 2 July 2012, the KPT had proposed to spread over overtime of ₹3 crores as decided by the Board of Trustees of the KPT over five years period and balance was proposed to be adjusted in the general revision of its Scale of Rates.

Subsequently, in the revised proposal of 21 February 2013, the port has considered overtime of ₹6 crores and proposed to spread it over five years period (i.e. 120 lakhs per annum). When sought reasons for increasing the overtime expenditure from ₹3 crores to ₹6 crores in the year 2011-12, the port has clarified that the earlier proposal was based on six months data only while the revised proposal of February 2013 considers the actuals for the full year.

On examining the actuals for the year 2011-12, it is seen that the total salaries and wages including overtime is ₹5491.66 lakhs which is found to be 56% higher than the salaries and wage cost estimated in the last tariff Order. The main reasons for steep increase in actual salaries and wages is attributable to increase in the overtime element. When sought reasons, the port has clarified that excess demand for CHD gangs vis-à-vis their supply, the increase in overtime cost per hour, and the effect of wage revision are the main reasons for steep increase in the overtime cost.

The port has submitted that purely to avoid huge variation in the rates, it has consciously taken a decision to spread

part of the overtime cast over a period of five years on the request made by the Trade. The Board of Trustees of the KPT was also of the view that it may not be feasible for the stevedores to pass it on to the final users, which may attract commercial consequences and lead to legal problems and moreover stevedores themselves cannot bear the huge burden and hence a conscious decision is taken to spread the overtime cost of the year 2011-12 over five years.

- (b) The two points to be decided regarding actual overtime cost of the year 2011-12 while analysing the performance are:

- (i) Of the actual overtime cost of ₹16.76 crores reported in the Annual Accounts for year 2011-12 pertaining to the CHD the KPT has considered ₹6 crores in CHD activity and balance ₹10.76 crores is proposed to be considered in the general revision proposal.
- (ii) Spreading off the overtime cost of ₹6 crores over five years period.

With reference to (i) above, it is pointed out that the proposal of KPT to consider part of overtime incurred for CHD from general revision proposal will result in flow of cross-subsidy from general revision to CHD. However, attempt of the port to consider part of the overtime cost from general revision proposal is reportedly based on demand from trade and is an attempt to reduce the impact of steep increase in the CHD rates.

It is observed that there is always flow of cross subsidy between the activities/ sub-activities. If this activity was treated as a part of general revision proposal, the flow of cross-subsidy to this activity from other activities could not have been avoided. In view of the above position, the proposal of KPT recover a part of overtime cost i.e. ₹6 crores from CHD and to consider residual overtime cost of ₹10.76 crores in its general revision proposal is allowed by this Authority.

As regard point (ii) above, it is relevant to state that during the last fixation, the overtime cost formed as one of the components of the Salaries cost. The approach adopted by KPT of spreading overtime cost over five years period is not found to be in line with the approach followed in the last tariff Order. Hence, overtime cost is considered as part of the salaries and wage cost for the year 2011-12 in our analysis in line with the approach adopted in the last tariff Order.

- (c). The KPT has considered increase in Variable Dearness Allowance (VDA) at 10% of basic pay in the year 2011-12. Since actual salaries and wages reported for CHD for the year 2011-12 is considered which must have already captured the effect of increase in VDA, consideration of the impact of increase in VDA separately for the year 2011-12 does not arise.

- (d). The port has considered the effect of wage revision w.e.f. 1 January 2012 @ 20% of salaries and wages in the year 2011-12. During the last tariff revision as recorded in para 13(xii), the effect of wage revision from 1 January 2012 was not considered. Hence, while comparing the actuals with the estimates, the impact of wage revision is not considered for like to like comparison with the estimates.
- (e). The pension payments, gratuity payments and commutation payment for the year 2011-12 at the actual level is furnished by KPT. These items relating to CHD are not reflected in the Annual Accounts of KPT separately. The port has clarified that the actual payments of pension, gratuity and commutation pension are considered based on records for CHD maintained by the port in the monthly pension bill. In the last tariff Order, this Authority had relied on the estimates furnished by KPT in this regard on similar basis. The KPT has confirmed that the actual payments do not include arrears relating to past period. Based on the clarification furnished by the port, the actual pension, gratuity payments and commutation payments for the year 2011-12 as indicated by the port is relied upon.
- (f). The capital employed i.e. net fixed assets considered by KPT in the cost statement is ₹27,541,000. This amount marginally differs from net value of assets furnished by the KPT in the statement of assets for CHD. The capital employed for the year 2011-12 is considered at ₹27,541,461 as indicated in the statement relating to assets for CHD. Consequently, the return on capital employed at 16% also stands modified.
- (g). During the last tariff revision average revenue per gang was scaled down by 5% towards cost reduction and productivity improvements. The same adjustment is considered while analysing the actuals for like to like comparison with the estimates.
- (viii). A copy of the cost statement for the year 2011-12 vis-à-vis the estimates relied in the last tariff Order is attached as Annex - I. A summary of the analysis of the actual financial performance of CHD for the year 2011-12 vis-à-vis the estimates considered in the last tariff Order is tabulated below:

Sl. No.	Particulars	Estimates considered in the last Order	(₹ in lakhs)	
			2011-12	2011-12
(i)	Total Exps (incl. Depn)	4037.78	5496.72	36%
(ii)	ROCE	45.74	42.62	-7%
(iii)	Total Revenue Requirement to meet Expense plus ROCE (i + ii)	4083.51	5539.34	36%
(iv)	Total gangs supplied (in nos.)	23843	27554	16%
(v)	Revenue expected ₹ per gang (iii/ iv)	17127	20104	17%
(vi)	5% towards cost reduction/ productivity improvement/ labour rationalisation, etc.	856	1005	17%
(vii)	Revenue expected per gang considered to fix commodity-wise per tonne rate (v-vi)	16271	19098	17%

To assess the net deficit in the CHD, the actual revenue earned by CHD in the year 2011-12 is reduced from the total actual expenses plus admissible ROCE and 5% towards cost reduction/ productivity is also considered. The net deficit in the CHD based on actuals is given below:

	(₹ in lakhs)
(i) Total Expenses Plus ROCE (from sl no (iii) in the above table)	5539.34
(ii) Actual Revenue Generated in 2011-12 (as per Annual Accounts)	4023.77
(iii) Net Deficit (ii-i)	-1515.57
(iv) Less: 5% reduction towards cost reduction/ productivity improvement/ labour rationalisation, etc. as considered in last Order	75.78
(v) Net deficit after adjustment at (iv)	-1439.79

The variation in the financial parameters considered in the estimates of last tariff Order vis-à-vis the actual parameter is analysed hereunder.

- (a) The cargo-wise levy for CHD determined in the last Order was to recover shortfall of ₹4083.51 lakhs estimated for the year 2011-12. As against that, the actual income earned by the KPT from the levy is ₹4023.77 lakhs for the corresponding period which means a drop of -1.4% from the revenue requirement estimated in the last Order.
- (b) The variation in number of gangs is 16% higher than the estimated number of gangs.
- (c) The variation in the actual capital employed and return thereon vis-à-vis the estimates considered in the last Order is -7%.
- (d) The actual revenue requirement for the year 2011-12 works out to ₹5,539.34 lakhs which is 36% higher than the estimated revenue requirement of ₹4,083.51 lakhs. This is mainly on account of steep variation observed in the overall expenses of CHD which is 36% higher than the estimated level. This variation is after excluding part of the actual overtime expense of ₹10.76 crores proposed to be covered by KPT from general revision proposal. The steep increase in the actual expenses vis-à-vis the estimated expenses is attributable to increase in the salaries and wages, pension, gratuity payments on account of wage revision of the year 2007.

As against the actual revenue requirement of ₹5,534.34 lakhs, the actual revenue earned from CHD is ₹4023.77 lakhs, resulting in deficit in CHD.

- (e) It is relevant here to state that though the variation in number of gangs and return on capital employed is less than +/- 20%, the variation in the actual overall expenses is 36% higher than the estimated level. Moreover, the revenue requirement which formed the basis for determining the rate in actual terms is found to be 36% higher than the estimated level. Since the variation in these two parameters are more than 20% prescribed in the tariff guidelines, there is a case for adjustment of the deficit in the CHD in the future tariff.

The port has claimed for set off of the entire deficit assessed by it at ₹9.17 crores for the year 2011-12 and partial recovery of overtime cost to the tune of ₹6 crores to be spread over five years period i.e. ₹1.20 crores annually aggregating to 10.37 crores in the subsequent year 2012-13 and has reckoned in while arriving at the proposed rate.

In case variation in estimates vis-à-vis actuals in physical/financial parameters is more than (+)/(-) 20%, Clause 2.13 of the tariff guidelines of 2005 allows adjustment of 50% of the deficit / surplus to be considered in future tariff and not 100% set off as claimed by the port. In accordance with the provision in the guidelines, 50% of actual deficit assessed in the CHD i.e. ₹719.90 lakhs (50% of ₹1439.79 lakhs) is considered for adjustment in the future tariff.

(a) On our advice, the port has furnished the estimates for the year 2012-13 pro-rata based on nine months actuals for the period April 2012 to December 2012 along with estimates for the years 2013-14 and 2014-15. The analysis / modifications done in the estimates furnished by the KPT for the years 2012-13 to 2014-15 are explained in the subsequent paragraphs.

The KPT has estimated 63.37 lakh tonnes of break bulk cargo and 206.34 lakhs tonnes of bulk cargo to be handled by CHD for the year 2012-13 aggregating to 266.91 lakh tonnes based on the actual traffic handled by the CHD in the nine months from April to December 2012. The traffic as estimated by the KPT for the year 2012-13 is relied upon.

For the years 2013-14 and 2014-15, the port has projected the traffic at the same level as 2012-13. The traffic of a few cargo items like thermal coal and fertilizer estimated by the KPT for the years 2013-14 and 2014-15 are found to be in line with the traffic projected by the KPT in the general revision proposal for these years. For other cargo, detailed commodity-wise detail break up is not available in the general revision proposal. It is seen that the port has not proposed any growth in the traffic of the CHD. This is found to be in line with the general revision proposal where the port has not proposed any growth in overall traffic of the port in the year 2014-15 over the traffic projections of the year 2013-14.

For the purpose of this exercise, the traffic of CHD as projected by the KPT is relied upon and considered. If any undue advantage is accrued to KPT by relying on the traffic estimated by the port, then at the time of next tariff review such undue advantage / gain will be considered for full adjustment in the next tariff revision of CHD.

The KPT has estimated salaries and wages cost for the year 2012-13 at ₹9974.20 lakhs which is based on nine months actuals for the period April 2012 to December 2012 prorated for the full year. The port has estimated the effect of wage revision at 20% of the Salaries and wage separately for the year 2012-13. For the subsequent year 2013-14, the port has considered 27% increase over the estimates of 2012-13 which includes the effect of wage revision at 20%.

For the year 2014-15, the port has escalated this cost item by 5.8% over the estimates of previous year. Apart from this, the port has also considered increase in Variable Dearness Allowance at 10% of the basic pay for each of the years 2012-13 to 2014-15 to reckon the effect of 2.5% quarterly increase in the VDA. The estimate of salaries and wage related cost estimated by the KPT is analysed and modified wherever found necessary as explained below:

- The port has estimated salaries and wages cost for the year 2012-13 prorating the nine months actual salaries and wage cost which reportedly includes overtime cost. The KPT has stated that labour is required to be booked on overtime due to demand and that minimum overtime has been considered in the proposal. It is seen that against the actual overtime of ₹16.76 crores reported in the year 2011-12, the overtime considered in the year 2012-13 based on actuals for nine months is ₹6 crores. The estimates of 2012-13 are based on actuals for nine months and hence are relied upon and considered.

- (b) Salaries and wages of the workers are due for revision w.e.f 1 January 2012. The port has considered the effect of wage revision for the financial year 2012-13 at 20% of the salaries and wages cost and shown it as a separate entry. For the years 2013-14 and 2014-15, the impact of wage revision at the stated level is included as part of salaries and wage cost by the port.

It is relevant to state here that the impact of wage revision for Class III and Class IV employees due from 1 January 2012 was considered at 15% in the general revision proposals of Mumbai Port Trust and New Mangalore Port Trust. This is also in line with wage revision impact allowed in other general revision cases of Major Port Trusts with reference to earlier wage revision of 2007.

The impact of wage revision due from 1 January 2012 is allowed at 15% of the salaries and wage cost in line with the decision taken in earlier tariff cases of Major Port Trusts. The port has not furnished breakup of Class III and Class IV employees. It has to be recognised that CHD being a labour intensive division, it may not be unreasonable to presume that the salaries and wage cost will comprise of these two categories of employees. The impact of wage revision is considered at 15% of the estimated salaries and wages cost from the year 2012-13. For the subsequent years 2013-14 and 2014-15, annual escalation of 7% is allowed in line with the annual escalation decided to be allowed by this Authority in the tariff cases to be decided in the year 2013-14.

Accordingly, the impact of wage revision for the years 2012-13 to 2013-14 is considered at ₹596.14 lakhs, ₹637.88 lakhs and ₹682.52 lakhs respectively. In the cost statement prepared by us the impact of wage revision is shown as a separate entry for each of the three years.

- (c) The cost statement filed by the KPT shows that port has escalated the salaries and wage cost by 5.8% in the years 2013-14 and 2014-15 over the estimates of the respective previous year. Apart from annual escalation of 5.8% per annum, the port has also considered increase in Variable Dearness Allowance (VDA) at 10% of the basic pay for each of the years 2012-13 to 2014-15.

The port has stated that annual escalation applicable for other cost items in tariff revision may not apply to the dock workers of the port as increase in VDA is directly based on Consumer Price Index (Industrial DA Points). The average yearly increase in VDA for the past three years is stated to be 12%. In view of this, considering the current inflationary trends and also considering quarterly increase of 2.5% in VDA, the port has sought to justify that 10% annual increase in VDA claimed by the port is perfect.

Clause 2.5.1 of the tariff guidelines of March 2005 requires the expenditure projections to be in line with the traffic projections and with reference to the Whole Sale Price Index for all commodities. It is relevant here to state that the guidelines do not prescribe any different methodology for allowing annual escalation for Cargo Handling Division at the port. The rates for Cargo Handling Division at other Major Port Trusts like Visakhapatnam Port Trust, New Mangalore Port Trust, etc. have been determined allowing the annual escalation as decided by this Authority for the tariff cases decided in the relevant year. This Authority has decided to allow maximum escalation factor of 7% for the expenditure projections in all the tariff cases to be decided in the financial year 2013-14 to factor the impact of inflation. That being so, the estimates of salaries and wages for the years 2013-14 and 2014-15 are arrived by applying annual escalation

of 7% per annum on the overall the estimates of salaries and wage cost of the respective previous years as against 5.8% annual escalation applied by the KPT.

As stated earlier, cargo handling division is a labour intensive unit and hence its cost elements are fixed in nature and not likely to vary with the traffic. In any case, the port has not projected any growth in the traffic of cargo to be handled by the CHD.

- (d) The other items of expenditure viz. stores, office & administration expenses, operation and maintenance expense, medical expense for the year 2012-13 are pro-rata estimated by the KPT based on the nine months actuals. The estimates of these expenses for the year 2012-13 are relied upon.

For the subsequent two years 2013-14 and 2014-15, the KPT has estimated these expenditure applying annual escalation of 6.5%. The annual escalation of 6.5% is perhaps based on the annual escalation adopted by this Authority for the cases decided in the year 2012-13. As stated earlier, this Authority has decided to adopt escalation factor of 7% for the expenditure projections in all tariff cases of major ports and private terminals to be decided in the year 2013-14. Accordingly, the annual escalation factor of 7% is applied for estimating each of these cost items

- (e) The port has estimated depreciation for the years 2012-13 to 2014-15 at ₹10 lakhs per annum. It is seen that the port has not proposed any additions/ deletions to the gross block relating to the CHD during this period. That being so, the depreciation for the year 2012-13 to 2014-15 is considered at the level of 2011-12 actuals (i.e.) ₹9.05.441 instead of ₹10 00,000 considered by KPT.
- (f) The port has estimated gratuity payment, pension payment and commutation of pension payment for the year 2012-13 at ₹371.47 lakhs ₹922.74 lakhs and ₹187.40 lakhs respectively. Each of the estimates are found to be 46.4% higher than the actual payments for the year 2011-12

The figures relating to pension payments, gratuity payments and commutation of pension payments are not separately indicated in the Annual Accounts for the Cargo Handling Division. The port has confirmed that actual pension payments, gratuity and commutation payment to CHD workers during the year 2012-13 is worked out on the basis of records separately maintained by the port for CHD and has also confirmed that it does not include any arrears relating to the past period. The port has stated that the estimates for the year 2012-13 are based on actual payments done in the year 2012-13 for nine months period from April to December 2012 and it has considered the impact of wage revision due from 1 January 2012 at 20%. Based on the clarification furnished by the port estimates of pension, gratuity payments and commutation of pension payments for the year 2012-13 are considered except moderating the effect of wage revision at 15% in line with the impact of wage revision shown in salaries and wages

From the data work furnished by the port, it is seen that the gratuity payments and commutation of pension payments (excluding the impact of wage revision) in the years 2013-14 and 2014-15 are estimated to reduce over the estimates of the respective previous years. However, the pension payments is estimated to escalate by 11.6% and 17.2% in the years 2013-14 and 2014-15 respectively over the estimates of the respective previous years. The port has stated that it includes VDA increase @ 3% per quarter. Apart from this, the port has also considered the effect of wage revision at 20% on each of these payments

The escalation in the estimates of pension payment applied by the KPT for the years 2013-14 and 2014-15 is beyond the admissible limit of 7%. Hence the annual escalation in the estimates of pension payment for the

years 2013-14 and 2014-15 is restricted to 7% per annum over the estimates of the respective previous years. The impact of wage revision on pension payments, gratuity payments and commutation payment is allowed at 15% from the years 2012-13 to 2014-15 in line with the impact of wage revision allowed for salaries and wages.

Since pension and gratuity payments relating to CHD are not reflected separately in the Annual Accounts of KPT, the port is advised to exclude the expenditure on these heads in its general revision proposal to avoid overlapping of expenses.

- (g) The port has considered the capital employed for CHD (i.e. the net fixed assets) at constant figure of ₹275.41 lakhs for the years 2012-13 to 2014-15 based on the actual net fixed assets reported for the year 2011-12. In our analysis, the net fixed assets for the year 2012-13 to 2014-15 are considered at ₹257.31 lakhs, ₹248.25 lakhs and ₹239.20 lakhs after excluding the annual depreciation of ₹90.54 lakhs in each of the years. The KSAL has stated that return may not be allowed on capital employed on the ground that the on board charges are collected prior to supply of labour. Clause 2.9.1. of the tariff guidelines of March 2005 entitles a Port Trust to earn return on the capital employed. This Authority has decided to allow 16% return on the capital employed in the cases to be decided in the year 2013-14. Accordingly, 16% ROCE on the modified capital employed is allowed as considered by the KPT.
- (xii) The KPT has estimated the number of gangs at 28139 for each of the years 2013-14 and 2014-15. The same is relied upon and considered for arriving at the revenue requirement per gang
- (xiii) The KPT has proposed revision in the rates of CHD with retrospective effect from 1 April 2012. KSA and other user associations have strongly objected the proposal of KPT for fixation of rates retrospectively w.e.f. 1 April 2012. They have submitted that past dues cannot be recovered from importers/exporters once a vessel completes discharge/ loading operation. At the same time trade cannot bear the burden of past differential dues as a consequence of fixation of new rates with retrospective effect.

This Authority while extending the validity of the rates of the Cargo handling division in the Order dated 9 April 2012 had held that proposal of the port for retrospective revision of tariff w.e.f. 1 April 2012 would be considered based on justifications to be furnished by the KPT during the proceedings of the case.

With reference to its proposal seeking for retrospective revision w.e.f. 1 April 2012, the KPT has submitted that the CHD division has suffered massive loss of ₹34.12 crores mainly due to huge rise in the salaries and wages of the dock workers. The port has further submitted that during fixation of per tonne rate for CHD rate in the last Order, the piece rate considered at ₹850/- and ₹1084/- were purely adhoc rates based on the working results of the erstwhile KDLB during the 9 month period from 01.04.2006 to 31.12.2006. Moreover, the KPT had not captured the effect of wage revision impact due from 1 January 2007 in the last tariff fixation of CHD. The effect of all the above factors has culminated into huge deficit in the CHD activity and CAG has made adverse remarks in this regard.

As per clause 3.2.8 of the tariff guidelines of 2005, the revised tariff to be approved by TAMP will have prospective effect. In view of constraints explained by KSA and other user association about collection of the past dues if rates are revised retrospectively and also in view of specific clause in the tariff guidelines for prospective revision in tariff, this Authority is not inclined to consider the request made by the port for retrospective revision.

However, at the same time, in view of submissions made by KPT explaining the reasons for huge deficit in the CHD, it is not found appropriate to require the port to bear the loss arising in the CHD on account of increase in the labour related cost incurred by the port in the year 2012-13 which ideally should be borne by the trade for availing services of labour from CHD. In fact even the KPT has claimed adjustment on entire deficit estimated in the year 2012-13 while arriving at the proposed rate.

In view of the position explained above, the entire deficit estimated for the year 2012-13 is considered for adjustment in the tariff to be determined as explained in the subsequent part of the analysis.

The actuals for the year 2012-13 are not available at the time of analysis of this case. The estimates furnished by the KPT are considered subject to certain modifications as explained in the previous part of this analysis. Since the analysis for the year 2012-13 is done based on the estimates, the actual position shall be subject to review during the next revision exercise. If the variation is found to be more than the level prescribed in the tariff guidelines, it shall be adjusted in the next tariff validity cycle as per clause 2.13 of the tariff guidelines.

(xiv) (a). This Authority vide its Order No.TAMP/37/2007-KPT dated 9 April 2012 has extended the validity of the rates for on-board labour beyond 31 March 2012 upto 30 June 2012 and the last extension was granted till 28 February 2013 subject to the condition that the additional surplus, if any, that may accrue to KPT during the extended period of validity will be adjusted fully in the tariff to be fixed.

(b) The port has estimated the total cost plus return for the year 2012-13 excluding the past period deficit of 2011-12 at ₹6,486.07 lakhs. After considering the estimated revenue from CHD at ₹5,380.53 lakhs based on the actuals for the nine months, the port has estimated net deficit for the year 2012-13 at ₹1105.55 lakhs.

The KPT has sought adjustment of entire deficit of ₹1105.55 lakhs estimated for the year 2012-13 and second instalment of spread over of the overtime expense at ₹120 lakhs aggregating to ₹1225.54 lakhs in the year 2013-14. In the year 2014-15, the port has considered the adjustment of ₹120 lakhs towards spread over of the overtime pertaining to the year 2011-12. The treatment of overtime relating to the year 2011-12 is explained in the analysis contained in earlier paragraphs and the adjustment of the deficit for the years 2011-12 and 2012-13 is tabulated and explained in subsequent part of this analysis.

(c) The cost statement for the CHD drawn by us subject to the modifications explained in the preceding part of the analysis, depicts the total cost plus ROCE at ₹6,088.75 lakhs for the year 2012-13. After reckoning the revenue estimated by the KPT for the year 2012-13 at ₹5,380.53 lakhs, the cost statement reflects a net deficit of ₹708.22 for the year 2012-13.

(d) In the last tariff Order, 5% reduction was effected in the revenue requirement towards productivity improvement/ labour rationalisation. Keeping in view that the manning scale is still not fully implemented and notional gang booking continues in the port, etc., to factor these issues 5% reduction in the estimated revenue requirement is effected in the years 2012-13 to 2014-15 towards productivity improvement/ labour rationalisation and cost reduction. Such reduction of 5% was also considered in the last tariff Order, as brought out earlier.

(e). Actual net deficit for the year 2012-13 after adjustment of 5% comes to ₹672.80 lakhs

For reasons explained in the earlier part of the analysis, the entire deficit estimated for the year 2012-13 is considered for adjustment in the tariff to be determined.

(f) To summarise, the deficit for CHD for the years 2011-12 and 2012-13 considered for adjustment in the future tariff is given below:

		(₹ in lakhs)
50% of the Actual Net deficit assessed for the year 2011-12 (₹1439.79 lakhs * 50%)		719.90
100% of the deficit estimated for the year 2012-13		672.80
Total deficit assessed for adjustment in tariff		1392.70

The cost position considered for fixation of levy in this tariff cycle is for two years i.e. 2013-14 and 2014-15. Considering that this Order will come into effect by October 2013, the revised tariff effectively will be for truncated period of eighteen months i.e. from October 2013 to March 2015 as against the usual tariff cycle of three years.

It is relevant here to mention that in order to smoothen the fluctuation in tariff and to avoid artificially bringing down the tariff in one cycle, this Authority in the cases of other Major port Trusts and Private terminals where the surplus assessed was substantial has decided to adjust past surplus over period of five years.

In the instant case, in order to smoothen the impact of steep increase in tariff and to avoid sudden fluctuation in tariff between two cycles, the deficit assessed in the years 2011-12 and 2012-13 at ₹1392.70 lakhs is adjusted over normal tariff validity cycle of three years period instead of restricting it to the current tariff cycle which is for truncated period of eighteen months from October 2013.

Accordingly, ₹696.35 lakhs is adjusted over eighteen months i.e. from October 2013 to 31 March 2015 in this tariff cycle and the residual deficit of ₹696.35 lakhs will spill over for adjustment in the first eighteen months of the next tariff cycle.

- (xv). The cost statement of the CHD filed by the KPT has been modified in line with the above analysis. The cost statement of the Cargo Handling Division is attached as **Annex - II**. A summary of the revenue requirement estimated for the years 2013-14 and 2014-15 in the modified cost statement is given below:

Sr. No	Particulars	2013-14 (Estimates)	2014-15 (Estimates)	(₹ in lakhs)
(i)	Total estimated expenses	6,583.26	7,152.03	
(ii)	16% ROCE	39.72	38.27	
(iii)	Revenue requirement (i+ii)	6,622.98	7,190.30	
(iv)	Less 5% adjusted towards cost reduction/ productivity improvement	331.14	359.51	
(v)	Add: Adjustment of past deficit for the years 2011-12 and 2012-13 in the year 2013-14 (6 months) from October 2013 onwards and 2014-15	232.11	464.23	
(vi)	Estimated Revenue requirement (iii-iv+v)	6,523.95	7,295.02	
(vii)	Total gangs supplied (nos.)	28,139	28,139	
(viii)	Revenue requirement per gang (₹/ gang)	23.185	25.925	
(ix)	Average Revenue requirement (₹/ gang)	24.555		

- (xvi). (a). The port has estimated annual revenue requirement per gang at ₹26,735 for the year 2012-13, ₹28,506 for the year 2013-14 and ₹25,995 for the year 2014-15 averaging to ₹27,079 per gang. In our analysis, since the year 2012-13 is already over, the average revenue requirement estimated for the years 2013-14 and 2014-15 at ₹24,555 per gang is considered to arrive at cargo wise per tonne rate.
- (b). The KPT has furnished detailed working for arriving at commodity-wise rate to meet the estimated revenue requirement per gang. The methodology adopted by the KPT for arriving at commodity-wise per tonne rate is followed while arriving at the revised rate based on the revised estimated revenue requirement.

The port has presumed 90% of cargo volume as foreign and 10% cargo as coastal for arriving at the per tonne rate except for thermal coal and

iron ore where it has projected the entire cargo to be foreign. The cargo and its share as presumed by the KPT is relied upon.

- (c) The rate proposed by the KPT for iron ore and thermal coal at ₹22.59 and ₹7.33 respectively do not match with its calculation. The revenue generation at the proposed rate for these two cargo items works out to be higher than the revenue requirement estimated from these cargo category by the port. There seems to be some anomaly in the calculation of port which is corrected in our working. In our working, the rate is arrived so as to match the modified revenue requirement estimated for the cargo items. The working sheet for arriving at per tonne rate for bulk cargo and break bulk cargo is attached as Annex - III (a) and (b) respectively
 - (d). The last tariff Order prescribed per tonne rate for soda ash cement oil extractions (break bulk) among other cargo items. In the initial proposal of KPT dated 2 July 2012, the port had not proposed rate for these three cargo items. On a query raised in this regard, port has clarified that soda ash is no longer being handled at KPT and the chances of these cargoes being handled also appear to be very remote. Hence, no rate is proposed. In view of clarification furnished by the KPT, the tariff item relating to soda ash is deleted from the schedule of rates for CHD.
- In the revised proposal dated 21 February 2013, the KPT has proposed to include rate for cement and oil extractions (break bulk) and has included the traffic projected from these cargo items in its working. The revised proposal was taken on consultation with users and there has not been any adverse comments from any user in this regard. Accordingly, cement and oil extractions (break bulk) are considered in our working for arriving at per tonne rate in line with the revised proposal filed by KPT.
- (e). In the revised proposal dated 21 February 2013, the KPT has included traffic of granite and marble and proposed to introduce rate for this cargo as well. The revised proposal was taken on consultation with users and there has been no adverse comments from users in this regard. Accordingly, traffic and shift output estimated by the KPT for this cargo relied upon and considered in our working for arriving at the rate for granite and marble.
 - (xvii). In the initial proposal, the KPT has proposed to revise the per tonne rates for supply of on-board labour on a quarterly basis to capture the change in the rate of Variable Dearness Allowance (VDA). The port has proposed to modify the per tonne rates suo motu every quarter to reflect the change in the VDA and subsequently obtain the ratification of this Authority therefor. The KPT has in the revised proposal of February 2013 requested to allow fixed percentage increase on a cumulative basis on the per tonne rate at the beginning of each year during the three year tariff validity cycle instead of quarterly increase sought in the earlier proposal to capture the effect of increase in VDA. Clause 3.1.8 of the tariff guidelines of 2005 stipulates that tariff once fixed shall be in force for three years. That being so, the proposal of KPT for increasing the rates quarterly/yearly (cumulative basis) is not found to be in line with the provision in the tariff guidelines of 2005 and hence not accepted. As regards the contention of KPT about quarterly increase in VDA, it is to be noted that the tariff determined is based on the average revenue requirement estimated for the years 2013-14 and 2014-15. The estimation of revenue requirement factors in annual escalation of 7% to meet the inflation cost in all items including VDA which is a component of salary and wages.
 - (xviii). The validity of the rates for CHD extended in the last tariff Order dated 17 December 2012 had expired on 28 February 2013. The port has continued to levy the rates approved vide earlier Order dated 25 March 2011. The validity of the existing rates is deemed to have been extended from 1 March 2013 onwards till the effective date of implementation of revised rate approved in this Order.

The tariff guidelines of 2005 stipulate a tariff validity cycle of 3 years. Since the cost position considered for fixation of rate for CHD is for two years i.e. 2013-14

and 2014-15, the tariff prescribed will be for a truncated period of eighteen months. The financial position considered for the purpose of this analysis is only till 31 March 2015, hence the validity of the revised rates will also expire on 31 March 2015.

(xix). The KPT was advised to examine the suggestion made by Kandla Ports Stevedores Association to include on-board labour charge of CHD in the wharfage. The KPT in this regard has clarified that stevedoring charges invariably forms part of the ocean freight and are usually paid by vessel agents to stevedores whereas wharfage charges are reimbursed by the exporter/ importer to the Custom House Agents. Moreover, it has brought out other practical difficulties like requirement of separate bills/ receipts by importers for wharfage & on-board labour charges for claiming duty, bringing uniformity in classification of commodities for wharfage and on board stevedoring, etc. In view of practical difficulties expressed by KPT in merging the two components, the existing system of separate levy for deployment of on board labour from CHD is allowed to continue for the present. The port is advised to examine the possibility of merging on-board labour charges with wharfage at the time of filing the next review in consultation with the trade, as agreed by the port.

(xx). The port has expressed difficulties in proposing productivity linked rates citing that there are fifty different types of dry cargoes handled at Kandla each having different productivity levels and grouping these cargo items is a tedious process. The KPT is of view that prescribing productivity linked rates for each cargo type will complicate the realization of charges from port users.

The port has not proposed productivity linked rate, but, has mentioned that this point is taken care in its proposal. The port has stated that if the actual revenue per gang is more than the maximum revenue requirement expected per gang, the surplus will be refunded by the port to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedores. The port opines that this methodology will recognize productivity instantly and is very easy to implement and is understood by the stevedores and operating staff.

The port has, however, not incorporated a suitable condition to operationalise this proposition in the Schedule relating to CHD. The said proposition of the KPT does not appear to be very scientific and well examined proposal. The productivity factor depends upon several factors like availability of grabs with the vessels, the lifting capacity of the grabs, failure of the grabs, failure of other equipment like crane, unfavourable climatic condition, insufficient cargo, appropriate yard and hatch planning etc. The KPT has not considered these factors relevant for achieving productivity while proposing to refund / collect from stevedores for excess / short recovery from the expected revenue requirement per gang. The KPT is, therefore, again advised to file a well analysed proposal taking into consideration the above factors and propose productivity linked rates to act as an incentive to the stevedores to achieve better productivity and reduce the overall cost of operation at the time of next revision of rates for CHD. Till such time, the productivity linked proposal of KPT is incorporated as a conditionality in the schedule.

11.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves and incorporates the revised composite rate for on-board labour of Cargo Handling Division of KPT attached as Annex - IV at Clause 3 in Chapter III of the Scale of Rates of the KPT.

11.2. The revised composite on-board charges for CHD will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification in the Gazette of India and shall remain in force till 31 March 2015. The approval accorded thereto will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

11.3. This Authority has relied upon the estimates for the years 2012-13 to 2014-15. Additional surplus, if any, arising due to variation in actual performance in the said years will be governed by the provisions of Clause 2.13 of the tariff guidelines of 2005 in the next review, unless a different method of treatment of any of the specific items is indicated in the analysis above.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

Annex - I

Comparision of Actuals vis-à-vis Estimates of 2011-12 for Cargo Handling Division of the Kandla Port Trust

Sl. No.	Particulars	Estimates in TAMP Order dated 25.3.2011	Actuals for 2011-12	(Amt. in Rupees)	
				Variation in % over the moderated figures	
1	TOTAL EXPENSES				
(i)	Salary & Wages (including overtime of Rs 16.76 cores)	353.124.503	549.166.577	56%	
	<u>Less:</u> Overtime of Rs 10.76 cores to be adjusted in the general revision proposal as proposed by the KPT	107.576.011	---		
Total	Salaries and Wages considered for assessing actual cost position for 2011-12				
(ii)	Stores	441.590.566	441.590.566	25%	
(iii)	Office & Administration Exp	2,441	697.718		
(iv)	Operation & Maintenance Exp	128.310	282.268		
(v)	Medical Exp	96.737	86.418		
(vi)	Depreciation	3.325.314	4.910.008		
(vii)	Gratuity	988.412	905.441		
(viii)	Commutation of Pension	5.310.715	25.372.723		
(ix)	Pension	1,506.465	12.799.998		
TOTAL		39,293,053	63,027,279		
2	Capital Employed	403,775,950	549,672,419	36%	
3	Return on Capital Employed	28,590,658	27,541,461		
4	Revenue Requirement (1 + 3)	4,574,505	4,261,763	-7%	
5	Total Gangs Supplied	408,350,455	553,934,182	36%	
6	Actual Revenue expected per Gang (4 / 5)	23,843	27,554	16%	
7	5% Reduction on account of cost reduction / productivity	17,127	20,104	17%	
8	Actual Revenue expected per Gang after 5% reduction as above. (6 - 7)	856	1,005		
		16,271	19,098	17%	
A. Summary of Actuals for the year 2011-12					
(i)	Actual Total Expenses for 2011-12	553,934,182			
(ii)	Actual Revenue Generated in 2011-12 as per Annual Accounts	402,377,241			
(iii)	Expenditure in Excess of Revenue	151,556,941			
(iv)	Adjustment of 5% towards cost reduction/productivity improvements, etc as considered in last order	7,577,847			
(v)	Actual Loss after above adjustment	143,979,094			
(vi)	50% of the above loss (sr. no. v) to be adjusted from 01.10.2013 to 30.9.2016 i.e in 36 months.	71,989,547			

Cost Statement of Cargo Handling Division of the Kandla Port Trust

ANNEX - II

पर्याय ४।

भारत का राजपत्र : असाधारण

65

Sl. No.	Particulars	Actuals 2011-12 from Annex - I	Estimates as furnished by KPT			Estimated Modified by TAMP
			2012-13	2013-14	2014-15	
1 TOTAL EXPENSES						
(i) Salary & Wages (Estimates of KPT for 2012-13 includes impact of wage revision in TAMP's statement wage revision considered at Sl. no (xii))	441590566	397427867	504923894	534185754	397427867	475247918
(ii) Stores	697718	813795	86368132	9230262568	813795	870761
(iii) Office & Administration Exp	282268	139964	4906165	1587506679	139964	149761
(iv) Operation & Maintenance Exp	86418	6483	590404	73528026	6483	6937
(v) Medical Exp	4910008	3862149	4113189.04	4380546328	3862149	4132499
(vi) Depreciation	905441	100000	100000	100000	905441	905441
(vii) Gratuity (including wage revision considered at 15% of actuals of 2012-13)	25372723	37146748	29002949	24648265	35598966	27794493
(viii) Commutation of Pension (including wage revision considered at 15% of actuals of 2012-13)	12798998	18739742	18164993	14839349	17959292	17593785
(ix) Pension (including wage revision considered at 15% of actuals of 2012-13)	63027279	92274622	103033944	120798344	68423846	94619935
(x) SUB - TOTAL	549672419	550511370	6614601976	700942888	545147411	571327330
(xi) Add: VDA Increase Expected @ 10% of Basic Pay per annum (Considering 2.5% per qtr)	0	1333933	3753512	14114143	0	0
(xii) Impact of wage revision for the year 2012-13 considered by KPT at 20% of Salaries & wages in TAMP's statement wage revision is considered at 15% of salaries & wages from 2012-13 to 2014-15	0	79485573	0	0	59614180	63787173
(xiii) Excess of Expenditure over income during the year 2011-12 (excluding OT) ₹91701747 + OT amount spread for 5 years as decided by Board i.e. ₹3 crore 12/- 5)=₹12000000 Adjustment of past loss of 2011-12 considered by TAMP as at Sr. No. 9 & 10	0	103701738	12255451	12000000	0	0
(xiv). TOTAL	549672419	747902614	797718579	727057031	604757611	658326284
2 CAPITAL EMPLOYED	27541461	27541000	27541000	27541000	25730379	24325138
3 RETURN ON CAPITAL EMPLOYED	4261763	4406560	4406560	4406560	4116893	3970222
4 REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR (1 + 3)	563,934,182	752309174	802125139	731463591	608874504	662298306
5 REVENUE REALISED DURING 2011-12 and 2012-13	402,377,241	538052885	0	0	538052885	0
6 Deficit estimated for the years 2011-12 and 2012-13	151,556,941	110534551	0	0	70821619	0
7 Less: Effect of adjustment of 5% towards cost reduction/ productivity improvements, etc. as considered in last order	7,577,847	0	0	0	3541081	33114915
8 Deficit for the year 2011-12 and 2012-13 after considering effect of 5% reduction as considered in last order	143,979,094	0	0	0	67280538	0
9 Quantum of Past Period Loss considered for adjustment:	0	0	0	0	0	0
10 50% of Actual Deficit of ₹143979094/- for the year 2011-12 Plus 100% of deficit estimated for the year 2012-13 of ₹67280538/-	0	752309174	802125139	731463591	0	652395071
11 Set off of past period loss over 3 year period from 01/10/2013 to 31/3/2015 (current tariff cycle) and the remaining to be adjusted in the next tariff cycle upto 30/9/2016	27554	28139	28139	28139	28139	28139
12 Total Revenue to be recovered [4 - 7 + 11]	19098	26735	28566	25995	0	23185
13 Total Gangs Supplied						25925
14 Revenue expected per Gang (9/10)						24555
15 Average Revenue Expected from per gang per commodity per tonne						
						27079

COMMODITY WISE PER TONNE RATE FOR BULK CARGO FOR ON-BOARD LABOUR OF CARGO HANDLING DIVISION**ANNEX - III (a)**

Sr. No.	Particulars	No. of gangs	Average Revenue Requirement per gang (₹)	Quantity handled (MT)	Gang Shift Output (MT)	Rate per MT (₹)	Foreign Traffic (90%)	Coastal Traffic (10%)	Revenue requirement (₹)	Proportionate Foreign Traffic	Rate for Foreign cargo (₹)	Rate for Coastal cargo (₹)
(i).	Fertiliser/ Fertiliser Raw Material	4273	24555	4947647	1158	21.21	4452882	494765	104922817	4749741	22.09	13.25
(ii).	Rice and other foodgrains	2429	24555	1686309	694	35.37	1517678	168631	59643698	1618957	36.84	22.10
(iii)	Iron ore	621	24555	1000000	1610	15.25	1000000	0	15248554	1000000	15.25	15.25
(iv).	Ores other than iron ore	661	24555	839067	1269	19.34	755160	83907	16230747	805504	20.15	12.09
(v).	Scrap	77	24555	48000	623	39.39	43200	4800	1890722	46080	41.03	24.62
(vi).	Oil Extractions	2531	24555	2522039	996	24.64	2269835	252204	62148292	2421157	25.67	15.40
(vii).	Thermal Coal	1808	24555	3863787	2137	11.49	3863787	0	44395145	3863787	11.49	11.49
(viii).	Other Coal	140	24555	325000	2321	10.58	292500	32500	3437677	312000	11.02	6.61
(ix).	Salt	2032	24555	3403000	1675	14.66	3062700	340300	49295428	3265880	15.27	9.16
(x).	Sugar	589	24555	590000	1002	24.51	531000	59000	14562799	565400	25.53	15.32
(xi).	All other unspecified goods	693	24555	1329536	1919	12.80	1196582	132954	17016502	1276355	13.33	8.00

ANNEX - III (b)**COMMODITY WISE PER TONNE RATE FOR BREAK BULK CARGO FOR ON-BOARD LABOUR OF CARGO HANDLING DIVISION AT KANDLA PORT TRUST**

Sr. No.	Particulars	No. of gangs	Revenue Requirement per gang (₹)	Quantity handled (MT)	Gang Shift Output (MT)	Rate per MT	Foreign Traffic (90%)	Coastal Traffic (10%)	Revenue Requirement (₹)	Proportionate Foreign Traffic	Rate for Foreign cargo (₹)	Rate for Coastal cargo (₹)
(i).	Fertiliser/ Fertiliser Raw Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii).	Rice and other foodgrains	2868	24555	1232691	430	57	1109422	123269	70423272	1183383.36	59.51	35.71
(iii).	Cement	69	24555	15000	217	113	13500	1500	1684284	14400	117.66	70.60
(iv).	Steel Coils and Steel pipes	1278	24555	1032886	808	30	928597	103289	31381081	991570.56	31.65	18.99
(v).	Timber and other logs	5392	24555	2862523	531	46	2576271	286252	132399680	2748022.08	48.18	28.91
(vi).	Salt	161	24555	127969	795	31	115172	12797	3953329	122850.24	32.18	19.31
(vii).	Sugar	1600	24555	610000	381	64	549000	61000	39287739	585600	67.09	40.25
(viii).	Granites and Marbles	569	24555	316000	555	44	284400	31600	13971702	303360	46.06	27.63
(ix).	Machinery Packages and other packages	17	24555	14796	870	28	13316	1480	417432	14204.16	23.39	17.63
(x).	Oil Extraction	39	24555	27492	705	35	24743	2749	357639	26392.32	36.28	21.77
(xi).	All other unspecified goods	292	24555	38000	336	73	88200	9800	7170012	94080	76.21	45.73

Insert the following schedule in Chapter - III of the Scale of Rates of Kandla Port Trust

**CLAUSE 3 - CHARGES FOR COMPOSITE RATE FOR ON-BOARD LABOUR OF CARGO
HANDLING DIVISION AT KANDLA PORT TRUST**

Sr. No	Cargo Items	Bulk		Break Bulk		(Rate in ₹ Per MT)
		Foreign ₹	Coastal ₹	Foreign ₹	Coastal ₹	
1	Fertiliser/ Fertiliser Raw Material	22.09	13.25	-	-	-
2	Rice and other foodgrains	36.84	22.10	59.51	35.71	-
3	Cement	-	-	117.66	70.60	-
4	Steel Coils and Steel pipes	-	-	31.65	18.99	-
5	Timber and other logs	-	-	48.18	28.91	-
6	Machinery Packages and other packages	-	-	29.39	17.63	-
7	Iron ore	15.25	15.25	-	-	-
8	Ores other than iron ore	20.15	12.09	-	-	-
9	Scraps	41.03	24.62	-	-	-
10	Oil Extractions	25.67	15.40	36.28	21.77	-
11	Thermal Coal	11.49	11.49	-	-	-
12	Other Coal	11.02	6.61	-	-	-
13	Salt	15.27	9.16	32.18	19.31	-
14	Sugar	25.53	15.32	67.09	40.25	-
15	Granites and Marbles	-	-	46.06	27.63	-
16	All other unspecified goods	13.33	8.00	76.21	45.73	-

NOTE:

The revenue for actual quantity handled by a stevedore to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. ₹24,555/-, the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedore.